नंदीग्राम में मार्क्सवादियों का हिंसाचार

नंदीग्राम में मार्क्सवादियों का हिंसाचार

चीत्कार उठी मानवता

सम्पादक
प्रभात झा

सह-सम्पादक
के.के. शर्मा
संजीव सिन्हा

कला सम्पादक
धर्मेन्द्र कौशल

◆ **प्रकाशित लेखों में लेखकों के निजी विचार हैं।**

नवम्बर **2007** ई. (विक्रम संवत **2064**)

मूल्य : 15/- रुपए

मुद्रक :
एक्सेलप्रिंट
सी-**36**, फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लैक्स
झण्डेवालान, नई दिल्ली-**110055**

प्रकाशक :
भारतीय जनता पार्टी
11-अशोक रोड
नई दिल्ली-**110001**
फोन नं. : **011-23382234**
ई-मेल : bjpco@vsnl.com

सम्पादक की ओर से...

नंदीग्राम पर जितने शब्द लिखे गए, लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे वे सभी माकपाइयों के कुकर्मों के लिए बहुत कम कहे जाएंगे। अब तक जितना लिखा गया उसे पढ़ने के बाद तो बुद्धदेव की बुद्धि खुल जानी चाहिए थी और उसे इस्तीफा देकर सार्वजनिक तौर पर अपने को कानूनी कटघरे में प्रस्तुत कर देना चाहिए था। माकपा के महासचिव प्रकाश करात को चाहिए था कि वे दल के हित में और भविष्य के लिए कम से कम बुद्धदेव भट्टाचार्य का इस्तीफा मांग लेते। पर, वाह री माकपा! छोटे मियां तो छोटे मियां बड़े मियां सुभान अल्लाह! एक व्यक्ति किसी लड़के की शिकायत करने उसके पिता के पास पहुंचा कि आपका बेटा चाहे जहां पेशाब कर देता है। थोड़ी देर बाद देखा कि उस लड़के का पिता बेटे को समझाने के बाद खुद ही घूम-घूम कर पेशाब कर रहा था। वाह रे कारत, वाह रे येचुरी! पूरी दुनिया एक स्वर से माकपा पर थू-थू कर रही है और जिन्होंने माकपा के लिए गाकर, नाचकर, चित्र बनाकर, कहानी और कविता लिखकर 'लाल सलाम-लाल सलाम' किया, आज वे स्वयं अपना सिर पकड़कर पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगता है हमने तो सांप को दूध पिलाया था, क्योंकि नंदीग्राम में जो कुछ हुआ कम-से-कम वे तो नहीं कर सकते थे जिनमें आदमियत होती है। दरिन्दे भी ऐसा नहीं करते जैसा नंदीग्राम में माकपाइयों ने किया। माकपा कहती थी कि वह दरिद्रों के उत्थान का काम करेगी पर क्या पता था कि उसके भीतर ही दरिंदगी मौजूद थी।

चैनलों पर चमकने वाली वृंदा कारत, सुहासिनी अली, सरला माहेश्वरी तीन राजनायिकाएं पता नहीं कहां चली गई? नंदीग्राम में जबरिया बलात्कार से चीत्कार भरती नन्हीं-नन्हीं बच्चियों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंची। मानवाधिकार की आड़ में वर्षों तक रोटी सेंकने में माहिर तीस्ता सीतलवाड़, पति-पत्नी शबाना आजमी-जावेद अख्तर पता नहीं कहां खो गए? जावेद अख्तर की गजलें पता नहीं क्यों चुप हो गई? माकपा के गुनाहों पर जावेद द्वारा गजलों का न गुनगुनाना भी उन्हें गुनाहगारों की कतार में खड़ा करता है। लाशों की ढेर पर राजनीति करनेवाले, गुजरात की आड़ में पांच वर्षों से वामपंथियों द्वारा राजनीतिक बाजार चलाने वालों के कदम नंदीग्राम में क्यों नहीं पहुंच पाए?

माकपाई इतने निर्लज्ज हो गए कि जिस हंसिया-हथौड़ा से उन्होंने जनसमर्थन मांगे थे उसी हंसिया-हथौड़ा से जनसंहार करने लगे। नंदीग्राम में वामपंथी तो नंगे हुए पर कांग्रेसियों की भी कलई खुल गई। कुर्सी बचाने के लिए नंदीग्राम में नरसंहार, बलात्कार, लूट-पाट करनेवालों का सहारा लेना और उन्हें बचाना लोकतंत्र में बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी

गत कुछ वर्षों में प्रोपगंडा के लिए अनेक बार राजनीति की नौटंकी करती रही है। पर पता नहीं आज वह वामपंथियों के हंसिया-हथौड़े से क्यों भयभीत हैं? घटना हुई, दो चार मरे और सोनिया पहुंची। पर पता नहीं क्यों नंदीग्राम के कोहराम के स्वर सोनिया के कानों तक नहीं पहुंची? कैसी निर्दयी हैं? क्या वे कुमारियों के भंग हुए कौमार्य की चीत्कार से भी पसीज नहीं पाई?

नंदीग्राम की घटना राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। भारत का यह पहला राज्य है जहां हाईकोर्ट के जज, राज्यपाल, बुद्धिजीवी सबकी दुत्कार सुनी वामपंथी सरकार ने। वामपंथियों की भाषा देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वृंदा कारत पार्टी महिला कैडर को हिंसाचार के लिए आह्वान करती है। पार्टी के राज्य नेता कहते हैं कि मेधा नंदीग्राम आई तो उसे 'पिछवाड़ा' दिखाएंगे।' येचुरी नंदीग्राम को 'जस्टीफाई' करने में जुटे है।

मर्यादाएं टूट गई। लाज लजाने लगी। धैर्य टूट गया। संविधान शरमा गया। शासन-प्रशासन कातिल बन गया। न्यायधीश, राज्यपाल, मानवाधिकार कार्यकर्ता चिल्लाते रहे। मौत का तांडव होता रहा। माकपाइयों ने जिनसे वोट लिया था उन्हीं की अस्मिता-आबरू से खेलते रहे। बुद्धदेव नीरो हैं। बुद्धदेव हिटलर हैं। बुद्धदेव स्टालिन हैं। बुद्धदेव नादिरशाह हैं। बुद्धदेव फासिस्ट हैं। इतिहास गवाह है कि हर आततायी का अंत हुआ है। वैसे तो हर नागरिक के अंतसमन से माकपाई उतर गए हैं, बस यह तो समय तय करेगा कि पश्चिम बंगाल का जनमानस अपने वोटों की ताकत से ऐसे माकपाइयों को कब उतारती है।

हमने माकपाइयों के इस घृणित कृत्य को लिपिबद्ध करने का प्रयास इसलिए किया है कि जन-जन में नंदीग्राम का दर्द पहुंचे और लोग यह समझे कि जब पहरेदार कातिल बनता है तो किस तरह का कोहराम मचता है। भविष्य में जनतंत्र का जनाजा न निकले इसलिए इस पुस्तक में तमाम प्रख्यात लेखकों के लेख, समाचार पत्रों की संपादकीय प्रस्तुत कर रहे है। इसके साथ-साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में और राज्यसभा में भाजपा की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने नंदीग्राम का जो सच देश को बताया, हम उसे यहां जनजागरण अभियान के तहत प्रकाशित कर रहे हैं।

हमें आशा है कि कम-से-कम आनेवाले समय में शेर की खाल में छिपे भेड़िये की पोल जरूर खुलेगी और साथ ही माक्सर्ववादियों का असली चेहरा। यह प्रयास शीघ्रता में हुआ है, अतः हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो, उसे समय की मांग समझकर आप भावात्मक रूप से लेंगे।

प्रभात झा

राष्ट्रीय सचिव, भाजपा

नंदीग्राम में मार्क्सवादियों का हिंसाचार

चीत्कार उठी मानवता

&vlhe dekj fe=

एक बार फिर खून से होली खेली जा रही है प. बंगाल में। स्थान वही पुराना–नंदीग्राम और रक्तपात मचाने वाले हैं वही मार्क्सवादी। गत १४ मार्च को मेदिनीपुर जिलान्तर्गत नंदीग्राम में निरपराध गांववालों पर गोली चलाकर १४ लोगों (यह आंकड़ा सरकारी है, गैर सरकारी आंकड़ा तो इससे कई गुणा अधिक है) को मौत के घाट उतार दिया गया था। फिर भी अपने 'लक्ष्य' को हासिल करने में सरकार सफल नहीं हुई थी– यानी उद्योग के नाम पर सरकार कृषि–जमीन को हड़पने में सफल नहीं हुई थी। गत ३० सालों से एक प्रकार से विरोधहीन राजनीतिक माहौल में इस राज्य में माकपा का राज चलता आ रहा है। साथ में कुछ और वामपंथी दलों (जैसे भाकपा, फारवर्ड ब्लाक, रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी आदि) के साथ वाममोर्चा चला रही है यह हिंसक सरकार। गत मार्च में

क्या है मुद्दा

- पिछले साल इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ प. बंगाल सरकार ने समझौता किया था। इसके तहत नंदीग्राम में एसईजेड पर केमिकल हब का निर्माण किया जाना था। इसके लिए 14 हजार एकड़ से अधिक जमीन की जरूरत थी।
- सलेम ग्रुप परियोजनाओं के लिए 35 हजार एकड़ भूम चाहता है। एसईजेड के अलावा उसे 100 किमी लंबे ईस्टर्न लिंक एक्सप्रेसवे और हल्दी नदी पर हल्दिया व नंदीग्राम के बीच एक पुल बनाने की जिम्मेदारी थी।
- नंदीग्राम की जमीन से 40 हजार लोगों की जीविका प्रभावित होती लेकिन सरकार का मानना था कि परियोजना से रोजगार बढ़ेंगे व यह पूर्व में स्थापित हल्दिया प्रोजेक्ट का पूरक होगा।
- नंदीग्राम प्रकरण में दो पक्ष हैं राज्य और जनता।

'गणहत्या' करते हुए भी जब माकपा नंदीग्राम के अन्दर घुस नहीं पायी तो इसके अभिमान को शायद ठेस पहुंची थी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पायी थी। उसी का नतीजा है कि इन मार्क्सवादियों ने गत दिनों फिर से नंदीग्राम पर हमला बोल दिया। सरकारी कथन के अनुसार इस बार केवल ४ ही व्यक्ति मरे हैं। परन्तु गैर सरकारी सूत्रों ने यह संख्या २० बताई है।

माकपा के इस बर्बर तथा भयानक आक्रमण को देखते हुए सम्पूर्ण समाज में जो प्रतिक्रिया हुई वह असाधारण है। गत मार्च के हमले के बाद हिंसा का इस तरह स्वतःस्फूर्त प्रतिवाद अब तक नहीं हुआ था।

...उधर मासूम किसान–मजदूर मार्क्सवादी हत्यारों की गोलियों का शिकार होते रहे ... और इधर बुद्धदेव कोलकाता में फिल्मोत्सव का आनन्द लूटते रहे।

बंगाल में विशिष्ट वर्ग के लोग आम जनता के सुख–दुख में बहुत ही कम भाग लेते थे। परन्तु इस बार नन्दीग्राम में जो कुछ हुआ उसके विरोध में वे केवल अखबारों में वक्तव्य छपवाकर ही चुप नहीं बैठे, बल्कि जुलूस में भाग लेकर पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी हुए। इन गिरफ्तार होने वालों की सूची में 'मिस्टर एण्ड मिसेज अय्यर' फिल्म की निर्देशक तथा सुप्रसिद्ध बंगला अभिनेत्री अपर्णा सेन, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्देशक गौतम घोष, 'परिणीता' के निर्देशक ऋतुपर्ण घोष, नाटककार विभास चक्रवर्ती, अभिनेता कौशिक सेन, साहित्यकार महाश्वेता देवी, प्रसिद्ध कलाकार शुभाप्रसन्न आदि थे। १२ नवम्बर, २००७ को पुलिस आयुक्त गौतम चक्रवर्ती तथा मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इनकी गिरफ्तारी पर खेद व्यक्त किया। १४ नवम्बर को कलकत्ता में विशाल विरोध रैली हुई जिसमें एक लाख से अधिक लोग एकत्र हुए थे। नन्दीग्राम के नृशंस हत्याकाण्ड के विरोध में बंगाल के वरिष्ठ फिल्मकारों ने १० नवम्बर से शुरू हुए कोलकाता फिल्म उत्सव का बहिष्कार किया। विख्यात अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने तो वहां पुरस्कार लेने तक से इनकार कर दिया। इस उत्सव को लेकर हर साल जो उत्साह तथा उमंग दिखाई देती थी, वह इस बार गायब है। चारों ओर केवल पुलिस, पुलिस और

पुलिस ही घूमती नजर आई। सभी माकपा नेता तथा माकपा कार्यालय आज पुलिस के सुरक्षा घेरे में हैं। नंदीग्राम में जहां वे 'विजयी' मुद्रा में घूम रहे हैं वहीं कोलकाता में इनकी छवि डरे हुए छुटभैयों जैसी है। कलाकार शुभाप्रसन्न कहते हैं, 'हमने इतिहास में पढ़ा था कि जब इटली की राजधानी रोम जल रही थी तब वहां का राजा नीरो बंसी बजा रहा था। आज जब नंदीग्राम जल रहा है तब राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य नन्दन प्रेक्षागार की ठण्डक में बैठकर फिल्म उत्सव का मजा लूट रहे हैं। हे भगवान, यही लोग खुद को सर्वहाराओं के नेता कहते हैं!' गत मार्च में माकपा ने जिस तरह से पुलिस व प्रशासन को इस्तेमाल करके नंदीग्रामवासियों की हत्या की थी तथा उन पर अत्याचार किए थे उसकी तुलना मुगल या ब्रिटिश शासन की बर्बरता से ही की जा सकती है। मगर तब भी खेजुरी नामक स्थान तक ही इनका प्रभाव सीमित रहा था। इस 'हार' को 'जीत' में बदलने की लिये इस बार छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखकर विस्तृत योजना बनाई गई थी। इसके पहले भी बाहर से गुण्डों को लाया गया था। परन्तु इस बार चुन-चुनकर उन गुण्डों को इस्तेमाल किया गया जो कि इसके पहले किये गये हमलों, जैसे छोटा अंगरिया कांड, नानुर गणहत्या, गड़वेता, पिंला, केशपुर आदि कांडों में अपनी बर्बरता दिखा चुके थे।

नंदीग्राम में ऐसे बढ़ा घमासान

2006, 31 मार्चः पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ एक समझौता कियां उसी के तहत नंदीग्राम में एसईजे का विकास किया जाना था।

2007, 3 जनवरीः हिंसा की शुरूआत, नंदीग्राम में कृषि भूमि के अधिग्रहण का जनता द्वारा विरोध और पुलिस फायरिंग।

4 जनवरीः माकपा ने एसईजेड कानून में संशोधन की मांग की।

6 जनवरीः विरोध के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का गठन।

9 जनवरीः तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

14 मार्चः पुलिस कार्रवाई में 14 ग्रामीण मारे गए।

15 मार्चः हत्याकांड पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश।

ये लोग अपने साथ आग्नेयास्त्र तथा पुलिस शस्त्रों से लैस होकर नंदीग्राम में घुसे थे। उन्होंने निरपराध ग्रामवासियों पर अन्धाधुंध गोलियां चलायीं। मृतकों या घायलों को तुरन्त किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया जाता था, ताकि किसी को मृतकों की असली संख्या के बारे में पता ही न चल सके। हिंसक रक्तपात का विरोध करने गईं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को माकपा कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम जाने से रोका, मगर किसी तरह छुपते-छुपाते वे नंदीग्राम जाने में सफल हुईं। पत्रकारों को पीटा गया। इसी दौरान खुफिया पुलिस के हाथ लगे दो पुराने अपराधी-सुकुर अली तथा तपन घोष। ये दोनों छोटा अंगरिया हत्याकाण्ड के अपराधी थे और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। परन्तु शासक दल यानी माकपा की सहायता से वे गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे थे। इसी सिलसिले में एक षडयंत्र की भी पोल खुल गयी। नंदीग्राम पर हमला करने से पहले माकपा द्वारा यह प्रचार किया गया था कि नंदीग्राम में माओवादी घुस गए हैं और वे लोग माकपा समर्थकों पर हमला कर रहे हैं। परन्तु सुकुर और तपन के पकड़े जाने पर यह स्पष्ट हो गया है कि माओवादियों के नाम पर यही लोग हमला कर रहे थे जो कि पहले से तय था।

इस षडयंत्र में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध रही। गत दिनों

29 अप्रैलः फिर हिंसा भड़की, समिति और माकपा के लोग भिड़े।

8 मईः ममता शांति वार्ता के लिए तैयार।

24 मईः सर्वदलीय बैठक विफल।

30 जुलाईः प्रतिरोध समिति ने किया राज्यव्यापी बंद का आह्वान।

6 नवंबरः प्रतिरोध समिति व माकपा कार्यकर्ताओं की भिडंत में दो मरे, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता।

8 नवंबरः नंदीग्राम जाते समय मेधा पाटकर पर किया गया हमला।

9 नवंबरः नंदीग्राम मुद्दे पर राज्यपाल जीके गांधी ने सत्ताधारी माकपा की आलोचना की।

10 नवंबरः ममता की लोकसभा से इस्तीफे की घोषणा।

11 नवंबरः सहयोगी दलों ने माकपा को जिम्मेदार ठहराया।

12 नवंबरः बंगाल बंद, सीआरपीएफ नंदीग्राम में प्रवेश करने में सफल।

13 नवंबरः राज्य सरकार ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी।

13 नवंबरः श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एनडीए शिष्ट मंडल का नंदीग्राम दौरा।

रिजवानुर नाम के एक मुस्लिम युवक के साथ एक हिन्दू लड़की प्रियंका के विवाह की घटना पुलिस प्रशासन ने इस तरह से फैलाई ताकि आम लोगों की नजर नंदीग्राम से हट जाए। उसी मौके का फायदा उठाकर नंदीग्राम षडयंत्र रचा गया था।

उस षडयंत्र की एक कड़ी यह भी थी कि पुलिस को निष्क्रिय रखकर पार्टी कैडरों को हत्याकाण्ड में, नंदीग्राम के लोगों को घर से निकाल बाहर करने में तथा उनके घरों को आग लगाने में जुटा दिया गया था। उधर मुख्यमंत्री यह प्रचार कर रहे थे कि सी.आर.पी.एफ. बल की मांग करने पर भी केन्द्र सरकार इसे भेज नहीं रही है। सत्य तो यह है कि ११ नवम्बर सायं ३ बजे तक सी.आर.पी.एफ. को नंदीग्राम के आसपास जाने ही नहीं दिया गया क्योंकि तब तक सम्पूर्ण नंदीग्राम पर माकपाई अपना कब्जा फिर से जमा नहीं पाए थे। इसे पूरे हिंसक षड्यंत्र में दस हजार ग्रामवासियों को बेघर कर दिया गया, ५० घरों को जला दिया गया। ग्रामवासियों के खून की होली खेलने के बाद इन हत्यारों ने 'विजयी जुलूस' निकालकर घाव पर नमक छिड़का। इतना कुछ होते हुए भी केन्द्र की यूपीए सरकार चुप्पी साधे है, क्योंकि माकपा के समर्थन पर यह सरकार टिकी है।

कलकत्ता हाईकोर्ट सक्रिय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नंदीग्राम में हुई हिंसा में प्रभावित लोगों के उपचार और गांव में गैर सरकारी संगठनों तथा मीडिया के प्रवेश की तुरंत व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को नंदीग्राम में शांति बहाल करने, गैर सरकारी संगठनों को सेवा करने और मीडिया को स्थिति का स्वतंत्र आंकलन करने देने के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए। एक पखवाड़े से जारी झड़पों के दौरान नंदीग्राम में मीडिया और स्वयंसेवी संगठनों को प्रवेश नहीं करने दिया गया है।

न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र गुप्ता और न्यायमूर्ति तपन मुखर्जी की अवकाश कालीन पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमर मुखर्जी और दो अन्य की याचिका पर यह निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नंदीग्राम में झड़पों में कम से कम दस लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पीठ ने हालात से निपटने में प्रशासन की लापरवाही पर आकोश भी व्यक्त किया।

(साभार : दैनिक भास्कर)

नंदीग्राम पर ऐसे कब्जा जमाया माकपा ने

भाड़े के सिपाहियों, अपराधियों के हाथों में थी माकपाई सेना की कमान।

माकपा ने नंदीग्राम पर फिर से कब्जा कर लिया है। पार्टी का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति (बीयूपीसी) का गढ़ रहे इस इलाके के तकरीबन सभी गांवों पर कई किलोमीटर लंबा जुलूस निकालकर उसने अपन झंडा गाड़ दिया है। यह संभव हुआ है माकपा की निजी सेना के जरिए।

एक हफ्ते तक चले ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए ते-तर्रार निजी सेना बनाई गई। कैसी हे यह निजी सेना? डीएनए-भास्कर ने यह पता लगाने के लिए नंदीग्राम के लोगों, पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की।

दुर्गापूजा के बाद हुई प्लानिंगः पिछले माह दुर्गा पूजा महोत्सव खत्म होने के तत्काल बाद माकपा का शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं के भारी दबाव में आ गया था। कार्यकर्ता हाथ से निकल चुके नंदीग्राम पर फिर से कब्जा करना चाहते थे। स्थानीय नेताओं को आशंका थी कि नंदीग्राम के हाथ से निकल जाने पर अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। माकपा के बड़े नेता कोई बड़ा प्रशासनिक कदम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम में पुलिस तैनात करने के बाद फायरिंग में १४ लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में विकल्प के तौर पर तय किया गया कि नंदीग्राम से संबंध रखने वाले राज्य के एक मंत्री और एक सांसद को पार्टी मुख्यालय बुलाया जाए।

थोड़े समय में ही सेना तैयारः 'केशपुर लाइन' के आधार पर समूचे ऑपरेशन का बड़ा आक्रामक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। २६ अक्टूबर से ३ नवंबर तक के संक्षिप्त समय में ही माकपा ने निजी सेना खड़ी कर दी। वॉर रूम का प्रबंधन पूर्वी मिदनापुर के पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक गुरिया ने संभाला। उनके साथ थ, नंदीग्राम में छह जनवरी को

अपनी जान गंवाने वाले पार्टी नेता शंकर सामंत के भाई नव कुमार सामंत। यह तय हुआ कि पार्टी कार्यकर्ता इस सेना के पैदल सिपाही होंगे और बाहरी लोग पहले हमला बोलेंगे।

कुख्यात अपराधियों से सजी सेनाः कार्यकर्ताओं के काडर पडोस के गरबेटा और चन्द्रकोण से लाए गए। प्लाटून को कुख्यात और स्थानीय अपराधियों से सजाया गया। तपन घोष और सुकुर अली जैसे भूमिगत नेताओं की विशेषज्ञता का लाभ लिया गया। घोष और अली छोटा अंगारिया में तृणमूल कार्यकर्ताओं को जलाने के मामले में सीबीआई के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं।

गोला-बारूद का प्रबंधः पड़ोस के बांकुडा जिले के ओंडा और राजपुर तथा बिहार-झारखंड से भी काडर बुलवाए गए। टी को पड़ोसी राज्यों से हथियार व गोला-बारूद नंदीग्राम तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया।

'पुलिस कुछ न करें'ः चार नवंबर को माकपा मुख्यालय ने निजी सेना को हरी झंडी दिखा दी। नंदीग्राम थाने का खास निर्देश दिए गए कि वह किसी भी हालत में पुलिस न भेजे। पांच नवंबर को पूर्वी मिदनापुर के एसपी ने ऑन रिकार्ड कहा कि उन्हें सुरक्षाबल नंदीग्राम भेजने के निर्देश नहीं हैं।

...और शुरू हुआ अभियानः छह नवंबर को सेना की एक टुकड़ी ने नंदीग्राम की ओर कूच किया। तलपट्टी नहर की टेखाली पुलिया पार कर उसने भांगबेरा में विरोधियों पर फायरिंग शुरू की लेकिन यह तो महज एक दिखावा था। बड़ी टुकड़ी नहर पार कर गरचकबेरिया और सतेंगोबरी की तरह बढ़ गई। यह बड़ी सेना विरोधियों पर भारी पड़ी और गांव के गांव सेना के कब्जे में आते चले गए। विरोधियों और उनके समर्थकों को माकपा सेना ने बंधक बना लिया।

आठ नवंबर को सेना भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के मजबूत गढ़ सोनाचूरा की ओर बढ़ने को तैयार थी। कहीं से कोई विरोध नहीं था। क्यों? क्योंकि सेना के साथ सबसे आगे बंधक चल रहे थे, उनके पीछे माकपा काडर और फिर स्वचालित हथियारों से लैस सेना के 'सिपाही'। खुद के लोगों को बंधक बना देख बीयूपीसी के दस्तों ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। अंततः १० नवम्बर को नंदीग्राम फिर से माकपा के कब्जे में आ चुका था। (साभार : दैनिक भास्कर)

वामपंथी आतंक का भयावह सच

एनडीए शिष्टमंडल ने चार घण्टों तक नन्दीग्राम के कई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया कुछ स्थानों पर शिष्टमंडल २ किलोमीटर से अधिक दूरी तक चल कर ऐसे खण्डों में भी गया, जहां सीपीआई (एम) के कार्यकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र को उजाड दिया था और वहां के कई जाने-माने लोगों से बातचीत की। शिष्टमंडल पहले अधिकारीपाड़ा गया, जहां उसने कई स्थानों पर रूक कर रास्ते में पड़े कई गांव वालों से बातचीत की। बाद में यह घायल व्यक्तियों को सांत्वना देने के लिए नंदीग्राम हस्पताल गया और इसके बाद नन्दीग्राम हाई स्कूल परिसर स्थित राहत शिविर का निरीक्षण किया। विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने लोगों की मांग पर स्कूल के मैदान में

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के एक शिष्टमंडल ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। यह दौरा 13 नवम्बर को सम्पन्न हुआ। इस शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

1- Jh ykyd".k vkMok.kh] foi{k d urk
2- Jherh l"kek Lojkt] miurk] jkT;lHkk e foi{k dh urk
3- Jh 'kjn ;kno] vè;{k] tn ¼;½ vkj lkln ¼jkT;lHkk½
4- Jh ct fd'kkj f=ikBh] urk cht turk ny ¼ykdlHkk½
5- Jh l[kchj flg ckny] urk f'kjkef.k vdkyh ny] ykdlHkk
6- Jh ljUn flg vgyokfy;k] e[; lprd Hkktik ¼jkT; lHkk½
7- Jh vuUr xM] lkln] ykdlHkk] f'koluk
8- Jh 'kjn tk'kh] lkln] jkT;lHkk] Lor= Hkkjr i{k
9- Jh pnu fe=k] lkln] jkT;lHkk
Jh edy jk;] r.key dkxl] lkln ¼jkT;lHkk½ dkydkrk ,;jikV l f'k"VeMy e 'kkfey g,A

तत्काल जमा हो गई जनसभा को सम्बोधित किया। इसके बाद यह दल संतंगाबाडी गया। समझा जाता है कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने इस गांव को बदला लेने की दृष्टि से विशेष रूप से अपना निशाना बनाया था। समय की कमी के कारण प्रतिनिधिमण्डल को अपने दौरे को कम करना पड़ा और वह संतंगाबाडी के बाहर के क्षेत्र कमालपुर में की गई विनाशलीला को देखकर लौटना पड़ा क्योंकि प्रतिनिधिमण्डल को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी से मिलना था। महामहिम राज्यपाल के साथ नन्दीग्राम की भयानक स्थिति पर ३० मिनिट तक बातचीत हुई। इसके बाद मंगलवार रात्रि को प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली वापस लौट आया।

शिष्टमंडल के अनुभवों को संक्षेप में नीचे दिया गया हैः

१. दिवाली की सप्ताहंत के अवसर पर सुनियोजित और पैशाचिक ढंग से सीपीएम के कार्यकर्ताओं की करतूतों की ''विजय'' के बाद नंदीग्राम का अन्दरूनी भाग किसी कब्रगाह के दृश्य की खामोशी प्रगट कर रहा था। १० नवम्बर को राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में जिस ''अवैध युद्ध क्षेत्र की स्थिति जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो बात कही थी, उसके बाद सामूहिक रूप से ऐसे लोगों का पलायन शुरू हो गया सीपीएम के अत्याचारों के आगे आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। इसके फलस्वरूप केवल कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ही दिखाई पड़ें, जबकि अधिकांश लोग छिपे हुए ठिकानों पर चले गए। देखा गया कि लोग इस बुरी तह से आंतकित थे कि वे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे थे और लगता था कि सीपीएम के कार्यकर्ता निरन्तर उन लोगों पर नजर रखे हुए थें।

२. सीपीएम के समर्थन नन्दीग्राम गांवों मे जा बसे हैं और वे पार्टी को सूचना देने का साधन बने हुए हैं। यह बाध्यकारी बना दिया गया है कि हर घर पर सीपीएम का झण्डा लहराया जाए। प्रतिनिधि मण्डल ने देखा कि वहां हाल ही में पार्टी के निशाने वाले लाल झण्डों के गट्ठे ले जाए गए थे, जो सड़क के किनारे पड़े हुए थे, जिन्हे हर घर की छत पर लगाया जाना था। एनडीए टीम को बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति ''युद्धक्षेत्र आप्रेशन'' के बाद चला गया है तो उसे वापस आने के लिए कुछ शर्तों के

साथ 'नो आब्जेक्शन' प्रमाण पत्र सीपीएम स्थानीय समिति से लेना होगा, जिसमें यह शर्त भी शामिल रहेगी कि वह अपनी राजनीतिक आस्था बदल लेगा और वह मीडिया से बात नहीं करेगा।

३. पूरे क्षेत्र में आतंक छाया हुआ है और लोग खुलकर बात करने से डरे हुए हैं। किन्तु बहुत सी महिलाएं, विशेष रूप से श्रीमती सुषमा स्वराज से मिली। स्पष्ट था कि इन महिलाओं ने अपने पति और या पुत्रों का पता लगाने की बात कही जो कई महीनों से 'मिसिंग' हैं। प्रतिनिधिमण्डल को लगा कि 'मिसिंग' का मतलब है कि वे 'मृत' हैं और अधिकारियों ने ऐसे लोगों को 'मिसिंग' बताना ही बेहतर समझा क्योंकि इससे निर्मम हत्या में मारे जाने वाले लोगों की संख्या कम करने में मदद मिलती थी।

४. प्रतिनिधिमण्डल 'सीपीएम की प्लानिंग' से हतप्रभ था। नन्दीग्राम अस्पताल में बहुत से बिस्तर खाली थे, जिससे यह भाव दिया जाता था कि पिछले सप्ताह हुई हिंसा में शायद ही कोई घायल हुआ हो। कोलकाता के मीडिया के प्रमुख चैनल हतप्रभ थे क्योंकि एक दिन पहले ही तो हस्पताल में गम्भीर रूप से घायल लोगों से पटा पड़ा था। स्थानीय निवासियों से बताया कि एनडीए की टीम के दौरे की तैयारी में सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने रोगियों को चेतावनी दे दी थी कि वे सोमवार की रात को ही अस्पताल छोड़ कर चले जाएं और अधिकांशतः लोगों ने डर से उनकी आज्ञा मानी।

५. नन्दीग्राम राहत शिविर से चीत्कार करती महिलाओं ने प्रतिनिधिमण्डल के पास पहुंच कर उससे मदद मांगी कि वह उन लोगों का पता लगाए और उन्हें दण्डित कराए जिन्होंने उनके पुत्रों और पति की हत्या कर दी है। टीम एक दस वर्षीय बालक गोपाल से मिली, जिसकी मां श्यामली को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने शांति मार्च में भाग लिया था। उसके पति का पहले से ही पता नहीं चल रहा था।

६. सतंगाबाडी के पास कमालपुर में एक बड़ा दो मंजिला मकान देखा जो पूरी तरह से जला कर राख कर दिया गया था। उसके मालिक मोहिबुल ने कहा कि सीपीएम के हथियारबंद कार्यकर्ता

वहां बृहस्पतिवार रात को आए और इमारत को आग लगा दी। यह स्पष्ट ही बदले की भावना से किया कार्य था क्योंकि मोहिबुल का बड़ा भाई भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का नेता था, जो एक ऐसी संस्था थी जो इस क्षेत्र में सीपीएम के अत्याचारों का विरोध करती थी।

७. श्री आडवाणी और श्रीमती सुषमा स्वराज जो इस वर्ष १४ मार्च से हो रही हिंसा के प्रथम दौर से यहां तीन बार आ चुके थे। ने बताया कि आज नन्दीग्राम में आतंक की भावना छाई हुई हैं। श्रीमती स्वराज ने कहा कि पहले के दौरों के समय हजारों लोग के चेहरों पर छाये भय और अत्यंत तनावपूर्व वातावरण अपनी कहानी स्वयं कह रहे थे।

बच्चे मांग रहे हैं भीख

उधर भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के साथ कई दिनों के सशस्त्र संघर्ष के बाद माकपा के लोगों द्वारा फिर कब्जा किए जाने के बाद से नगर के आंतरिक इलाकों में कई जगह वीरानी छायी है। नंदीग्राम बाजार राहत शिविर पर बच्चे भीख मांगते दिखायी दिए। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, एक लड़के ने कहा, 'हमें दोपहर में ही खाने को मिलेगा। सबेरे से हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हम भूखे हैं।' डरावनी कहानियां भी सुनने को मिल रही है। पिछले आठ दिन से शिविर में रह रहे गोलुनगर अधिकारीपाडा के पिजुश कांति दसाधिकारी ने कहा, 'हमें मारा गया और हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यहार किया गया। राज्य प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। हम कैसे घर जा सकते हैं।' नंदीग्राम बाजार में १५०० से ज्यादा शरणार्थी शिविर में पनाह लिए हए हैं। सीआरपीएफ के जवान यहां चौकसी रख रहे हैं।

राष्ट्रीय सहारा, १६ नवंबर २००७

लोकतंत्रीय भारत में स्टालिन का 'भूत'

nioUæ Lo:i

कोलकाता से केवल १६० किलोमीटर दूर पूर्वी मेदिनीपुर जिला के नंदीग्राम इलाके में पिछले ११ महीने से जो रक्तरंजित इतिहास लिखा जा रहा है, वह रोंगटे खड़े करने वाला है। प. बंगाल की माकपा नियंत्रित वाममोर्चा सरकार ने इन्डोनेशिया की सलीम कम्पनी का केमिकल्स कारखाना खड़ा करने के लिए नंदीग्राम के उपजाऊ खेतों के अधिग्रहण की एकपक्षीय घोषणा कर दी। किसानों ने उसका विरोध किया। जबरन अधिग्रहण को रोकने के लिए उन्होंने ६ जनवरी, २००७ को 'भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति' का गठन कर सामूहिक प्रतिरोध का संकल्प लिया। वहां के गरीब किसानों का नारा था 'जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे।' इसे स्वयं को गरीबों का हमदर्द बताने वाली माकपा और उसकी सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। यह समूचा क्षेत्र जो कभी माकपा का गढ़ माना जाता था अब जमीन रक्षकों और पार्टी वफादारों में विभाजित हो गया। संघर्ष

टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता नि□य बनर्जी को धामकी दी कि तुम गरचकबेरिया क्यों जा रहे हो? तुम्हें कार सहित गायब कर दिया जाएगा। नंदीग्राम में जो कुछ हुआ उससे बंगाल के कलाकारों, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा विद्रोह कर उठी। अर्पणा सेन और ऋतुपर्ण घोष ने बंगाल सरकार का पुरस्कार लेने से मना कर दिया, फिल्म मेले का बहिष्कार कर दिया।

का बिगुल बज गया। किसानों ने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया और सरकार का साथ देने वाले माकपाइयों को अपने गांवों से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने नंदीग्राम की सीमा पर खेजुड़ी नामक स्थान को अपने भावी युद्ध का दुर्ग बना लिया। इस लड़ाई को 'दखल' की लड़ाई कहा गया। गांवों पर कब्जा गांववासियों का हो या माकपा और उसकी सरकार का। सरकार जनता को सुरक्षा देने के बजाय पार्टी के पीछे खड़ी थी और पार्टी जमीन और गांवों पर फिर से दखल जमाने के लिए बेताब थी।

दखल का बड़ा प्रयास २४ मार्च को हुआ जब पुलिस की छत्रछाया में सशस्त्र माकपा काडर ने गांवों पर हमला बोल दिया। मकान जलाये गये, महिलाओं के बलात्कार की दिल दहलाने वाली कहानियां सामने आयीं, पुलिस की गोलियों से कम से कम १४ गांव वालों की मृत्यु की खबर की सरकार ने भी पुष्टि की। घायलों की तादाद तो बहुत ज्यादा थी।

इस घटना से पूरे देश में हलचल मच गई। क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर भी ऐसा हो सकता है कि कोई सरकार अपनी ही जनता के विरुद्ध किसी एक पार्टी के इशारे पर लड़ाई छेड़ दे? स्टालिन युग के रूस की त्रासदी आंखों के सामने घट रही थी। वहां तो पार्टी का अधिनायकवाद था, पार्टी ही सरकार थी, मीडिया की जुबान बंद थी, जनता की आवाज उठाने वाली किसी दूसरी पार्टी का अस्तित्व नहीं था। अधिनायकवादी व्यवस्था के लौह आवरण के पीछे रूस की जनता पर रूस की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके तानाशाह स्टालिन ने अमानुषिक जुल्म ढाये, हजारों-लाखों बेगुनाहों का कत्लेआम केवल इसलिए हुआ कि उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों से असहमति दिखाई, उन्होंने सरकार को कुछ सलाह देने की कोशिश की। स्टालिन के अत्याचारों की, उसकी निरंकुशता की, उसके द्वारा रचे गये नरमेध की खबरें छन-छन कर बाहर आती थीं, किन्तु भारत और दुनियाभर के कम्युनिस्ट उन्हें पूंजीवादी 'प्रोपेगेण्डा' कहकर उड़ा देते थे। पर, स्तालिन की मृत्यु के तीन वर्ष बाद १९५६ में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की २०वीं कांग्रेस के एक गोपनीय सत्र में स्टालिन के उत्तराधिकारी निकिता खुश्चेव ने जब रूस की बेबस जनता पर स्टालिन के अमानुषिक अत्याचारों और भयंकर नरमेध का हृदय-द्रावक

वर्णन प्रस्तुत किया तो पूरा सदन सिसकियों और सुबकियों से भर उठा था। खुश्चेव रपट को दुनिया से छिपाने की भरसक कोशिशों के बावजूद पश्चिमी देशों के स्वतंत्र मीडिया ने उसका भांडा फोड़ ही दिया और अब तो 'ब्लैक बुक आफ कम्युनिज्म', नोबेल पुरस्कार विजेता सोलझेनित्सिन की 'गुलग आर्चीं पेलेगो' जैसी पुस्तकों के माध्यम से स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के जनविरोधी अत्याचारों एवं विशाल नरमेध की अनेक कहानियां उपलब्ध हैं।

कम्युनिस्ट हिंसा

आशा की जाती थी कि लोकतांत्रिक भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बनने के बाद भारतीय कम्युनिस्टों की सोच और मानसिकता में कुछ बदल आया होगा पर यह आशा निर्मूल सिद्ध हुई है। जिन दो राज्यों-बंगाल और केरल में उन्हें सत्ता का स्वाद मिला है, वहां से समय-समय पर कम्युनिस्ट हिंसा की खबरें आती रही हैं। केरल में माकपा छोड़कर गये कार्यकर्ताओं की हत्या की अनेक घटनायें घट चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर हमलों एवं संघ के कई कार्यकर्ताओं की हत्या के समाचार भी आते रहे हैं। इसी प्रकार बंगाल में वाममोर्चे के छोटे घटकों जैसे फार्वर्ड ब्लाक और आर.एस.पी. के साथ माकपा के खूनी संघर्ष के अनेक प्रसंग उत्पन्न हुए हैं। इन सबके बावजूद यह माना जाता रहा कि माकपा सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी होने और अपने जन्मकाल से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन जाने के कारण अन्दर से काफी बदल चुकी होगी, वह जन-भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होगी, वह सत्ता को जन-कल्याण का साधन समझती होगी न कि उसे ही साध्य समझती होगी पर, नंदीग्राम के ग्यारह महीने के घटनाचक्र ने माकपा के वास्तविक चरित्र को नंगे रूप में प्रगट कर दिया है। अब उसके लिए सत्ता पाना और सत्ता में बने रहना ही 'क्रान्ति' की व्याख्या हो गई है। लेनिन ने भगवान की जगह पार्टी को बैठा दिया था। किसी कम्युनिस्ट की निष्ठा का वास्तविक केन्द्र पार्टी होती है। जिस प्रकार मुसलमानों में प्रचलित है कि 'एक बार अल्लाह के साथ गुस्ताखी बर्दाश्त हो सकती है, पर पैगम्बर के साथ छेड़खानी मत करना', उसी प्रकार कम्युनिस्टों में पार्टी ही विचारधारा है, पार्टी ही मार्क्स से भी ऊपर है। पार्टी के लिए जीना-मरना ही निष्ठा की एकमात्र कसौटी है। इसी फार्मूले के तहत

बंगाल में पार्टी और सरकार का भेद मिट चुका है। पार्टी और प्रशासनतंत्र एकरूप हो चुके हैं। बंगाल की पुलिस जनता के लिए नहीं, संविधान के लिए नहीं, पार्टी के लिए काम करती है। दोनों के सम्मिलित शिकंजे को तोड़ना आसान नहीं है। यही है बंगाल में कम्युनिस्ट शासन की ३० वर्ष लम्बी अखण्डता का असली रहस्य। नंदीग्राम को श्रेय जाता है कि उसने पहली बार इस रहस्य को पूरी तरह बेपरदा कर दिया। पहली बार यह रहस्य खुला कि प. बंगाल का कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य स्वयं को मुख्यमंत्री से अधिक माकपा का कार्यकर्ता मानते हैं। उनकी सहानुभूति नंदीग्राम से अधिक अपनी पार्टी के कैडर के साथ है। उनकी पार्टी कैडर ने गुंडों की सहायता से शस्त्र बल द्वारा नंदीग्राम पर जबरन कब्जा कर लिया इससे वह चिन्तित नहीं, गर्वित हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसी गुंडागर्दी की विजय पर हर्षित होकर कह सकता है कि 'हमने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया' हमारे सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन बुद्धदेव अपने को दुखारी जनता के साथ नहीं, हथियारों से लैस पार्टी के साथ खड़ा करना चाहते हैं।

एक पुराने कम्युनिस्ट प्रोफेसर सुमित सरकार ने गुस्से में आकर बुद्धदेव को गुजरात के नरेन्द्र मोदी की पंक्ति में बैठा डाला। पिछले चार साल से कम्युनिस्ट प्रचारतंत्र का पूरा हमला नरेन्द्र मोदी पर केन्द्रित है। जिस प्रकार कम्युनिस्ट शासन में पार्टी का महामंत्री ही राष्ट्रपति होता है, उसके इशारे के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी कम्युनिस्ट अधिनायक की छवि उन्होंने नरेन्द्र मोदी पर थोप दी। २७ फरवरी, २००२ को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में ५६ रामसेवकों को जिन्दा जलाने की घटना की व्यापक जन प्रतिक्रिया को वे मुख्मयंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रायोजित सिद्ध करने की जी तोड़ कोशिश की। पर नरेन्द्र मोदी ने आज तक एक भी शब्द उस जन प्रतिहिंसा की वकालत में नहीं बोला। उन्होंने कभी 'हम' और 'वे' की भाषा नहीं बोली, वह तब से आज तक पांच करोड़ गुजरातियों के विकास और कल्याण की ही भाषा बोल रहे हैं, वे गुजरात की समग्र अस्मिता के प्रवक्ता बन गये हैं। 'हम' और 'वे' की 'ईंट का जवाब पत्थर से देने' की भाषा बोलने वाले बुद्धदेव भट्टाचार्य की नरेन्द्र मोदी के साथ तुलना करना बौद्धिक दिवालियेपन का लक्षण है।

माकपा की योजना

'वे' और 'हम' की मानसिकता पूरी माकपा के ऊपर से नीचे तक व्याप्त है। नंदीग्राम में ७ नवम्बर से ११ नवम्बर तक वहां की निहत्थी गरीब जनता पर जो सशस्त्र विजय अभियान चला वह अकेले बुद्धदेव के मस्तिष्क की उपज नहीं है, उसके वयोवृद्ध ज्योति बसु से लेकर विमान बसु, महासचिव प्रकाश कारत की बीवी और पालित ब्यूरो की सदस्या वृन्दा कारत तक सभी शीर्षस्थ माकपाई नेताओं की सांझी योजना ही है। एक टेलीविजन चैनल पर गुस्से से तमतमाये ज्योति बसु को यह कहते मैंने सुना कि नंदीग्राम पर तृणमूल के अनुयायियों के कब्जे को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। बंगाल के माकपा नेता विनोय कोनार ने बार-बार कहा कि चाहे कितनी भी हिंसा क्यों न करनी पड़े, नंदीग्राम को माकपा के कब्जे में लाना ही होगा। अब हम उसी भाषा में बोल रहे हैं जो हमारे विरोधियों की समझ में आती है। वाम मोर्चे के अध्यक्ष विमान बसु ने कहा कि जब हम पर बम फेंके जा रहे हों तो हम रसगुल्ले नहीं फेंकेंगे। वृन्दा करात ने बंगाल जाकर महिला कार्यकर्ताओं को खुलेआम हिंसा का आह्वान करते हुए कहा कि हिंसा एक वैध रास्ता है। वृन्दा कारत का इस आह्वान के पीछे पार्टी की सर्वोच्च संस्था पालित ब्यूरो और उसके महासचिव की आज्ञा के रूप में देखा गया होगा।

इस प्रकार पूरी पार्टी की मर्जी से नंदीग्राम विजय का सशस्त्र अभियान रचा गया। इस अभियान की तैयारी दुर्गा महोत्सव के तुरन्त बाद आरंभ हो गई। इस बार तय किया गया कि पुलिस उसमें सीधे भाग न ले। पुलिस को केवल इतना काम दिया गया कि वह नंदीग्राम क्षेत्र की पूर्ण नाकाबंदी में दखल देने के बजाय उसे सफल बनाने में मदद करे। अर्थात् नंदीग्राम पहुंचने की कोशिश करने वाले मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोकने के प्रयत्नों में बाधा न डाले। इस प्रकार पुलिस की सहायता से नंदीग्राम पहुंचने वाले सब रास्तों को सील कर दिया गया। मेधा पाटकर जैसी सामाजिक कार्यकर्ता और ममता बनर्जी जैसी राजनेता पूरी कोशिश करके भी नंदीग्राम नहीं पहुंच पाईं। मेधा पाटकर की कार पर हमला किया गया। वे धरने पर बैठीं पर बंगाल सरकार ने उनकी ओर से आंखें मूंद लीं।

एक दैनिक पत्र के अनुसार २६ अक्तूबर से ३ नवम्बर तक के

अल्पकाल में माकपा ने एक निजी सेना खड़ी कर ली। इस सेना में पूरे बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बिहार-झारखंड से भी काडर बुलवाए गए। छंटे हुए अपराधी तत्वों को इस फौज के साथ जोड़ा गया। एक 'वार रूम' बनाया गया जिसका प्रबंधन पूर्वी मिदनापुर के जिला पार्टी अध्यक्ष अशोक गुरिया को सौंपा गया। तृणमूल कार्यकर्ताओं को २००१ में जिंदा जलाने के आरोप में भूमिगत तपन घोष और सुकुर अली जैसों की विशेषज्ञता का लाभ लिया गया, गोला-बारूद और बन्दूकें जुटायीं गईं। यह तैयारी पूरी हो जाने पर चार नवम्बर को माकपा मुख्यालय ने निजी सेना को, जिसे हरमत ब्रिगेड नाम दिया गया, आक्रमण के लिए हरी झंडी दिखाई। नंदीग्राम थाने को खास निर्देश दिये गये कि वह किसी भी हालत में पुलिस न भेजे। पांच नवम्बर को पूर्वी मिदनापुर के एसपी ने आन रिकार्ड कहा कि उन्हें सुरक्षाबल नंदीग्राम भेजने के निर्देश नहीं हैं।

दैनिक भास्कर के अनुसार, 'छह नवम्बर को इस सेना की एक टुकड़ी ने नंदीग्राम की ओर कूच किया। तलपट्टी पुलिया की टेखाली पुलिया पार कर उसने मांगबेरा में विरोधियों पर फायरिंग शुरू की। लेकिन यह महज दिखावा था। बड़ी टुकड़ी नहर पार कर गरचकबेरिया और सतेगाबेरी की तरफ बढ़ गई। यह बड़ी सेना विरोधियों पर भारी पड़ी और गांव के गांव सेना के कब्जे में आते गये। विरोधियों और उनके समर्थकों को सेना ने अपना बंधक बना लिया।

झूठे वामपंथी

आठ नवम्बर को सेना भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के मजबूत गढ़ सोनाचूरा की ओर बढ़ चली। उसका कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि सेना के आगे आगे 'बंधकों' को रखा गया था, उनके पीछे माकपा काडर और फिर स्वचालित हथियारों से लैस सेना के 'सिपाही'। खुद के लोगों को बंधक बना देख बी.यू.पी.सी. के दस्तों ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। अंततः १० नवम्बर को नंदीग्राम के ३२ गांव फिर से माकपा के कब्जे में आ गये।' दसियों हजार ग्रामवासी अपने घरों से उजड़ गये, उनके घर जलाकर राख कर दिये गये। किसी के पति, किसी के पुत्र लापता हो गये। इस विजय अभियान में कितने लोग मारे गए इसका निर्णय करने का कोई साधन नहीं।

माकपा का लाल झंडा विजय का प्रतीक बन गया। पार्टी के प्रति

अपनी निष्ठा प्रगट करने के लिए अपने घर पर लाल झंडा फहराना आवश्यक हो गया। पायनियर के सम्पादक चंदन मित्रा ने एन.डी.ए. टीम के सदस्य के नाते नंदीग्राम का आंखों देखा वर्णन लिखा है जिसे पढ़कर दिल बैठ जाता है कि क्या सचमुच किसी लोकतंत्रीय देश में ऐसा दृश्य खड़ा किया जा सकता है। वे लिखते हैं, नंदीग्राम में पूरा सन्नाटा छाया है, वहां बच्चे रोना भूल गए हैं और कुत्ते भोंकना। यह मरघट की शान्ति का दृश्य है। वे बताते हैं कि बी.यू.पी.सी. के समर्थक गरीब किसान अपनी पकी फसल को काटने के लोभ में माकपा के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनसे आत्मसमर्पण पत्र पर अंगूठा लगवाया जाता है, मीडिया के सामने मुंह न खोलने की शपथ ली जाती है, पार्टी का झंडा घर पर फहराने को दिया जाता है। वितरण के लिए लाल झंडों का वहां ढेर लगा था। माकपा की फौज ने बी.यू.पी.सी. के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की सूची बना ली है जिन्हें उस क्षेत्र में कभी भी न घुसने देने के लिए वे दृढ़ संकल्प हैं। हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में पड़े हैं। टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता निर्भय बनर्जी को धमकी दी कि तुम गरचकबेरिया क्यों जा रहे हो? तुम्हें कार सहित गायब कर दिया जाएगा। नंदीग्राम में जो कुछ हुआ उससे बंगाल के कलाकारों, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा विद्रोह कर उठी। अर्पणा सेन और ऋतुपर्ण घोष ने बंगाल सरकार का पुरस्कार लेने से मना कर दिया, फिल्म मेले का बहिष्कार कर दिया। १४ मार्च को कोलकाता में पहली बार वहां के प्रमुख कलाकर्मियों एवं बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में ५०,००० लोगों की विशाल भीड़ ने मौन प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में माकपा के कट्टर समर्थक मृणाल सेन भी सम्मिलित हुए। बंगाल के राज्यपाल और महात्मा गांधी के पौत्र श्री गोपाल गांधी ने ७०० शब्दों का एक तथ्यपूर्ण कड़ा वक्तव्य देकर माकपाई फासिज्म की निन्दा की। कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी बंगाल सरकार की कटु आलोचना की। माकपा के तीनों सहयोगी घटकों-भाकपा, आर.एस.पी. व फारवर्ड ब्लाक ने भी माकपा को इस लज्जाजनक कांड के लिए जिम्मेदार ठहराया। किन्तु माकपा नेतृत्व को इसकी कोई लज्जा नहीं है। वे अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, राज्यपाल की निंदा कर रहे हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बुद्धदेव ने कहा कि नंदीग्राम में हिंसा का आरंभ माओवादियों ने किया, किन्तु उनकी

सरकार के ही मुख्य सचिव ने कहा कि उस क्षेत्र में माओवादियों का कोई प्रमाण नहीं है। वाममोर्चे के तीनों घटक माकपा की आलोचना कर रहे हैं पर सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत निर्लज्जता से कह रहे हैं कि वाममोर्चे में कोई मतभेद नहीं है। बुद्धदेव पूरी घटना के लिये केन्द्र सरकार के सी.आर.पी.एफ. को समय से न भेजने का दोष दे रहे हैं, जबकि उन्होंने विजय अभियान पूरा होने तक सी.आर.पी.एफ. को वहां घुसने नहीं दिया। यदि बुद्धदेव का यह आरोप सही है कि उन्होंने २७ अक्तूबर को ही केन्द्र सरकार से सी.आर.पी.एफ. की मांग की थी, पर ५ नवम्बर तक केन्द्र उसे भेजने को तैयार नहीं था। सी. आर.पी.एफ. विजय आपरेशन आरंभ होने के काफी बाद आई। इसमें संदेह नहीं कि यदि केन्द्र ने अक्तूबर के अंत तक सी.आर.पी.एफ. भेज दी होती और उसने नंदीग्राम का चार्ज ले लिया होता तो स्थिति कुछ और बनती। क्या माकपा की हरमत ब्रिगेड सी.आर.पी.एफ. से टकराव मोल लेती? नंदीग्राम में इतना कुछ हो जाने पर भी सोनिया और मनमोहन सिंह केवल मौन ही नहीं तो वे परमाणु समझौते पर माकपा नेतृत्व का मान मनौव्वल में लगे हुए हैं। स्पष्ट ही उनकी मुख्य चिन्ता अपनी सरकार को बचाना है न कि माकपा के अत्याचार से नंदीग्राम की जनता की रक्षा करना। सोनिया-मनमोहन की इस कमजोरी से ही माकपा नेतृत्व अपने कुकर्म पर लज्जित होने के बजाय मूछों पर ताव दे रहा है।

■

वामपंथियों के किले में खून की होली

unhxke l: ykVdj] pnu fe=k

आतंक का यह सबसे डरावना चेहरा है। गांव दर गांव औरतों-बच्चों की आंखों से झांकता खौफ। जबान गूंगी हो चुकी है, बुजुर्गों की पसलियां उनकी किस्मत की तरह पढ़ी जा सकती हैं। यह वह जगह है जहां हर घर पर लाल झंडा लगाना जरूरी है। यही है नंदीग्राम-जहां टूटे हुए घरों के पीछे दुबके हैं डरे हुए लोग।

वे अब धान कटाई के लिए घर लौटना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें सीपीएम के स्थानीय दफ्तर जाकर एक 'सम्पूर्णपत्र' पर हस्ताक्षर करने होंगे मीडिया से बात न करने का वादा करना होगा और सीपीएम में शामिल होना होगा। उसके बाद उन्हें लाल झंडा देकर घर जाने की अनुमति मिलेगी।

मंगलवार को हम भी यहां थे। यानी राजग का प्रतिनिधिमंडल और मीडिया के लोग। नंदीग्राम में वैसे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लोग नहीं दिखते लेकिन स्थानीय निवासियों के चेहरे पर छाया डर यह बताने के लिए काफी है कि सीपीएम और उसका काडर सर्वव्यापी हैं। ज्यादातर घरों पर सीपीएम के लाल झंडे लगे हैं। कई झंडे हाल ही में टंगे हैं। कई जगहों पर हमें सड़क किनारे लाल झंडों के भारी बंडल दिखे। पता चला ये आगे के गांवों में लगेंगे। उन घरों में जिन पर सीपीएम के सशस्त्र कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते कब्जा किया। यहां हर राजनीतिक दल के दफ्तर गिरा दिए गए हैं। सड़क किनारे पड़े पार्टियों के बोर्ड और बैनर खुद अपनी दुर्दशा बता रहे हैं। नंदीग्राम के लोगों के लिए अपने घरों पर लाल झंडा लगाना अनिवार्य है। अगर

वे घर तृणमूल कांग्रेस के सहयोगी संगठन भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के हैं तब तो सीपीएम का यह हुक्म और भी सख्ती से लागू होता है। कमेटी के अधिकतर लोग सीपीएम के हथियारबंद कार्यकर्ताओं से डर कर यह इलाका छोड़ चुके हैं। लाल झंडा लगाने का यही आदेश जमात-उल-उलेमा-ए-हिंद और उन सभी दलों पर लागू होता है जिन्होंने नंदीग्राम में सीपीएम के जमीन कब्जे का विरोध किया था। बहुत पूछने पर ग्रामीण बस इतना बोलते हैं कि उन्हें सीपीएम और पुलिस दोनों से डर लगता है। उन्हें राहत देने पहुंची सीआरपीएफ को दो दिन बाद किसी तरह सीपीएम के प्रभाव क्षेत्रों में तो जाने दिया गया लेकिन उन इलाकों में इस बल के जवान अब भी नहीं जा सके हैं

जहां सर्वाधिक हिंसा हुई। सीपीएम के आतंक का एक और उदाहरण देखें। तृणमूल कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता किसान है जो सीपीएम के डर से गांव छोड़ गए थे। वे अब धान कटाई के लिए घर लौटना चाहते हें लेकिन उसके लिए उन्हें सीपीएम के स्थानीय दफ्तर जाकर एक 'सम्पूर्णपत्र' पर हस्ताक्षर करने होंगे, मीडिया से बात न करने का वादा करना होगा और सीपीएम में शामिल होना होगा। उसके बाद उन्हें लाल झंडा देकर घर जाने की अनुमति मिलेगी। अधिकारी पाड़ा के पास हमें एक बुजुर्ग से बात करने का मौका मिला। उससे पूछा गया, हमला किसने किया? जवाब था, 'मोटरसाइकिल सवार थे' किसी न फिर पूछा, 'क्या एम-पार्टी के लोग थे?' बुजुर्ग ने पहले तो कहा हां, फिर बोले मैंने कुछ नहीं देखा, आप जाइए यहां से एक मुस्लिम महिला सुषमा स्वराज का हाथ पकड़ कर रोने लगी। असके दो जवान लड़के लापता थे। पहले तो वह अपना नाम बता गई लेकिन फिर सहम गई। हमें बताया गया कि जानकारियां निकलवाने के लिए सीपीएम अपने कार्यकर्ताओं को रिर्पोटर बना कर भेजती है। नंदीग्राम हाई स्कूल में प्रतिनिधिमंडल पर पथराव भी हुआ। यहां हमें दस साल का एक लड़का गोपाल मिला जिसकी मां श्यामली को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। लालकृष्ण आडवाणी ने पूछा, 'श्यामली का दोष क्या था?' उन्हें बताया गया कि श्यामली शांति मार्च में भाग ले रही थी। गोपाल के पिता कई महीनों से लापता हैं। नंदीग्राम में लापता का मतलब है 'मृत' कमालपुर में हमें दो मंजिला मकान जमींदोज मिला। मकान मालिक मोहिबुल ने बताया कि मकान

सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि उसका भाई भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का नेता था। पिछले बृहस्पतिवार को सीपीएम के कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पहुंचा। औरतों और बच्चों को घर से बाहर किया (मर्द पहले ही घर छोड़कर भाग चुके थे) और घर को आग लगा दी। लेकिन हिंसा का यह नंगा नाच उम्मीद भी जगाता है। लोग डरे हैं, हारे नहीं। कुछ हिस्सों में जहां दूसरे दलों के समर्थकों की संख्या अधिक है, सीपीएम की निजी सेना 'हर्मद वाहिनी' भी उन्हें झुका नहीं सकी है। यह देख कर आश्चर्य हुआ कि एक राहत शिविर में हजार से अधिक लोग हमसे मिलने पहुंचे। इतिहास साक्षी है कि दमन कुछ ही समय तक लोगों को दबा पाता है, अंततः भावनाएं मुखर होती है। यही भावनाएं इतिहास बनाती हैं।

(लेखक राज्यसभा सदस्य और द पायनियर के संपादक है)

मार्क्सवाद की असलियत

ân;ukjk;.k nhf{kr

पश्चिम बंगाल अशांत है। आपातकाल जैसी स्थिति है। नंदीग्राम में चीत्कार है। मार्क्सवादी इस गांव को भारत का अंग नहीं मानते। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व बल को भी गांवों तक जाने से रोका है। मार्क्सवाद और मानवता का संघर्ष पुराना है। मार्क्सवादी वर्ग शत्रु के सफाए के विश्वासी हैं। वैसे मार्क्स और एंगेल्स की दृष्टि में किसान वर्ग शत्रु नहीं थे। दोनों ने जर्मनी के किसान संघर्ष की प्रशंसा की थी। मार्क्स ने १८४४ में किसान विद्रोह को जर्मन इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनवादी युद्ध बताया था। मार्क्स के अनुसार धर्म अफीम है। जर्मन किसान विद्रोह भी धार्मिक आस्था के कारण असफल हुआ। किसान और मजदूर किसी भी राष्ट्र के श्रमशील स्तंभ होते हैं। मार्क्स दोनों को मिलाकर जनवादी क्रांति के पक्षधर थे। चीन में माओ ने किसान लामबंदी के जरिए ही क्रांति की थी। लेकिन भारत के मार्क्सवादी और माओवादी किसान विरोधी हैं। माओवादियों से लड़ना आसान है। वे राज्य व्यवस्था और कानून के दायरे में हैं, लेकिन मार्क्सवादी केंद्र सरकार की संजीवनी हैं। पश्चिम बंगाल में वे स्वयं सरकार हैं।

कानून एवं व्यवस्था राज्यों का मसला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार का राजनीतिक तंत्र स्वयं ही कानून एवं व्यवस्था पर हमलावर है। पुलिस लाचार है। पश्चिम बंगाल में पुलिस का कामरेडीकरण हुआ है। सत्ताधारी दल द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने का कोई तंत्र नहीं है, स्थानीय पुलिस सरकारी निर्देश मानने को बाध्य है। अन्य राज्यों में □ी ऐसी ही स्थितियां अक्सर आती हैं।

यहां पुलिस और माकपा कार्यकर्ता की अलग पहचान नहीं है। वे पुलिस संरक्षण में कत्ल करते हैं,पुलिस उनके संरक्षण में हिंसा करती है।

दुनिया की सारी संस्कृतियां और सभ्यताएं मनुष्य केंद्रित हैं। मनुष्य जीवन की कीमत पर कोई भी सभ्यता, राज व्यवस्था या विचारधारा नहीं चलती। हिंसा हर हाल में घृणित है, लेकिन मार्क्सवादी हिंसा को निंदनीय नहीं मानते। पश्चिम बंगाल में बदले की कार्रवाई जारी है। मार्क्स पूंजीवाद को शत्रु मानते थे, किसान-मजदूर को अपनी लड़ाई का प्रमुख सैनिक मानते थे। माकपा सरकार ने किसानों की खेती छीनकर उद्योगपति को दी है। हालात ये हैं कि किसान धरना-प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगें रखने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं। किसानों की लोकतांत्रिक कार्रवाई का समर्थन करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ममता बनर्जी भी माकपा के निशाने पर हैं। राज्यपाल ने चिंता व्यक्त की सो वे भी माकपा के निशाने पर हैं। यहां मानवाधिकार आयोग ठेंगे पर है। मार्क्सवाद मानवाधिकार नहीं मानता। केंद्रीय संसदीय मंत्री भी रो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के परिवार की सुरक्षा के लिए डीजीपी से आग्रह किया। बावजूद इसके उसका घर तहस-नहस हुआ। घरवाले अपहृत हुए। मारे-पीटे गए। पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उनकी भी पिटाई हुई। मार्क्स विचारधारा बुद्धिजीवियों को पूंजीपतियों का पिछलग्गू मानती है। मार्क्सवाद की कलई खुल गई। जनवाद की खोल में छुपा पूंजीवाद प्रकट हो गया। सत्ता के क्रूर आचरण से वाम विचार की असलियत सामने आई। मार्क्सवादी इतिहासकार, आलोचक और कथित चिंतक हलकान हैं। फिल्मकार अपर्णा सेन ने 'वाम नैतिक श्रेष्ठता' पर सवाल उठाते हुए किसान उत्पीड़न को तानाशाही बताया है। कांग्रेस अपनी सरकार की चिंता में है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मार्क्सवादी हिंसा पर सीधा हमला किया है। इतिहासकार सुमित सरकार की टिप्पणी है कि उनका सिर शर्म से झुक गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के हिस्सेदार घटक दल भी खासे नाराज हैं। मंत्री त्यागपत्र की धमकी दे रहे हैं। बावजूद इसके माकपा आक्रामक है।

माकपा महासचिव प्रकाश करात ने राज्य सरकार व माकपा

कार्यकर्ताओं की कार्रवाई को जायज ठहराया है। भारत के संघीय ढांचे पर प्रश्नचिह्न है। कानून एवं व्यवस्था राज्यों का मसला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार का राजनीतिक तंत्र स्वयं ही कानून एवं व्यवस्था पर हमलावर है। पुलिस लाचार है। पश्चिम बंगाल में पुलिस का कामरेडीकरण हुआ है। सत्ताधारी दल द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने का कोई तंत्र नहीं है, स्थानीय पुलिस सरकारी निर्देश मानने को बाध्य है। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थितियां अक्सर आती हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में तीन वर्ष पहले हुए भीषण दंगों में ऐसी ही भयावह परिस्थिति थी। पुलिस अधिकारियों के सामने हिंसा थी, आगजनी थी। अनेक पुलिसजनों ने मीडिया के सामने बताया कि वे मजबूर थे। सभी राज्य भारतीय राष्ट्र-राज्य के अंगभूत घटक हैं। राज्य संप्रभु नहीं हैं। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में केंद्र असली शासक नहीं है। किसी भी शासन का मुख्य काम जनसुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था है। भारत में यह काम राज्यों के पास है, लेकिन तमाम राज्यों के क्षत्रप अपने-अपने क्षेत्रों के अत्याचारी जमींदार जैसा आचरण करते हैं। वे राज्यों को राष्ट्र से पृथक सत्ता बनाते हैं। केंद्र कार्रवाई नहीं करता।

पश्चिम बंगाल की सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य निर्वहन में असफल हो गई है। ममता बनर्जी के अनुसार सैकड़ों हत्याएं हुई हैं। प्रकाश करात के अनुसार २८ माकपाई मारे गए हैं। स्थिति आइने की तरह साफ है। राज्य का संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गया है, लेकिन सरकार बर्खास्तगी के लिए राजनीतिक अनुकूलता और इच्छाशक्ति चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार वाम दलों के बगैर अल्पमत में है। वाम दल अपने समर्थन की कीमत हर माह वसूल करते हैं। वे सरकार हिलाते हैं, गिराने की स्थिति में लाते हैं। कांग्रेस रिरियाती है, उनकी बातें मानती है। वे अल्पकालिक जीवनदान देते है। विद्वान प्रधानमंत्री भी मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल में वाम दलों का शासन है। पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है। यह वाम दलों की निजी जागीर नहीं है, लेकिन केंद्र उनसे डरता है। सरकार बर्खास्तगी लायक है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते बर्खास्तगी असंभव है। तब क्षेत्रीय आपातकाल क्यों नहीं लागू किया जाता? संविधान के अनुच्छेद ३५२ में व्यवस्था है कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के

कारण यदि भारत या उसके राज्य के किसी हिस्से की सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। बेशक ऐसी उद्घोषणा भी संसद में अनुमोदन के लिए आएगी। सशस्त्र विद्रोह की बात वे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। ऐसी आपात उद्घोषणा के जरिए केंद्र स्वयं सारी प्रशासनिक कार्रवाइयों के संचालन में निर्देश देने का अधिकारी होगा। आखिरकार केंद्र ऐसा साहस क्यों नहीं जुटाता? जाहिर है कि कांग्रेस और वाम दलों के बीच एक-दूसरे के अपराध न देखने का समझौता है।

पश्चिम बंगाल की हिंसा, अराजकता ने कई वैचारिक सवाल भी उठाए हैं। मसलन क्या मार्क्सवाद का अंत हो गया? कहीं नंदीग्राम का पूंजीवादपोषक किसानहंता फैसला भी मार्क्सवादियों की ऐतिहासिक भूल ही तो नहीं है? मार्क्सवादी छोटी-मोटी गलतियां नहीं करते। वे ऐतिहासिक भूल ही करते हैं। अमर्त्य सेन ने उपजाऊ कृषि भूमि उद्योगों को देने की नीति का विरोध किया है। क्या मार्क्सवादी गरीब किसानों को मारकर कोई नई जनक्रांति लाने की तैयारी में हैं? या परमाणु करार को सिर्फ अमेरिकी होने के कारण ही बेजा बताने वाले वामपंथी अमेरिकी भूमंडलीकरण की गिरफ्त में हैं? या सारी दुनिया से खारिज मार्क्सवादी खोटा सिक्का भारत में भी खोटे सिक्के के रूप में पहचान लिया गया है? भारत में मार्क्सवाद यों भी नहीं चलता, पश्चिम बंगाल में भी हंसिया और हथौड़ा हिंसा के जरिए ही शासन करता है। मार्क्सवादी इतिहासकार बताएं कि नंदीग्राम की शव यात्राएं मार्क्सवाद की भी शव यात्राएं क्यों नहीं हैं?

(लेखक उप्र सरकार के पूर्व मंत्री है)

नंदीग्राम में मजार बनेगी माकपा की

çHkkr >k

'नंदीग्राम' सीपीएम के आतंक का एक ट्रेलर है। गत तीस वर्षों से यहां पर जो कुछ हो रहा है, वह ऐसे ही खूनी आतंक के बल पर। सत्ता जनता के मतों के बजाए सीपीएम के ''खूनी गुंडों'' के बंदूक के बुलैट के भय से यहां बैलेट यानि इलेक्ट्रॉनिक मशीन तक बदल दिए जाते हैं। यहां की पुलिस, यहां का प्रशासन पूरी तरह 'लाल कैडर' में तब्दील हो चुका है। जानकारी लेने पर वे कहते हैं कि यह हमारी मजबूरी है। यह विडम्बना नहीं तो और क्या कि जब सारा देश दीपावली की रात दिए जला रहे थे, तब नंदी ग्राम में माकपा के कार्यकर्ता उनके घर जला रहे थे, जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते हैं।

लोकप्रिय एवं भद्र लोगों की सरकार द्वारा गत ११ महीनों से नंदीग्राम में जिस तरह का सरकारी आतंक मचाया जा रहा है, वह इतना ही समझने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल में सच में ममता बनर्जी बत्तीस दातों के बीच रहकर जिस तरह काम कर रही

देश की 'महिला राष्ट्रपति' क्या हृदय विहीन हो चुकी है। क्या वह स्वयं को राष्ट्रपति चुनावों में प्राप्त मतों का कर्ज उतार रही है?

वृंदा करात के इस बयान पर मुकदम क्यों नहीं दर्ज हुआ? जिसमें उन्होंने कहा कि ''हिंसा एक वैध रास्ता है?'' क्या एक सांसद अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को इस आशय की छूट दे सकती है? क्या वृंदा करात यह नहीं जानती कि खुले आम हिंसा का आह्वान संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध है?

है यह सराहनीय ही नहीं बल्कि संघर्ष के राजनैतिक संस्कृति की एक बेजोड़ मिसाल है। ''मौत के बीच'' संघर्ष करना सहज नहीं है। ममता को पश्चिम बंगाल की जनता की ममता चाहिए। 'सीपीएम' के दिन लदने वाले हैं। ''नंदीग्राम'' सच में नंद ग्राम है। यहीं से कृष्णावतार होगा और कंसरूपी आततायी सीपीएम के नाश का सिलसिला शुरु होगा। यह बात तो तय हो गई नंदीग्राम में केमिकल हब बने या न बने पर आने वाले दिनों में सीपीएम की मजार तो जरूर बनेगी।

पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, वहां की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बाद में पहले सीपीएम कैडर का अंग है। नंदीग्राम में क्या नहीं हुआ? गोली चली। लोग मरे। मरे परिजनों को राहत के बजाए उनके घरवालों पर आतंक। आतंक का ऐसा विकृत रूप जहां १२-१२ साल की कुवांरियों का सीपीएम के गुंडों द्वारा जबरिया कौमार्य भंग किया गया। यह कैसा भारत? यह कैसा वामपंथ? यह कैसा साम्यवाद? यह कैसी धर्मनिरपेक्षता? देश चकित है। लोकतंत्र सिहर गया है। पश्चिम बंगाल के कामरेड यह भूल गए कि आततायियों का भी एक दिन अंत होता है। मुख्यमंत्री बुद्धदेव का यह कहना कि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ सीपीएम का कैडर भी हूं। यह कौन सी भाषा है?

सीपीएम के विरुद्ध सोनिया गांधी की चुप्पी। मनमोहन सिंह का मौन रहना। इतना ही नहीं, कांग्रेस अधिवेशन जिसे ''जश्ने राहुल'' कहा गया, में नंदीग्राम की चर्चा तक नहीं होना किस बात की ओर इंगित करता है? चोर-चोर मोसेरे भाई। संसद के भीतर सांसदों को जोर से बोलने और डपटने और क्रोधित हो जाने वाले लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की चुप्पी कोई समझ नहीं पा रहा है।

माकपा पोलित ब्यूरो की मेम्बर वृंदा कारत, सुहासिनी अली एवं सरला महेश्वरी चुप नहीं हैं, उल्टे ममता बनर्जी पर माओवादी से सांठ-गांठ का आरोप लगा रही हैं। कौन विश्वास करेगा? राजनैतिक नौटंकी करने में माहिर ये 'कामरेडियना' नंदीग्राम की घटना पर सीपीएम के गुंडों द्वारा किए गए गुंडई की पैरवी कर रही है। शायद शर्म को भी शर्म आ रही होगी। पति-पत्नी दोनों अपनी विचारधारा के बुद्धिजीवियों को कोस रही हैं। क्यों? वे सच न बोलें। इतने दिन से चुप थे। अब क्या करें? अब भी चुप रहें।

आतंक का घड़ा अब फूट चुका है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। वहां पूरी तौर पर हिटलरशाही है। फासीवाद और नाजीवाद का नंगा नाच, वहां सीपीएम सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। देश की सभी पार्टियां चुप हैं। नंदीग्राम में मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार करने की घटना ने सीपीएम के धर्मनिरपेक्ष चेहरे पर स्वयं कोलतार पोत दिया है।

बुद्धदेव भट्टाचार्य को जवाब देना होगा।

- पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और चौबीस परगना से हथियार बंद सीपीएम के कार्यकर्ता नंदीग्राम क्यों बुलाए गए?
- वहां सीपीएम कार्यकर्ताओं के घरों में असले क्यों रखे गए?
- क्या सत्ता का आवरण ऐसा होना चाहिए?
- मुस्लिम परिवारों के घर जला दिए गए। किसने जलाए इनके घर? किसने उजाड़ी इनकी बस्तियां?
- महिलाओं की इज्जत लूटने वाले कौन लोग थे?
- पुलिस की भूमिका 'कानून' की थी या कामरेड की?
- सरकार प्रायोजित आतंकवाद की योजना कहां बनाई गई?
- धीरे-धीरे जो रिपोर्ट आ रही है, वह खौफनाक और शर्मशार करने वाली है?
- राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी के सात सौ शब्दों वाले पत्र और बयान में जो कहा गया है, कामरेड उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?
- कांग्रेस इस सारे मामले पर चुप क्यों हैं?
- देश की 'महिला राष्ट्रपति' क्या हृदय विहीन हो चुकी है। क्या वह स्वयं को राष्ट्रपति चुनावों में प्राप्त मतों का कर्ज उतार रही है?
- वृंदा करात के इस बयान पर मुकदम क्यों नहीं दर्ज हुआ? जिसमें उन्होंने कहा कि ''हिंसा एक वैध रास्ता है?'' क्या एक सांसद अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को इस आशय की छूट दे सकती है? क्या वृंदा करात यह नहीं जानती कि खुले आम हिंसा का आह्वान संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध है?
- राज्यपाल को जिस तरह से आरोपित किया जा रहा है, क्या माकपा को यह सब करना चाहिए?
- प्रणव मुकर्जी और प्रिय रंजनदास मुंशी को क्या यह समझ में नहीं

आ रहा कि वे अपनी नेता मैडम को समझाएं।

माकपा खुश है कि उसने नंदीग्राम पर कब्जा करा लिया। 'नंदीग्राम' की इस घटना ने माकपा के दरिंदगी भरा चेहरा देश के सामने ला खड़ा किया।

वैसे तो वामपंथियों का इतिहास फरेबी का रहा है। वे कभी भी देश हित में खड़े नहीं हुए। देश के उन लोगों को अब वामपंथ समझ में आ गया होगा, जो 'टीवी' पर शब्दों के भ्रमजाल से देशवासियों को भ्रमित करते हैं।

गुजरात पर गला फाड़-फाड़कर चिल्लाने वाले 'लालू' नंदीग्राम क्यों नहीं जा रहे? मुलारयम सिंह क्या मायावती के बिछाए जाल में इतना फंस गए हैं कि वे इस अन्याय को मौन देख रहे हैं? आखिर क्या हो गया है? चन्द्रबाबू नायडू और जयललिता को? क्या करुणानिधि इतने गिर गए हैं कि वे नंदीग्राम की निंदा तक नहीं कर सकते?

देश ने अभी नंदीग्राम की मात्र दस से पन्द्रह फीसदी सच्चाई देखी है। क्योंकि वहीं पत्रकारों को भी मौत का भय है। फिर भी मीडया की बधाई की पात्र है, जिसने कम से कम सच को निगलने के बजाए उगलने की कोशिश की।

वैसे यह बात भी तय है कि प्रकाश कारत चाहे जितनी लाख सफाई दे, उन्हें उनकी पार्टी में पश्चिम बंगाल और केरल में कौन पूछ रहा है? वहां पर भी पार्टी दो भागों में बंटी है। पश्चिम बंगाल वाले तो प्रकाश और वृंदा कारत को तोता-मैना की उपाधि देते हैं।

'माकपा' का यह घिनौना चेहरा देश के सामने आ गया है। पश्चिम बंगल के साहसी लोगों को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की भूमिका में आना होगा। 'पश्चिम बंगाल' आहुति मांग रहा है। अतः पश्चिम बंगाल में आवश्यकता है देश को स्वयं पहुंचने की। भारत के प्रत्येक राज्य को वहां जाकर देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल सरकार है या आतंकी। पश्चिम बंगाल की जनता को समूचे देश का साहस चाहिए। देश को पश्चिम बंगाल के पीछे खड़ा होना होगा। यदि ऐसा हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब 'वामपंथ' अपने सबसे मजबूत कहे जाने वाले गढ़ में ही दम न तोड़ दे।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं)

बंगाल के बदलते संकेत

Loiu nklxIrk

दीवाली के एक पखवाड़े पहले कोलकाता ने वैश्विक पूंजीवाद की हृदयस्थली से आए कुछ अप्रत्याशित मेहमानों की मेजबानी की। वे दो कारणों से कोलकाता आए। पहला तो एक ऐसे राज्य का जायजा लेना जो एक कम्युनिस्ट पार्टी को शासन के लिए लगातार चुन रहा है। दूसरे, वे उस मुख्यमंत्री की रोचक कहानी का भी अनुभव करना चाहते थे जिसने बाजार अर्थव्यवस्था का उतना ही दिली स्वागत किया है जितना कभी उसे साम्यवाद पसंद रहा होगा। दोनों ही मामलों में मेहमानों के लिए संतुष्ट होकर लौटने के पर्याप्त कारण थे। आज का कोलकाता लोहे के पर्दो के पीछे छिपे गुमसुम प्रांतीय शहर की अपनी पहचान से कोसों दूर है। इसकी सतह पर आधुनिकता के सभी प्रतीक चमचमा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल के भीतर अतुल्य भारत का अभिन्न अंग बनने की ज्वाला धधक रही है। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ऐसे व्यवहारिक राजनेता की अपनी प्रतिष्ठा के साथ न्याय ही किया है जिसके पास पश्चिम बंगाल के लिए एक अंतर्दृष्टि है। एक प्रतिष्ठित मेहमान की बड़ी सटीक टिप्पणी थी-अगर आपने मुझे चेताया नहीं होता तो मैं यह अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि वह एक कम्युनिस्ट हैं। दुर्भाग्य से राजनीति में एक सप्ताह लंबा समय है। यदि वही मेहमान काली पूजा के बाद फिर कोलकाता लौटते तो उन्हें दुनिया बदली नजर आती। उन्हें माकपा और उसके मुख्यमंत्री के प्रति शहर गुस्से से भरा नजर आता। उन्हें अहसास होता कि हालिया बंद ने आम जनजीवन को कितना कष्टप्रद बना दिया। टीवी खोलते ही उन्हें स्थानीय शख्सियतें मुख्यमंत्री के लिए बुरा-भला कहती दिखाई देतीं। उनकी तुलना नरेन्द्र मोदी से की जा रही है, जो देश में कुछ लोगों के लिए सबसे बड़े फासिस्ट बन गए हैं। उन्हीं अतिथियों को कतिपय स्वयंभू बुद्धिजीवी माकपा को आतंकवादी

संगठन बताते भी मिल जाएंगे। बेशक पश्चिम बंगाल बदलाव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि नंदीग्राम में पिछले कुछ दिनों की घटनाएं क्या उस शासन के खिलाफ बहुतायत दुःखी और संतप्त लोगों के असंतोष की चरम अभिव्यक्ति हैं जिसे अब असहिष्णु और धृष्ट माना जा रहा है? इसके कुछ हफ्ते पहले ही रिजवानुर रहमान की हत्या के मामले में मध्यम वर्ग की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। **अब इस संकेत के मजबूत आधार हैं कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के ३० वर्ष के अबाधित दबदबे के बाद सत्ता विरोधी भावना जड़ें जमा रही है। पश्चिम बंगाल में माकपा के उपचार और दूसरे सामान्य राज्यों में सरकारों की कार्रवाई में जो अंतर है वह है नैतिक श्रेष्ठता का अहंकार।** आर्थिक कुप्रबंधन के इतने लंबे घटिया रिकार्ड वाली किसी भी सरकार को उपहास का विषय बनाया जाता, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में ऐसा नहीं हुआ। वहां ज्योति बसु लंबे समय तक राजनीतिक दूरदर्शिता के प्रतीक बने रहे। उनकी २३ वर्ष की विरासत के पहलू थे-शिक्षा, मूलभूत ढांचे और औद्योगिक माहौल का विध्वंस तथा पेशेवर वर्ग का पलायन। उनके अधीन पश्चिम बंगाल बाहर निकल भागने का अच्छा स्थान बन गया। उनके उत्तराधिकारी बुद्धदेव भट्टाचार्य उनसे अलग काफी साहसी साबित हुए। बुद्धदेव उन गिने-चुने भारतीय कम्युनिस्टों में हैं जिन्होंने सोवियत संघ के पतन में मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था की व्यापक असफलता देखी। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे ज्योति बसु की विरासत को उलटने का काम शुरू किया। उन्होंने निजी निवेशकों को आकर्षित किया, आर्थिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में जीवंत कोलकाता के महत्व को अनुभूत किया और एक राजनीतिक संस्कृति के निरर्थक महिमामंडन को कम करने की कोशिश की। बुद्धदेव यह समझने में सफल रहे कि शेष भारत के आर्थिक उदय के पीछे कौन से कारण हैं और वे कारण पश्चिम बंगाल में क्यों काम नहीं कर सकते। स्टालिनवाद के संकीर्ण चश्मे से देखें तो बुद्धदेव हो सकता है कि गैर-वामपंथी तक नजर आएं, लेकिन जब चीन भी मुक्त बाजार का प्रबल समर्थक बन रहा है तब बुद्धदेव का यह कदम कोई घृणित कार्य तो नहीं है। उन्होंने आर्थिक विकास के साथ जीवंत पूंजीवाद के प्रतीकों से जुड़ने में कुछ

भी गलत नहीं माना। उनका तर्क बेहद साधारण है–यदि पश्चिम बंगाल को भारत के आर्थिक उदय का सहयोगी बनना है तो उसे आधुनिक पूंजीवाद के तौर-तरीकों को स्वीकार करना होगा। सिंगुर और नंदीग्राम में ग्रामीणों का भूमि अधिग्रहण पर विरोध वस्तुतः भय और अनिश्चितता पर आधारित था। उनके विरोध से सावधानी, संवेदनशीलता और यहां तक कि उदारता से निपटा जाना चाहिए था, लेकिन बुद्धदेव जल्दी में थे और इस जल्दबाजी को माकपा की स्थानीय इकाइयों ने अराजकता में बदल दिया। एकाधिकारी सत्ता के अहंकार में उन्होंने उस एकमात्र तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की जो उन्हें पता है–ताकत का अपने ढंग से इस्तेमाल। अतीत में इस रवैये ने हमेशा उनकी इच्छा पूरी की है, लेकिन आज के दौर में यह संभव नहीं था। अपने जाने पहचाने राजनीतिक विरोधियों के अतिरिक्त माकपा को अब उस वैचारिक अधिष्ठान से भी लड़ना पड़ रहा है जो उसका अब तक सहयोगी रहा है। आज माकपा की कार्रवाई को लेकर वैचारिक अधिष्ठान दो भागों में बंटा नजर आ रहा है। यह वामपंथी ही थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में १९६७ में खूनी बदले की संस्कृति आरंभ की। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल का बौद्धिक वर्ग वामपंथियों का समर्थक है। नंदीग्राम के घटनाक्रम का माकपा पर कोई प्रभाव पड़े या न पड़े, लेकिन पश्चिम बंगाल पर इसके विनाशकारी परिणाम अवश्य होंगे। राज्य के पुनर्जागरण का दृष्टिकोण विवाद के गहरे समंदर में फंस गया है। पश्चिम बंगाल में बदलाव की जरूरत है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति में बदलाव अपरिहार्य है, लेकिन इसके लिए पिछले कई दशकों की प्रबल बौद्धिक विरासत को निर्णायक तरीके से खारिज करना होगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

मार्क्सवाद का बंदीग्राम

&onirki ofnd

नंदीग्राम मार्क्सवाद का बंदीग्राम बन गया है। स्तालिन और माओ ने कार्ल मार्क्स को कठघरे में वैसे कभी खड़ा नहीं किया, जैसे हमारे मार्क्सवादियों ने कर दिया है। स्तालिन और माओं ने सर्वहारा की ओर से कुलकों और सामंतों पर प्रहार किया, लेकिन हमारे मार्क्सवादियों ने सर्वहाराओं के बीच ही गृह-युद्ध छिड़वा दिया है। सर्वहारा ही सर्वहारा का खून बहाए, क्या यह मार्क्सवाद की उलट-पराकाष्ठा नहीं है? नंदीग्राम में मारे गए दर्जनों लोग कौन हैं? क्या वे पूंजीपति हैं, सामंत हैं, बुर्जुग हैं, शोषक हैं? वे चाहे माकपा के लोग हों, माओवादी हों, भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के स्वयंसेवक हों, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, पुलिस वाले हों – उनमें से कोई भी शोषक वर्ग का सदस्य नहीं है। इन शोषितों का खून बहाकर हमारे मार्क्सवादियों ने आज की राजनीति में कार्ल मार्क्स को कितने मार्क्स दिलवाए हैं? आज मार्क्स को शून्य 'मार्क्स' मिल रहे हैं। महान विचारक मार्क्स की ऐसी दुर्गति करने वाले हमारे मार्क्सवादी क्या अब खुद बच जाएंगे। उन्हें कल्पना नहीं है कि उनकी कितनी दुर्गति होगी।

तीन दशक में पहली बार बंगाल से मार्क्सवादियों के उच्छेद का बिगुल बज गया है। चुनाव में जब उच्छेद होगा, तब होगा, लेकिन अभी ही ऐसी स्थिति बन गई है कि केंद्र में भाजपा-गठबंधन होता तो कोलकाता की सरकार बर्खास्त हो जाती। राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को दो-दो बार खुला हस्तक्षेप करना पड़ा, यह मामूली बात नहीं है। स्वयं मार्क्सवादी गठबंधन के घटक बगावत की मुद्रा में है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री क्षिति गोस्वामी ने इस्तीफे की पेशकश की है। भाकपा और फारवर्ड ब्लॉक के नेता भी नंदीग्राम की हिंसा की निंदा कर रहे हैं। अनेक मार्क्सवादी नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टियों के रवैए पर मौन जरूर हैं, लेकिन अत्यंत क्षुब्ध हैं।

अगर बंगाल में कोई सशक्त विकल्प होता तो बंगाल के सत्तारूढ़ दलों का आज दिवाला पिट जाता, लेकिन जहां तक बंगाल की जनता का सवाल है, उसकी नजर में मार्क्सवादियों की कीमत बहुत गिर चुकी है, वरना क्या अड़तालीस घंटे का बंद वैसा सफल होता, जैसा कि अभी हुआ है?

मई २००६ के विधानसभा चुनाव में २९४ में से २३५ सीटें जीतने वाले बुद्धदेव भट्टाचार्य इतनी जल्दी फीकें क्यों पड़ गए हैं? वे इतने असहाय और निरूपाय क्यों दिखाई पड़ रहे है? बुरी तरह चुनाव हारने वाली तृणमूल नेता ममता बनर्जी अचानक बंगाली जनमत पर हावी क्यों होती जा रही हैं? शेर की तरह दहाड़ने वाले माकपा के केंद्रीय नेता अब मेमनों की तरह क्यों मिमिया रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ है कि परमाणु सौदे पर हमारे मार्क्सवादी शीर्षासन की मुद्रा में आ गए हैं? आखिर क्या वजह है कि उन्होंने केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से बात करने की ढील दे दी है?

इस ढील का मूल कारण वह शिकंजा है, जो नंदीग्राम ने मार्क्सवादियों के गले पर अचानक कस दिया है। यह कांग्रेस की मेहरबानी है कि वह भट्टाचार्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर रही है। अगर वह बर्खास्त कर दे और इस समय चुनाव हो जाएं तो मार्क्सवादियों को पता है कि बंगाल की जनता उन्हें नंदीग्राम में बंद कर देगी। कोलकाता छोड़कर उन्हें नंदीग्राम में बंद कर देगी। कोलकाता छोड़ कर उन्हें नंदीग्राम के बंदीग्राम में निवास करना पड़ेगा। अब तक चुनाव का डर केवल कांग्रेस को था, अब उसकी दहशत मार्क्सवादियों के दिल में भी बैठ गई है। इसीलिए अब दोनों एक-दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। दोनों जुबान जरूर चलाएंगे, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर गठबंधन का रथ भी हांकते रहेंगे। अब कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा।

इस अधर के लटकाव का ज्यादा नुकसान भाकपा को भुगतना होगा, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही गिड़गिड़ा रहीं थी, लेकिन मार्क्सवादी निरंतर गुर्राते रहे थे। अब वे बंगाल में ही नहीं, सारे भारत में मसखरों की तरह दिखाई पड़ेंगे। सत्ता का गणित शेर को कैसे भेड़ बना देता है, इस कहावत को मार्क्सवादी चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि उनमें उतना ही और वैसा ही क्षीण नैतिक

साहस है, जैसा कि अन्य बुर्जुआ पार्टियों में है। नंदीग्राम ने मार्क्सवादी पार्टियों में है। नंदीग्राम ने मार्क्सवादी पार्टियों में है। नंदीग्राम ने मार्क्सवादी पार्टियों के नाम पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। वे अपने आपको बंगाल की क्षेत्रीय पार्टियां घोषित क्यों नहीं कर देतीं? अपने सत्ता-सुख के लिए वे मार्क्सवाद को चूना क्यों लगा रही हैं?

इस तरह के असुविधाजनक सवाल मार्क्सवादियों से कांग्रेस क्यों करेगी? कांग्रेस को कोई लाग-लपेट नहीं है। वह पूरी तरह सत्तावादी और सुविधावादी पार्टी है। नंदीग्राम उसके लिए अचानक आसमान से फरिश्ते की तरह उतरा है। वह गदगद है। वह अब तृणमूल से भी हाथ मिला लेगी। वह इसलिए भी गदगद है कि नंदीग्रम, भारत के 'सबसे बड़े भक्त' जॉर्ज बुश की मनोकामना भी पूरी करेगा। अगर परमाणु सौदे पर हमारे कॉमरेड मौन साध लें तो क्या पता वाइट हाउस में बुश नंदी-पूजा ही शुरू करवा दें। किसे पता था कि नंदीग्राम जैसा एक स्थानीय मसला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इतना महत्वपूर्ण निणार्यक तत्व बन जाएगा।

अगर सिंगुर और नंदीग्राम के हादसे नहीं होते तो दुनिया को यह भी शायद ही पता चलता है कि हमारे छोटे मियां तो बड़े मियां से भी आगे चल रहे हैं। साम्यवाद के सबसे बड़े मियां आजकल चीन ही है। जैसे औद्योगीकरण के खतिर चीनी कॉमरेडों ने शंघाई और शेन-जेन की पुरानी बस्तियों को एक ही झटके में उखाड़ दिया, वैसे ही हमारे कॉमरेड भी भारतीय और इंडोनेशियाई पूंजीपतियों की खातिर बंगाली किसानों को अपनी जमीन से बेदखल करना चाहते थे। वे चीनियों से भी आगे निकल रहे थे, क्योंकि चीनी कॉमरेड यही काम चीनी राज्य के लिए कर रहे थे। लेकिन हमारे कॉमरेड यही काम देसी और विदेशी पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा चीन विस्थापितों के लिए समुचित वैकल्पिक सुविधा और उचित मुआवजे की व्यवस्था करता है जबकि हमारे यहां शोषितों के जीवन-मरण का यह प्रश्न अभी तक कोरी बहस का मुद्दा बना हुआ है।

माकपा की सराहना तो तब होती जब वह इस समस्या का कोई आदर्श हल सबके सामने लाती। अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करते। तब तो माना जाता कि शोषितों-पीड़ितों के लिए मार्क्सवादियों के दिल में कुछ दर्द है। अब सारी योजना को वापस लेने का क्या

फायदा? उसने यही सिद्ध किया कि आपने जन-आक्रोश के आगे घुटने टेक दिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि मार्क्सवादियों को यह भी ध्यान नहीं रहा कि वे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंग है। वे किसी चीनी या सोवियत व्यवस्था में सरकार नहीं चला रहे हैं।

लोकशाही और पार्टीशाही में कितना फर्क है, इस तथ्य को मार्क्सवादी अब भली-भांति समझ गए होंगे। इस तथ्य का एक आनुषंगिक निष्कर्ष यह भी है कि भारत का सौभाग्य है कि मार्क्सवादियों का राज्य केवल बंगाल और केरल जैसे प्रदेशों में ही कायम हुआ, सारे भारत में नहीं हुआ। अगर हो जाता तो क्या होता, इसकी कल्पना की जा सकती है।

मार्क्सवादियों ने अपने आचरण से कई बुनियादी सवाल भी खड़े कर दिए। जैसे, क्या राज्य और पार्टी में कोई फर्क नहीं है? क्या दोनों एक-दूसरे के पर्याय है? नंदीग्राम के मकानों और भूखंडों से माकपा कार्यकर्ताओं को बेदखल करके अगर विरोधियों ने उन पर कब्जा कर लिया था तो राजधर्म क्या कहता है? अत्याचार ग्रस्त लोगों को न्याय दिलाइए। कोई फर्क मत कीजिए। वे चाहे किसी भी पार्टी या जाति या मजहब के हों। सरकार को निष्पक्ष रह कर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया? आंख मींच ली और पार्टी काडर को इशारा कर दिया। माकपा कार्यकर्ता नंदीग्राम पर टूट पड़े। हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने हत्या की, लूटपाट मचाई, बलात्कार किया और कब्जे किए। पुलिस खड़ी-खड़ी देखती रही।

केंद्र ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस भिजवाई, लेकिन बहुत देर से। नंदीग्राम पहुंची हुई पुलिस बाहर ही खड़ी कर दी गई ताकि वह माकपा कार्यकर्ताओं के जन-युद्ध में बाधा न पहुंचाए। अब ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य संतुष्ट है कि नंदीग्राम में शांति लौट रही है। क्या यह शांति वैसी ही नहीं है, जैसी कि गुजरात में है? कैसी घृणित जुगलबंदी है, संप्रदायवाद और सेकुलरवाद में? इससे बढ़कर गैर-जिम्मेदाराना बयान कोई मुख्यमंत्री क्या दे सकता है कि नंदीग्राम के लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से मिला है। यह तो राजधर्म के पूर्ण तिरोधान की घोषणा ही है।

लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि आप पहले सरकार और पार्टी को एकमेक कर दें और फिर यह मान बैठें कि पार्टी ही जनता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य कृपया यह बताएं कि वे पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ माकपा के हैं? इसमें शक नहीं कि नंदीग्राम के पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को अकर्मण्यता का नकाब पहनने के लिए मजबूर किया हो, लेकिन क्या चुनी हुई सरकार को खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आखिर वह किसके प्रति जवाबदेह है? उसका सर्वोच्च स्वामी कौन है? पार्टी कार्यकर्ता या जनता? जनता को नाराज करके नेता कहां जाएंगे? आखिर चुनाव की अग्नि परीक्षा में तो उन्हें उतरना ही पड़ेगा।

प्रदेश के कुल निवासियों के पंद्रह-बीस प्रतिशत वोट ही काफी होते हैं, चुनाव जीतने के लिए। सिर्फ वोटों की संख्या तय नहीं करती कि आप लोकतांत्रिक हैं। लोकतांत्रिक नैतिकता लोगों की संख्या से परे की चीज है। उसका निवास लोकमत में है, लोक-कल्याण में है, लोकप्रियता में है। क्या माकपा इस कसौटी पर खरी उतर रही है?

इस कसौटी पर मार्क्सवादी खोटे सिद्ध हो रहे हैं। दलबंदी से अलग रहने वाली आम जनता के गुस्से की बात जाने दें, जो विद्वान, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार लोग वामपंथी या उनके सहयात्री माने जाते हैं। आज उनकी राय क्या है? महाश्वेता देवी, अपर्णा सेन, ऋतुपर्ण घोष जैसे लोग किसी दक्षिणपंथी पार्टी के स्वयंसेवक नहीं हैं। मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश और जनेवि के आचार्यगण किसी पार्टी या नेता के पिछलग्गू नहीं है। आखिर ये सब लोग खफा क्यों हैं? जनेवि के छात्र संघ के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टियों को आखिर मुंह की क्यों खानी पड़ी? सारा खबरतंत्र माकपा की खबर लेने पर उतारू क्यों है? बंगाल के बाहर रहने वाले बंगाली नंदीग्राम पर लज्जित क्यों हो रहे हैं? मार्क्सवादियों ने अपने कारनामों से मार्क्स पर ही नहीं, बंगाल के स्वर्णिम नाम पर भी बट्टा लगा दिया है। नंदीग्राम को अपने गले का पत्थर बना लिया है।

नंदीग्राम के अपराधियों को दंड कौन देगा?

वे जो खुद डरे हुए हैं या जनता के अवसन्न मन की राख से चिंगारी निकलेगी?

&r#.k fot ;

जिस प्रकार वामपंथी विचार के भी अनेक कलाकार, साहित्यकार एवं अन्य बुद्धिजीवी नंदीग्राम में माकपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ कोलकाता में सड़कों पर उतर आए और लगभग ३ मील लम्बे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, यह इस बात का हल्का सा संकेत देता है कि सब कुछ सहने वाली धरती की तरह जनता भी बहुत कुछ बहुत समय तक सहती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब परिणाम की चिंता किए बिना उसकी अंतश्चेतना अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। नंदीग्राम नरसंहार पर केन्द्र चुप है। जनता में हताशा और राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वास के कारण सन्नाटा है। लेकिन एक गुस्सा भीतर ही भीतर पल रहा है। यह कब, कहां और कैसे फूटेगा इसका अंदाजा लगाना कठिन है। लेकिन अन्याय करने वाले और अन्याय के प्रति चुप रहने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, यह विश्वास करते हुए राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कार्यकर्ताओं को निर्णायक प्रहार की सफलता हेतु जमीन, पानी और हवा (संत विनोबा के शब्दों में) तैयार करने का काम जारी रखना होगा। यह परिदृश्य रूस के राष्ट्रपति पुतिन की उपलब्धियों के संदर्भ में देखने का प्रयास समीचीन होगा।

हाल ही में प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह रुस की २८ घंटे की यात्रा पर गए थे। यह यात्रा वर्तमान संदर्भों में विशेष सामरिक महत्व की रही, क्योंकि एक ओर अमरीका से परमाणु संधि पर विवाद अभी थमा नहीं है, दूसरी ओर भारत के भूराजनीतिक क्षेत्र में रुस और चीन के साथ मैत्री का विशेष महत्व है। इस यात्रा में एक दिलचस्प बात यह रही कि यद्यपि संप्रग सरकार उन वामपंथियों के सहारे पर टिकी है जिन्हें १९१७ में रुस में प्रारंभ हुई बोलशेविक क्रांति की वैचारिक संतान कहा जा सकता है, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान न तो

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस क्रांति की चर्चा ही करना उचित समझा जिसकी बचे खुचे कम्युनिस्ट ९०वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और न ही वे मास्को में लेनिन की सुरक्षित रखी देह पर फूल चढ़ाने गए। बोलशेविक क्रांति का नामोनिशान उसी भूमि में समाप्त हो गया है जहां वह जन्मी थी। यह सब ७५ वर्ष से भी कम समय में दिखा, जबकि लगभग उसी समय प्रारंभ हुआ हिन्दुत्व का आंदोलन जो रा०स्व०संघ के नाम से पहचाना गया, ८२वें वर्ष में पहले से अधिक सशक्त, सबल दिख रहा है और भारतीय वस्तुपरक प्रेक्षक भी यह मानते हैं कि रा०स्व०संघ भारत का पाथेय तय कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े हिन्दू संगठन के नाते तो उसकी मान्यता चतुर्दिक फैली ही है। यह अंतर होता है आत्मीयता पर आधारित एवं मातृभूमि की वंदना से प्रेरित आंदोलन तथा हिंसा और घृणा पर टिके आंदोलन में।

हालांकि डा० मनमोहन सिंह की इस यात्रा में परमाणु सहयोग तथा दक्षिण भारत में रुस की मदद से चार नये परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके, क्योंकि रुस संभवतः अमरीका के प्रतिबंधों के कारण ऐसे समझौते फिलहाल नहीं कर सकता, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान, सन् २०११ तक चंद्रमा पर भारत और रुस का संयुक्त अंतरिक्ष यान-अभियान, आतंकवाद और नशीले पदार्थों पर रोकथाम के लिए साझा रणनीति तथा बहुत बड़ी मात्रा में युद्धक सामग्री, जैसे युद्धक हेलीकाप्टर और पांचवीं पीढ़ी के अत्यंत उन्नत युद्धक विमान प्राप्त करने पर समझौता हुआ।

पुतिन इस समय

जिस प्रकार वामपंथी विचार के □ी अनेक कलाकार, साहित्यकार एवं अन्य बुद्धिजीवी नंदीग्राम में माकपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ कोलकाता में सड़कों पर उतर आए और लग□ग 3 मील लम्बे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, यह इस बात का हल्का सा संकेत देता है कि सब कुछ सहने वाली धरती की तरह जनता □ी बहुत कुछ बहुत समय तक सहती है, लेकिन एक दिन ऐसा □ी आता है जब परिणाम की चिंता किए बिना उसकी अंतश्चेतना अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होती है।

रुस के महानायक के रुप में उभरे हैं, जिनकी तुलना रुसी साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने वाले पीटर महान से की जाने लगी है। कम्युनिस्ट शासन के दौरान सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति एक छलावे और भ्रम में छुपाकर रखी गई और दुनिया के सामने एक ऐसी महाशक्ति का मुखौटा प्रकट किया गया जो भीतर से खोखली होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि अमरीकी रणनीति के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ के विघटन का साधन बने। शेष बचा रुस महासंघ यद्यपि आज भी दुनिया के बड़े और विशालकाय देश के नाते जाना जाता है, परंतु विघटन के समय उसकी आर्थिक नींव टूट चुकी थी। उस समय लोग थैले भरकर रुबल ले जाते थे और उनके बदले अंगुलियों पर गिने जाने वाले डालर भी नहीं मिलते थे। १९९१ में बोरिस येलत्सिन रुस के पहले लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए राष्ट्रपति बने। परंतु वे भी रुस की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाए। उनके बाद राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन पर केवल रुस की आर्थिक स्थिति को ही संभालने की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि विश्रृंखलित और विखंडित रुस के स्वाभिमान और सामर्थ्य को पुनः स्थापित करने एवं केजीबी से निकले हुए कर्मचारियों के माफिया गिरोहों की गिरफ्त से रुस को मुक्त करने का काम भी उन्हीं के कंधों पर टिका। उधर चेचन्या में बढ़ रहे इस्लामी आतंकवाद की आंच रुस को भी जला रही थी। पुतिन ने सत्ता के सूत्र बहुत कड़ाई और परिणाम की चिंता किए बिना अपने हाथ में लिए, घोटाले और जालसाजी में लिप्त देश के सबसे बड़े उद्योगपति खादरोकोव्स्की को गिरफ्तार कर ९ साल के लिए जेल में भेजा। निष्क्रिय प्रधानमंत्री को अपने कमरे में बुलाकर तुरंत बर्खास्त किया और चेचन्या के इस्लामी विद्रोहियों से किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार करते हुए प्रबल सैनिक कार्रवाई द्वारा उनको कुचला। जाहिर था इसकी अमरीका के तथाकथित मानवाधिकारवादियों ने जमकर आलोचना की। बढ़ते रुस के महानायक पुतिन आज अमरीका की आंख में सबसे ज्यादा खटकने लगे हैं, क्योंकि अमरीका को लगता है कि उसकी एक धुव्रीय वैश्विक महाशक्ति बनने की यात्रा को पुतिन ही बाधित कर सकते हैं। लेकिन पुतिन दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति बनने के बाद अब अगले वर्ष मार्च में पद छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उनकी इस घोषणा का रुस में तीव्र विरोध हुआ है, क्योंकि लोग

चाहते हैं कि रुस को पुतिन जैसे कठोर और दृढ़निश्चयी शासक ही बचा सकते हैं।

इस समय रुस की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से आतंकवादियों का प्रायः निर्मूलन किया जा चुका है। पुतिन की आयु केवल ५५ वर्ष है। वे ब्लैक बेल्ट धारक कराटे खिलाड़ी हैं और युवकोचित उत्साह के साथ देश में एक नई शक्ति का स्फुरण करने में कामयाब हुए हैं।

भारत के प्रधानमंत्री जब उनसे मिले तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम नरसंहार हो चुका था। लेकिन न तो प्रधानमंत्री नंदीग्राम में माकपाई हिंसाचार के शिकार अपने ही भारतीयों से मिलने गए और न ही उन्होंने उस क्षेत्र में मार्क्सवादी आतंक के कारण डर से पलायन करने पर विवश लोगों की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय किए। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे नागरिकों पर हिंसक हमले का समर्थन ही किया गया। इस पर भी शासक दल की ओर से निंदा का एक शब्द भी नहीं कहा गया। देश में आतंकवादी कहीं भी, किसी भी जगह हमले करने के लिए स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। माओवादी हिंसाचार, इस्लामी जिहाद से भी ज्यादा बर्बर साबित हुआ है। ये कम्युनिस्ट आतंकवादी आज भी स्टालिन और माओ त्से तुंग को उसी प्रकार से नायक मानते हैं जिस प्रकार माकपा इन दोनों कम्युनिस्ट नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करती है। सबकी ऊर्जा और प्रेरणा के केन्द्र एवं स्रोत एक ही हैं, और वे अपने अपने देश में बर्बर हिंसाचार, गुलाग, साइबेरिया और सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर अमानुषिक आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, बस काम करने और मुखौटे ओढ़ने के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। माकपा और उसके सहधर्मी कम्युनिस्ट संगठन देश में असहिष्णुता, नफरत और हिंसाचार के सबसे बड़े केन्द्र बन गए हैं। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने केवल कम्युनिस्ट आतंकवाद पर नियंत्रण एवं निर्मूलन के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, जिसके १३ मुख्यमंत्री सदस्य हैं।

गृह मंत्रालय में इसी विषय पर एक विशेष डिवीजन १९ अक्तूबर, २००६ को बनाया गया था जिसका उद्देश्य है-सुरक्षा और विकास, दोनों ही दृष्टिकोण से कम्युनिस्ट आतंकवाद पर नजर रखना तथा

जिन क्षेत्रों में कम्युनिस्ट आतंकवाद तीव्रता से बढ़ रहा है वहां रोकथाम के उपाय सुझाना। इसमें सरकार को जम्मू-कश्मीर के इस्लामी जिहादियों के समान ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक अपनी ताकत और धन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय की २००७ की रिपोर्ट में गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल ने बताया है कि देश के १२,४७६ में से ३६५ पुलिस थाना क्षेत्रों में नक्सल या कम्युनिस्ट हिंसाचार की घटनाएं घटी हैं। २००३ में नक्सली कम्युनिस्ट आतंकवादियों ने ४१० नागरिकों एवं १०५ पुलिसकर्मियों की हत्या की । २००६ में यह आतंकवाद बढ़ा है और पिछले वर्ष कम्युनिस्ट आतंकवादियों द्वारा ५२१ नागरिकों एवं १५७ पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। मुख्यतः कम्युनिस्ट आतंकवादियों के गिरोह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड में नये प्रभाव बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका पहले से ही प्रभाव चला आ रहा है। इस दृष्टि से माओवादी गुट अब एकजुट हो रहे हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया(माओवादी) यदि नई भर्तियों के लिए जुटी हुई है तो मई २००५ में स्थापित क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा अब भारत का जनवादी लोकतांत्रिक मोर्चा (पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ इंडिया) के नाम से जाना जाने लगा है। पिछले दिनों झारखंड में नक्सलवादियों ने १८ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता श्री बाबूलाल मरांडी का पुत्र भी था। इन क्षेत्रों के विकास और नक्सल कम्युनिस्ट आतंकवाद पर रोकथाम के लिए १३ राज्यों हेतु केन्द्र सरकार ने ३६७७.६७ करोड़ रूपए आवंटित किए हैं।

पर जब केन्द्र में ऐसा राजा हो जो स्वयं ही डरा हुआ हो तो प्रजा कहां से संबल प्राप्त करेगी? इसलिए रुस के राष्ट्रपति पुतिन से केवल हथियार ही लेने की आवश्यकता नहीं है। आतंकवाद निर्मूलन और राष्ट्रीय स्वाभिमान जागरण हेतु शक्ति संवर्धन के लिए कुछ साहस भी मनमोहन सिंह ले आते तो बेहतर होता।

तानाशाहों के लिए संदेश

pnekgu

नंदीग्राम में कितनी महिलाओं से बलात्कार किया गया यह भी मालूम नहीं पड़ेगा कितने बम चल इनकी गिनती ही नहीं। कितने लोग मारे गए यह भी मालूम नहीं पड़ेगा। कितने शव नदी में फेंक दिये, कोई नहीं जानता। राहत शिविरों में असंख्य ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके मर्द कहां हैं? और यही पार्टियां हैं जो गुजरात को लेकर इतना शोर मचाती रही हैं। गोधरा के बाद गुजरात में जो दंगे हुए वे निंदनीय हैं। हिंसा का कहीं भी कोई औचित्य नहीं है, पर नरेन्द्र मोदी ने कभी खुलेआम हिंसा को जायज नहीं ठहराया पर बुद्धदेव भट्टाचार्य तो खुलेआम कह रहे हैं कि जो हुआ वह सही था। हिंसा के बल पर आप अधिक देर शासन नहीं कर सकते। सोवियत यूनियन को बिखरते समय नहीं लगा था इसलिए माकपा को सावधान हो जाना चाहिए। कि आम लोगों के साथ उसका रिश्ता टूट गया है। बुद्धदेव को यह भी याद रखना चाहिए कि उनके लोग

मुख्यमंत्री का कहना है कि 'मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं।' इस स्वीकृति पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, आखिर वहां माकवा के नेतृत्व में सरकार है और कांग्रेस वाला हाल नहीं कि नेता पार्टी से बड़ा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की समस्या मुख्यमंत्री तथा पार्टी का रिश्ता नहीं, असली समस्या है कि सरकार पार्टी के मातहत है। पार्टी वहां लूटपाट करें, लोगों को आतंकित करे, विरोधियों को खत्म कर दे, सरकार चुपचाप तमाशा देखती रहेगी। पश्चिम बंगाल के पतन का भी यही कारण है।

बिल्कुल माफ नहीं करते। सिद्धार्थ शंकर रे के बाद पूरे तीस वर्ष हो गए, कांग्रेस के उन्होंने अभी तक पैर नहीं जमने दिए इसी में मिनी-तानाशाहों के लिए संदेश छिपा है।

एक न एक दिन ऐसा होना ही था। सच्चाई सामने आनी ही थी। ३० वर्ष से पश्चिम बंगाल में वामदलों का शासन है। सब हैरान हैं कि यह कैसे संभव हुआ जबकि इस दौरान प्रदेश निरंतर पिछड़ता गया। नंदीग्राम का घटनाओं से साफ हो गया है कि उस अभागे प्रांत में वामदलों का शासन हिंसा तथा अत्याचार पर आधारित रहा है। सरकार पार्टी के अधीन हो गई और पार्टी के काडर ने विरोधियों को कुचल डाला। आज हालत है कि मेधा पाटेकर जो अधिकतर मामलों में वामदलों के साथ रही हैं, ने नंदीग्राम को टॉर्चर चैम्बर कहा है। उनके अनुसार यह ऐसा यातना शिविर है जहां सत्ताधारी माकपा के कार्यकर्ताओं को आतंक फैलाने की छूट है। वामदलों गठबंधन में शामिल आरएसपी के एक मंत्री ने इस्तीफे की इच्छा व्यक्त करते हुए नंदीग्राम में माकपा की गुंडागर्दी को इसके लिए दोषी ठहराया है। अब स्थिति कुछ सुधर गई है लेकिन एक बार तो पुलिस ने भी वहां की स्थिति को 'भयावह' कहा था। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हिंसा को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। उनके अनुसार माओवादियों की हिंसा का जवाब देने के लिए उनके काडर को हिंसा अपनानी पड़ी। वह पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुलेआम हिंसा, लूटपाट तथा बलात्कार को न्यायोचित ठहराने की हिमाकत की है। किसी भी लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए लेकिन मार्क्सवादी नेता समझते हैं कि उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। आखिर वे गांधीवादी तो कभी भी नहीं थे। उन्हें लक्ष्य की चिंता है साधनों की चिता उन्होंने कभी नहीं की इसीलिए नंदीग्राम में विरोधियों को हिंसा के साथ कुचल दिया गया।

एक पत्रकार ने नंदीग्राम से रिपोर्ट भेजी है, 'अधिकतर जगह माकपा के कार्यकर्ता अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए गांवों में दाखिल हो गए। उसके बाद लूटपाट और आगजनी शुरू हो गई। मध्यकालीन समय के युद्ध की याद दिलाने वाले हथकंडों को अपनाते हुए सीपीएम ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया जिसके आगे पकड़े गए ५०० भूमि उच्छेद कमेटी के कार्यकर्ताओं को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल

किया गया। सभी के हाथ बंधे थें इसके दो मकसद थे। एक, विरोधी अब उनकी रैली पर गोली नहीं चला सकेंगे और दूसरा अगर रास्ते में बारूदी सुरंग बिछाई गई है तो उसका असर इस मानवीय ढाल पर पहले होगा।'

यह हालत है आज के आधुनिक भारत के एक हिस्से की जहां लोगों को पकड़ कर 'मानवीय ढाल' की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की यह शिकायत कि वहां तृणमूल कांग्रेस तथा माओंवादियों के बीच सांठगांठ रही है, का प्रतिवाद उनके अपने गृहसचिव ने किया है जिनका कहना है कि उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। साफ है कि अपने काडर की हिंसा तथा बदमाशी से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री माओवादियों को दोषी ठहरा रहे हैं जबकि स्वतंत्र पर्यवेक्षक कह चुके हैं कि वहां की बुरी हालत का कारण माकपा का आतंक का शासन है। कई जगह तो बाकायदा बंकर बने हुए हैं। शायद इसीलिए राज्यपाल ने इसे युद्ध क्षेत्र कहा है। कुछ समय के लिए सीआपीएफ को नंदीग्राम में प्रवेश नहीं दिया गया। मीडिया को भी बाहर रखा गया। खैर अब चिंता नहीं रही क्योंकि मुख्यमंत्री हिंसा का औचित्य समझा रहे हैं। अगर हिंसा सही है तो फिर छिपाने की जरूरत ही नहीं है।

कांग्रेस जो इस मामले में बच-बच कर मुंह खोल रही है, को भी कहना पड़ा कि 'यह हिंसा राज्य-समर्थित कत्लेआम है।' कांग्रेस संतुष्ट है कि वामदल विशेष तौर पर माकपा, दबाव में आ गए हें और परमाणु करार को लेकर शायद अब बहुत तंग नहीं करेंगे लेकिन देश को तो सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कैसी सरकार है जिसके लिए हिंसा शासन का सही साधन है? जहां गांवों पर कब्जे किये जाते हैं और विरोधियों को परास्त करने के लिए अत्याचार और बलात्कार का इस्तेमाल किया जाता है। नंदीग्राम में कितनी महिलाओं से बलात्कार किया गया यह कभी मालूम नहीं पड़ेगा। कितने बम चले इनकी गिनती ही नहीं। कितने लोग मारे गए यह भी मालूम नहीं पड़ेगा। कितने शव नदी में फेंक दिये, कोई नहीं जानता। राहत शिविरों में असंख्य ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके मर्द कहां हैं? और यही पार्टियां हैं जो गुजरात को लेकर इतना शोर मचाती रही हैं। गोधरा के बाद गुजरात में जो दंगे हुए वे निंदनीय हैं। हिंसा का कहीं

भी कोई औचित्य नहीं है, नरेन्द्र मोदी ने कभी खुलेआम हिंसा को जायज नहीं ठहराया पर बुद्धदेव भट्टार्य तो खुलेआम कह रहे हैं कि जो हुआ वह सही था। अर्थात वह स्पष्ट कर रहे है कि अगर कम्युनिस्टों की सत्ता को चुनौती दी गई तो फिर ऐसा ही होगा।

मुख्यमंत्री का कहना है कि 'मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं।' इस स्वीकृति पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, आखिर वहां माकवा के नेतृत्व में सरकार है और कांग्रेस वाला हाल नहीं कि नेता पार्टी से बड़ा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की समस्या मुख्यमंत्री तथा पार्टी का रिश्ता नहीं, असली समस्या है कि सरकार पार्टी के मातहत है। पार्टी वहां लूटपाट करें, लोगों को आतंकित करे, विरोधियों को खत्म कर दे, सरकार चुपचाप तमाशा देखती रहेगी। पश्चिम बंगाल के पतन का भी यही कारण है। अब अवश्य बुद्धदेव घेराव की नीति की आलोचना करते हैं पर उस वक्त जब सस्ती लोकप्रियता के लिए उद्योग को पश्चिम बंगाल से खेदेड़ा जा रहा था सरकार मूकदर्शक बना रही। आज उसी उद्योग को वापस बुलाने की कोशिश में सिंगूर तथा नंदीग्राम में समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि अब निकी जमीन छीनी जा रही है वे प्रतिरोध कर रहे हैं और मीडिया के इस युग में उन्हें दमन से भी दबाया नहीं जा सकता।

एक लोकतंत्र में सरकार तथा पार्टी के अलग अलग निर्धारित क्षेत्र होते हैं। सरकार को चलाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भाजपा के प्रिय मुद्दों को एक तरफ रख दिया था लेकिन पश्चिम बंगाल में काडर सुप्रीम है। वह तो लाठी और गोली चलाने के आदी हैं। उन्हें तो समझाया गया है कि जो विरोध करे उसे पीट डालो और अगर जरूरत पड़े तो गोली भी चला दो, हम सब संभाल लेंगे। उन्हें बातचीत या आम सहमति का रास्ता आता ही नहीं क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसे कभी अपनाया ही नहीं गया। या आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। जरूरत से अधिक यह आत्मविश्वास अब उलटा पड़ा है और दशकों से इस आतंक को बर्दाश्त करने वाला समाज उठा खड़ा हुआ है। बुद्धदेव शुरू में अपने लोगों को नियंत्रण में करने का प्रयास करते रहे लेकिन जिन्न ने वापस बोतल में आने से इनकार कर दिया और अब दबाव इतना है कि उदार मुख्यमंत्री का मुखौटा उतार वह खुद हिंसा को सही ठहरा रहे हैं। इस प्रक्रिया में

उन्होंने आर्थिक सुधार की अपनी नीति भी खतरे में डाल दी क्योंकि जिस तरह के हथकंडे अपना कर माकपा ने अपनी सत्ता कायम की थी वही अब प्रांत के लिए बेड़िया बन गये हैं क्योंकि इन हालात में वे उद्योगपति महामूर्ख होंगे जो पश्चिम बंगाल में निवेश करना चाहेंगे। अब तो वहां के वामदलों के समर्थक बुद्धिजीवी भी सड़कों पर उतर आए हैं। पहली बार है कि माकपा बिल्कुल अलग-अलग पड़ गई है।

सबसे अधिक दुख इस बात का है कि यह बढ़िया प्रांत जिसने कई बार देश का विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व किया था एक बार फिर राजनीतिक तथा हिंसा के मिश्रण के कारण फंस गया है। पर हिंसा के बल पर आप अधिक देर शासन नहीं कर सकते। सोवियत यूनियन को बिखरते समय नहीं लगा था इसलिए माकपा को सावधान हो जाना चाहिए। आम लोगों के साथ उसका रिश्ता टूट गया है। बुद्धदेव को यह भी याद रखना चाहिए कि उनके लोग बिल्कुल माफ नहीं करते। सिद्धार्थ शंकर रे के बाद पूरे तीस वर्ष हो गए, कांग्रेस के उन्होंने अभी तक पैर नहीं जमने दिए इसी में मिनी-तानाशाहों के लिए संदेश छिपा है।

नंदीग्राम चाहता है, बुद्धदेव को फांसी हो

&eèkk ikVdj

नन्दीग्राम की क्या हालत है, बाहर से इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं इससे पहले भी वहां गई थी। मैंने वहां के लोगों का संकल्प, संघर्ष की मानसिकता देखी थी। लेकिन इस बार जो देखा, उसकी किस घटना से तुलना करूं, यह मेरी सोच से बाहर है। नन्दीग्राम मैं देख आई। जिलाशासक, अनूप अग्रवाल की भाषा और सीपीएम के नेताओं की भाषा हूबहू एक जैसी! नहीं, यह सोच से बाहर है। इससे पहले जॉर्ज बुश ने जो तर्क देकर, इराक में फौजों को घुसाया था, वही भाषा राज्य प्रशासन की जुबान पर भी गूंज रही है। ये वही लोग हैं, जो बुश के पुतले जलाते हैं। हाल में जो घटनाएं घटीं, अगर वे सब न घटी होतीं, तो सीपीएम के भ्रष्टाचार और तानाशाही का मुखौटा या नकाब कभी भी नहीं दिख सकता। मेरे साथ थे डी थंकप्पन, बी डी शर्मा, जी एन साइंबाबा की तरह सर्वभारतीय जन-आंदोलन के कर्मचारीगण! उन लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा। मैं चाहती हूं कि नन्दीग्राम की वास्तविक तस्वीर अपने समस्त देशवासियों के सामने पेश करूं।

उस दिन पुलिस और सीपीएम के कैडर एक साथ घुस आए थे। उस वक्त गांव की महिलाएं गौरांग का नाम-जाप कर रही थीं। और मुस्लिम लोग कुरान-पाठ कर रहे थे। किसी भी हाल में वहां संघर्ष की स्थिति नहीं थी। पुलिस और सीपीएम कैडरों ने इन्हीं निहत्थे लोगों पर हमला बोल दिया। हम सबने सोनाचूड़ा समेत कई गांवों का चक्कर लगाया। नन्दीग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल से होते हुए, हम कलकत्ता स्थित एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती घायल लोगों

से मिले और उन लोगों से बातचीत की। गोकुल नगर के अधिकारी मुहल्ले की महिलाओं के साथ, पुलिस ने १४ तारीख को ही दुर्व्यवहार किया था। १६ तारीख को, जिस वक्त इलाके के मर्द घर पर नहीं थे, उन लोगों की गैर मौजूदगी में सीपीएम कैडरों की फौज और पुलिस एक साथ गांव में घुस आई और औरतों के साथ बलात्कार किया। जैसे साम्प्रदायिक दंगे-फसाद में सबसे पहले औरतें ही बर्बरता का शिकार होती हैं, जैसे महिलाओं की इज्जत लूटकर, हमलावर प्राथमिक जय अर्जित करते हैं, नन्दीग्राम में भी उसी तरह की पाशविक-लीला का प्रदर्शन हुआ। 'विकास की दस्यु-फौज' के हाथों, आक्रांत, बलात्कार की शिकार महिलाएं, तमलुक के अस्पताल में भर्ती थीं। हम सब उन औरतों से मिले। उन लोगों की प्राथमिक डाक्टरी जांच किए बिना ही, डॉक्टरों ने फैसला दे दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं। जाहिर है, ये डॉक्टर काफी दबाव में थे।

नन्दीग्राम में बहुतेरे लोग अभी तक लापता हैं, हालांकि राज्य सरकार इसे दबा जाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल शायद इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया है और इसने एक नया तरीका ईजाद किया है। मैंने सुना कि यहां इनसान को कत्ल करके, उसका पेट चीरकर पानी में डुबा देते हैं। नतीजा यह होता है कि लाश जल के ऊपर नहीं आती। तालपट्टी नहर में ऐसे कितने ही लोगों को मारकर, उनका पेट चीरकर बहा दिया गया, इसका हिसाब शायद किसी भी दिन नहीं लगाया जा सकेगा। एक बच्ची को चीरकर, उसके दो टुकड़े कर दिए गए। इसकी तो कल्पना तक नहीं की जा सकती। शुरुआती जांच करके, हमने ऐसे १६ लोगों के नामों का पता लगाया है। देवव्रत खांडा, सुजित माइती, अनिमेष अधिकारी समेत वे तमाम लोग कहां हैं? इसका जवाब कौन देगा? जो लोग जिंदा बच गए, उन लोगों की हालत भी बयान-बाहर है। राधा रानी नामक एक महिला की योनि में रॉड घुसेड़कर उसे चीर दिया गया है। बलात्कार की शिकार, अधमरी इन लोगों को अस्पताल नामक नर्क में आखिर क्यों फेंक रखा गया है? राज्य सरकार को तो बहुत पहले ही चाहिए था कि इन लोगों को कलकत्ता लाकर, किसी अस्पताल में उन लोगों का इलाज कराते। आज जब लिखने बैठी हूं तो उन घटनाओं की याद आते ही आंखें भर आई हैं। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल से मेरा यही निवेदन है कि

आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। वे उन लोगों के उध्दार की तत्काल व्यवस्था करें। राज्य सरकार पर अब हमें भरोसा नहीं रहा। सिविल सोसायटी की मदद से इस त्राण-बंटन का इन्तजाम करना भी जरूरी है। हम सबने आपस में चन्दा करके सामूहिक कैंटीन खोलने के लिए ११ हजार रुपए जमा किए हैं। लेकिन जितने पैसों की जरूरत है, उसकी तुलना में ये रुपए काफी कम है। इस बार जब नन्दीग्राम गई, तो वहां के लोगों ने एक और मांग पेश की। जिन माताओं की गोद सूनी हो गई है, उन लोगों ने मांग पेश की-खूनी बुध्ददेव को फांसी दी जाए। मैं खुद मृत्युदंड के विरुध्द हूं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ढंग से धनंजय को फांसी दी गई थी, बलात्कार और कत्ल के अपराध में, उसी तरह इसी किस्म के अपराध में मुजरिम, बुध्ददेव को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। उन लोगों का बयान था कि धनंजय चूंकि गरीब था, इसलिए उसको फांसी दे दी गई और बुध्ददेव में चूंकि क्षमता है, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलेगीध मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई।

सीबीआई की जांच जैसे चल रही है, चले। इसके साथ हमारी मांग है कि विचार-विभागीय जांच भी शुरू की जाए। आगामी सोमवार से ही हम लोग दिल्ली के जन्तर-मन्तर में अनशन पर बैठ रहे हैं। हम लोग नन्दीग्राम, सिंगुर के आन्दोलन से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि वाम-फ्रंट की मीटिंग द्वारा की गई घोषणा नन्दीग्राम के लोगों की आंशिक विजय है। नन्दीग्राम अब किसी दिन भी केमिकल हलचल नजर नहीं आएगी, राज्य सरकार को यह घोषणा करनी होगी। सिंगूर से भी अपने पंजे हटाने होंगे। सिंगूर के लोगों को उनके खेत-खलिहान लौटाने होंगे। सीपीएम, समूचे भारत में सेज के बारे में आन्दोलन करती हुई घूम रही है। इस पश्चिम बंगाल में वह आंदोलन कहां हैध यह तो एक ही पार्टी की दोमुंही नीति है। हमने सभी वामपंथी बुध्दिजीवी लोगों के सामने सीपीएम की इस दोमुंही नीति को दिखाया है। बहुत से लोग इस पार्टी का असली चेहरा पहचान गए हैं। लेकिन अभी और लोगों को भी उनका असली चेहरा पहचानना बेहद जरूरी है।

(हिन्दी रूपान्तर : सुशील गुप्ता, साभार : वर्तिका)

कब्रिस्तान के अमन को कैसे कहें कि नंदीग्राम में शांति है

uck : .k HkVVkpk;

अगर कब्रिस्तान के सन्नाटे को 'अमन' कहा जा सकता है तो नंदीग्राम में फिलहाल शांति है। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी वाममोर्चा के प्रमुख घटक माकपा नेतृत्व को यह खामोशी ज्यादा भाती है। ग्रामवासी जिन्होंने अपनी जमीन पर हक के लिए ११ महीने तक संघर्ष किया, अचानक ही माकपा समर्थकों में शुमार हो गए हैं। जब बंदूक की नाल से ताकत निकलती है तो ऐसे में किसी का क्या अख्तियार रह जाता है। यहां तक कि ऐतिहासिक उद्धरण भी 'क्रूर हास्यास्पद' हो सकते हैं। सात नवंबर को रणनीतिक रूप से अहम तेकहाली पुल पर तैनात पुलिस को हटा लेना, सशस्त्र पुलि का अपने को थाना परिसर में ही सीमित कर लेना जबकि गांव के गांव जल रहे हों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की देरी से तैनाती और 'लिबरेशन' के लिए मिले अंतराल ने 'लोकतंत्र', 'प्रशासन', 'सरकार', 'वाम', 'मानवाधिकार' और 'सपंत्ति' तथा जीने के अधिकार जैसे शब्दों को बातिल और शून्य कर दिया है।

वे लोग जिन्हें नंदीग्राम के नक्शे पर माकपा को बलात् काबिज रखने के लिए जवाबदेही दी गई थी, वे कोई प्रतिबद्ध मार्क्सवादी काडर नहीं थे। वे परले दर्जे के हत्यारे, डकैत, संहारक हथियारे, डकैत, संहारक हथिचार चलाने में उस्ताद और लोगों की जान मरने या उनका अंग-भंग कर मौके से भाग निकलने में माहिर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जेंटीना से आए फिल्म प्रतिनिधियों को कोलकाता में आयोजित हो रहे फिल्मोत्सव का माहौल दमघोंटू लगा और वे चले गये। हम माकपा महासचिव प्रकाश करात एंड कंपनी की 'माओवादी' भूत वाली कहानी पर भरोसा कर सकते हैं जब तक कि वह लोगों की

नजरों में इराक में संहारक हथियार वाली बुश की थ्योरी की तरह फुस्स न हो जाए और छोटा अंगरिया मामले में वर्षों से सीबीआई को वांछित अपराधी सकूल अली वर तपन घोष को नंदीग्राम में मारे गए लोगों और घायलों को ठिकाने लगाते ले जाते रंगे हाथ पकड़ जाने का सच पूरी तरह से उजगार नहीं हो जाता। प्रदेश के गृह सचिव को १३ नवंबर तक यह इलहाम नहीं था कि नंदीग्राम में माओवादी भी मौजूद हैं। इनमें से किसी को पकड़ा भी नहीं गया। किसी को यह बात मालूम नहीं थी लेकिन माओवादियों की कारगुजारियों के बारे में प्रकाश करात बेहतर जानते हैं और इस रहस्य की जानकारी उन्हें सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नारायणन से मिली थी। अगर ऐसा हुआ भी तो यह सोचकर हैरत होती है कि ऐसे समय में जब पाक में आपात्काल का ऐलान हो रहा हो, सुरक्षा सलाहकार के पास इतना फालतू समय फिर भी बच जाता है कि वह नंदीग्राम में माओवादियों को ढूंढ निकाल ले! मैं तो अदना-सा-आदमी हूं और कलम का सिपाही हूं।

हम अपने इस सौभाग्य पर रश्क कर सकते हैं कि हमारे पास गोपाल कृष्ण गांधी के रूप में एक संवेदनशील समीक्षक राज्यपाल हैं, जिनकी बौद्धिक साख एक मार्क्सवादी चिंतक के रूप में बिमान बोस (वाममोर्चे के संयोजक) की तुलना में कहीं ज्यादा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बंगाल के लोग आजादी के बाद से ही ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के साक्षी रहे हैं जब प्रदेश सरकार और प्रशासन के हर काम में माकपा काडरों की दखलंदाजी चलती है। चाहे प्रेस हो, प्रख्यात सामाजिक नेता या विपक्ष का नेता; किसी को भी वहां घुसने की इजाजत नहीं होती! कानून उनके हाथों उसी तरह बंदी हो जाती है जैसा स्टालिन के जमाने में होता था।

नंदीग्राम में जारी इस खूनी मंजर के बीच कोलकाता में फिल्मोत्सव मनाने का इंतजाम किया गया। जिस दिन शाम को दीप जलाकर फिल्म समारोह का उद्घाटन होना था, उसी दिन दोपहर को नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जमीन से बेदखल किए जा रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर माकपा के नकाबपोशधारी गुंडे गोलिया बरसा रहे थे। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार तक किए गए। टेलीविजन के चैनलों ने दिखाया कि बुलेट खाए मानव अंगों से रिसते खून से नंदीग्राम की जमीन किस कदर रक्तरंजित हो गई थी। हजारों लोग

बेघर हो गए। गांव घर लौटने के बुद्धदेव भट्टाचार्य के आह्वान के बावजूद बहुतों ने अभी जाने को राजी नहीं हैं। मरने वालों की सरकारी संख्या तो सागर में एक बूंद भर है। मृतकों की सही-सही संख्या किसी भी जगह, इतिहास या भूगोल में नहीं बताई जाती। नंदीग्राम भी इस तथ्य का कोई अपवाद नहीं है। यह भी कोई अलहदा नहीं है कि किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस अपराध को अंजाम दिया है, यद्यपि किसी को भी हैरानी हो सकती है कि नरसंहार को अंजाम देने वाला और उसका रक्षक एक ही नामवली कैसे सटीक बैठते हैं। एक बाद खुद कार्ल मार्क्स ने अपने शिक्षण के दौरान कहा था, 'अगर यही मार्क्सवाद है तो ईश्वर को धन्यवाद कि मैं मार्क्सवादी हूं।' देश के सभी वामपंथ समर्थकों को इस दार्शनिक के विचारों से अपने को जोड़ना चाहिए। नंदीग्राम के साथ अनोखा यह हुआ कि वहां की हिंसक घटनाएं लोकतांत्रिक संघीय ढांचे में हुई। केन्द्र में बैठे हमारे नेता ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे होने दिया। इसमें कोई अजूबा नहीं कि परमाणु करार पर भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की बातचीत पर वामदलों ने अपना रवैया नरम कर लिया है और जब नंदीग्राम में विरोधियों से निपटने का काम पूरा हो गया, तो अब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आने की झंडी दी गई।

इन रिकार्डों का एक दिन फैसले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नंदीग्राम की हिंसक घटनाओं को लेकर मैं भावनात्मक रूप से काफी उद्विग्न हूं, इसलिए संभव है जहां-तहां तथ्यों की थोड़ी भूल हो जाए किन्तु मुझसे बड़े सच की अनदेखी कदापि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि लोग मारिचझानपी, नानपुर, केशपरु, गरबेटा आदि जगहों में हुई कारगुजारियों से अनजाने थे, बल्कि तब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया आज इतना विकसित जनसंचार माध्यम नहीं था। सत्ता में बैठे लोग जो यह सोचते थे कि वैश्वीकरण की ताकत जनता की प्रतिरोध करने की क्षमता कमतर कर देगी, नंदीग्राम की घटना ने उनकी आंखों में उंगली डालकर दिखा दिया कि सच वह नहीं है। नंदीग्राम हिंसा के पश्चात् कोलकाता, दिल्ली, बंगलुरू और अन्य शहरों के सभ्य नागरिक समाज के प्रदर्शनों में जबरदस्त प्रतिरोध के स्वर बुलंद किए हैं। पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवियों ने यह साबित कर दिया कि वे बिकाऊ नहीं हैं, हालांकि कुछ लोगों ने शैतानों के हाथों अपनी आत्मा बेच दी है।

शिकारी का साथ देने से अच्छा है खरगोश के साथ दौड़ना। इस बीच बिमान बोस गरजते हैं, 'नंदीग्राम में एक नया सवेरा हो रहा है', तो यह पश्चिम बंगाल के क्षितिज पर एक बड़ा ब्लैक होल बनाता है और यह जल्द ही देश के अन्य हिस्सों को भी अपना ग्रास बना लेगा। टेलीविजन के पर्दे पर उभरता एक चित्र 'नंदीग्राम का उपसंहार' है। एक गाय गोली से बिंधी आंखों से खूनी चीत्कार करती है। बेजुबान मासूम गाय नंदीग्राम की वीभत्स मारकाट का बयान कर जाती है। मैं तो फिलहाल कुछ बोलूंगा नहीं।

(लेखक मशहूर बांग्ला कवि और साहित्यकार हैं)

okeekpk ?kVdk u dgk&

नंदीग्राम नरसंहार के लिए माकपा दोषी

प.बंगाल में पिछले ३० वर्षों से वाममोर्चा की सरकार है जिसमें प्रमुख □ूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की है। इस पार्टी का ही प्र□ुत्व मोर्चे पर रहता है और नीति निर्धारण में माकपा नेताओं की बात प्रमुखता से मानी जाती है। मगर नंदीग्राम के वर्तमान हिंसक माहौल से वाममोर्चे के तीन प्रमुख घटकों- □ा.क.पा., आर.एस.पी., आर.पी.आई.- ने खुद को अलग करते हुए पूरा दोष माकपा पर मढ़ा है। उल्लेखनीय है कि इन तीनों दलों ने एक प्रस्ताव पारित करके माकपा की हिंसक राजनीति का विरोध किया और नंदीग्राम हत्याकाण्ड के लिए माकपा को दोषी ठहराते हुए इस पर अविलम्ब रोक लगाने की मांग की। यह कम्युनिस्ट राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वाममोर्चे में स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर दरार दिखाई दी है।

अब खुद को वामपंथी कैसे कहूं

xkre ?kk"k

नंदीग्राम घटना हमें देश की शासन व्यवस्था पर विचार करने का मौका देती है। हर घटना हमें सोचने के लिए विवश करती है, बशर्ते हम उसकी तह में जाएं। राजनीतिक पार्टियां आजकल विचारधारा से भटक गई हैं। उन्हें लोगों से ज्यादा कुर्सी की चिंता है। लोकतंत्र में कोई सरकार ३० वर्षों तक सत्ता में रहेगी, तो निश्चित रूप से बेपरवाह हो जाएगी। बंगाल में माकपा ३० वर्षों से सत्ता में है। आखिर यह कैसे हुआ। सिर्फ इसलिए कि बंगाल में विपक्षी दलों में एकता नहीं है, एक मंच पर आने को कोई तैयार नहीं। इसी का लाभ माकपा को मिला। मैं खुद वामपंथी हूं और इस विचारधारा से मुझे बेहद लगाव है, लेकिन आज मैं अपने को वामपंथी नहीं कह सकता। माकपा को विचारधारा से मतलब नहीं रहा। कुछ वर्ष पहले पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने मुझसे कहा था कि अब लोगों को विचारधारा से परिचित कराने के लिए माकपा में कक्षाएं नहीं लगतीं। कैडर से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, जबकि विचारधारा से कोई जुड़ाव नहीं। मेरी राय में विचारधारा अपनाकर यहां राजनीति करने कोई नहीं आता, बल्कि लोगों को पद, पैसे और प्रतिष्ठा की चिंता है। विचारधारा

मैं खुद वामपंथी हूं और इस विचारधारा से मुझे बेहद लगाव है, लेकिन आज मैं अपने को वामपंथी नहीं कह सकता। माकपा को विचारधारा से मतलब नहीं रहा। कुछ वर्ष पहले पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने मुझसे कहा था कि अब लोगों को विचारधारा से परिचित कराने के लिए माकपा में कक्षाएं नहीं लगतीं। कैडर से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, जबकि विचारधारा से कोई जुड़ाव नहीं।

से जुड़े नेताओं की संख्या घट रही है। नतीजतन नंदीग्राम में माकपा कैडर विपक्ष पर भारी पड़ा। जब तक विपक्ष ताकतवर था, उससे लोग त्रस्त रहे और जब माकपा की शक्ति बढ़ी, उसने नंदीग्राम पर कब्जा कर लिया। दोनों स्थितियों में निर्दोष जानें गई। राजनीति में बाहुबल का जोर है। जो कमजोर है, उसके लिए राजनीति नहीं। चुनाव जीतने के लिए अपराधी उतारे जाते हैं। कोई किसी से कम नहीं। यही स्थिति नंदीग्राम में थी। लोकतंत्र में तभी राजनीतिक विचारधारा कायम रह सकती है, जब उस पर चर्चा हो, गलतियां दूर करने की कोशिश हो लेकिन बंगाल की स्थिति दूसरी है। यह देखकर मैं दुखी हूं। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। सरकार ही अपराधियों और हिंसा का सहारा ले, तो लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं। सबसे दुखद यह कि सरकार अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करें। बुद्धिजीवियों ने सरकार की आलोचना की, तो उन्हें दुश्मन समझ लिया गया। सरकार किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप देखें पिछले १०.१५ वर्षों में बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। केवल कुछ लोग सत्ता का फायदा उठाते रहे। माकपा आत्ममंथन से पीछे हटेगी, तो वह दिन दूर नहीं जब लोग उसे सबक सिखा देंगे। नंदीग्राम और गुजरात की घटनाओं पर हमें आत्ममंथन की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। हम सत्ता के दम पर लोगों के जीवन से खेलें या मिलकर काम करें, विकल्प हमारे सामने है।

(गौतम घोष प्रसिद्ध फिल्मकार हैं)

प्रस्तुति : निर्भय देवयांश

माकपा के पतन के पहले का उन्माद

&t ; xkLokeh

यह तो पतन के पहले का उन्माद है। ऐसा उन्माद, जिसने बंगाल की सत्ता पर ३० वर्षों से काबिज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) को अंधा बना दिया है। इस उन्माद में मार्क्सवाद का ढोंग कर तीन दशकों से सत्ता का सुख भोग रही माकपा उस अवस्था को प्राप्त हुई है, जिसमें बुझने से पहले दीपक की लौ बार-बार उफनती है। अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर सभ्यता, संस्कृति व शासन के नाम पर वह जो कर रही है, उसकी अपेक्षा तो उससे नहीं थी। सत्ता के मद में चूर बुद्धदेव भट्टाचार्य व विमान बसु की भाषा आज वैसी नहीं होती, जैसी हुई है। कवि, लेखक, कलाकार, होनहार युवक-युवती और निहत्थे नागरिकों को इस तथाकथित वामपंथी सरकार की लाठियों, गोलियों की बौछार झेलने को विवश नहीं होना पड़ता।

१० नवंबर को माकपा की स्वपोषित गुंडावाहिनी ने माकपा के मुख्यमंत्री की पुलिस के संरक्षण में दिनभर नंदीग्राम में गोलियां बरसा कर वहां के निहत्थे किसानों को मौत की नींद सुलाने का काम किया। शाम होते ही संस्कृति और संवेदनशीलता की चादर ओढ़ मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य फिल्मोत्सव की चिंता में डूब गए। संस्कृति के अतीत से लोगों को परिचित कराने लगे, भविष्य की रूपरेखा तय करने लगे। वे यहीं नहीं थमते। बार-बार नरसंहारों को अंजाम दिलाने के बाद भी वे लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस करने से भी बाज नहीं आतें। यह सवाल तो उठता ही है कि नंदीग्राम में निहत्थे लोगों को मौत के हवाले कर रही माकपा की गुंडावाहिनी को कौन संरक्षण दे रहा है? कौन उसे प्रश्रय दे रहा है? बेशक एक ऐसा व्यक्ति, जो तथाकथित संस्कृतिबोध के अहंकार से फटा जा रहा है। एक ऐसा नेता, जिस अपने लेखक होने का भी दंभ है। पर किसी लेखक के जिद्दी स्वभाव, अड़ियल रवैये या कहें हठधर्मिता के चलते दुनिया में

कहीं भी रक्तपात हो रहा हो, निहत्थे लोगों का कत्लेआम हो रहा हो, ऐसा कभी किसी ने सुना है? देखा है? वह भी किसी एक जगह नहीं, जगह-जगह पर। एक बार नहीं, बार-बार। कभी सिंगुर में तो कभी नंदीग्राम में १७ जनवरी को, १४ मार्च को। इतने से हिंसा की प्यास बुझी नहीं तो फिर १० नवंबर को भी।

१० नवंबर की घटनाओं ने तो मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता व संस्कृतिबोध का मुखौटा उतार फेंका। मुख्यमंत्री की प्रशासनिक दक्षता व क्षमता की पोल खेलार रख दी। मालूम हो गया कि सूबे की सरकार कितनी डरपोक है। निहत्थे लोगों के तेज के सामने कैसे कांपने लगती है। उनकी पुलिस कविता पाठ करते, रवींद्र संगीत गाते नागरिकों को देख आंतकित हो जाती है। आंतक में बदहवास होकर लाठियों का सहारा लेती है। भद्दी गालियां बकती है। बुद्धदेव की पुलिस उनको व खुद को भयमुक्त करने के लिए लेखकों-कलाकारों को हवालात में भरने को आतुर हो उठती है। अगर यह बात नहीं होती, तो रवींद्र सदन के सामने सड़के के किनारे रवींद्र संगीत गाते शांतिप्रिय कलाकारों को जबरन वैन में भर कर लालबाजार लॉकअप में ठूंसने की आवश्यकता क्या थी।

दरअसल बुद्धदेव की पुलिस के सामने सवाल यह होता है कि वह अपना रणकौशल आखिर दिखायें कब? किसके सामने? नंदीग्राम में असलहे लहराते माकपा के नकाबपोश गुंडों की फौज के सामने तो इनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। यूं कहें कि माकपाई हमलावरों की छाया तक से भी बचने में ही इन्हें अपनी भलाई दिखती है। ड्यूटी के नाम पर बाहर होते भी हैं, तो पेड़ की छांव में कहीं ताश खेल रहे होते हैं। इनके सामने जब निहत्थे व शांतिप्रिय महिला, युवती लेखक-कवि, कलाकार वयोवृद्ध नागरिक आते है, इनका जोश जब उठता है। तभी तो रवींद्र सदन के सामने डीसी जावेद शमीम प्रतिवादी कवियों, लेखकों व कलाकारों को देख गालियां बकने लगते हैं, 'सुबह से बहुत हो गया। उठा लो सालों को। ये हैं संस्कृति संपन्न व्यक्तित्व के मालिक कहलाने वाले बुद्धदेव की पुलिस व प्रशासन के कारनामों की चंद झलकियां।

(जय गोस्वामी साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त बांग्ला कवि हैं)

समाचार पत्रों से संपादकीय

अमर उजाला

बुद्धदेव की भाषा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नंदीग्राम में हुई हिंसा को जिस तरह जायज ठहराया है, वह स्तब्ध करने वाला है। उनकी टिप्पणी थी कि विपक्षी दलों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। समझना मुश्किल नहीं है कि यहां 'विपक्षी दलों' से उनका मतलब तृणमूल कांग्रेस से है। वह यहीं चुप नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा, उन लोगों ने हमारे आदमियों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में, बदला तो लेना ही था। सहसा विश्वास नहीं होता कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही यहां हुई हिंसा को इस तरह न्यायोचित ठहरा सकता है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर उनके ही सहयोगी दल आरएसपी को आपत्ति है, विरोधी दलों की तो बात छोड़िए। दरअसल विगत मार्च से ही नंदीग्राम मामले में माकपा ने झूठ गढ़ लिया था। वह कह रही थी कि भूमि उच्छेद संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम के कुछ गांवों पर जबरन कब्जा जमा लिया, जिस कारण माकपा कार्यकर्ताओं को घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। हकीकत यह है कि नंदीग्राम में सेज के मुद्दे पर माकपा को तृणमूल समर्थकों के विरोध के आगे पीछे हटना पड़ा। इससे भी इंकार नहीं कि इस लड़ाई में कुछ माकपा कार्यकर्ताओं को भागने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसका 'बदला' लेने के लिए माकपा ने जो किया, उसकी उम्मीद कम से कम चुनी हुई सरकार से नहीं कर सकते। एक मुख्यमंत्री के लिए राज्य के सभी लोग अपने हैं, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जनता को 'उन लोगों' और 'अपने लोगों' में बांट दिया! ऐसे मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? इसके ब्योरे

हैं कि दुर्गा पूजा के बाद तृणमूल समर्थकों को सबक सिखाने के लिए बाकायदा योजना बनाई गई। कानून-व्यवस्था में विश्वास करने का दावा करने वालो वामपंथियों ने खूंखार अपराधियों की टीम बनाई। पुलिस को चुपचाप रहने का निर्देश दिया गया। माकपा का झूठ देखिए। उसका दावा है कि नंदीग्राम में बाहर से माओवादियों ने आकर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन राज्य के गृह सचिव बता रहे हैं कि न तो वहां किसी माओवादी की गिरफ्तारी हुई है और न ही किसी की शिनाख्त हुई है। हां, वहां सीआरपीएफ के छापे में हथियार और बारूदी सुरंग जरूर बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल की वाम मोरचा सरकार की छवि इस खून-खराबे से जितनी खराब हुई है, उतनी तीन दशक में शायद ही कभी हुई हो। लेकिन सबसे ज्यादा क्षति खुद मुख्यमंत्री की छवि को पहुंची है। दिग्गज कवि सुकांत भट्टाचार्य के इस भतीजे को माकपा का सांस्कृतिक चेहरा कहा जाता था। अपनी ही सरकार की बर्बरता के खिलाफ 'दुःसमय' नाम से नाटक लिखकर और उसका सार्वजनिक मंचन कर मंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कभी सनसनी फैला दी थी। विडंबना देखिए, उनके मुख्यमंत्री काल में राज्य में सचमुच दुःसमय लौट आया है।

दैनिक ट्रिब्यून, 15 नवंबर 2007

लाठी-गोली की सरकार!

नंदीग्राम में जो कुछ हुआ, उस पर कानून-व्यवस्था के शासन में विश्वास रखने वाले किसी भी सभ्य आदमी का सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के साहित्यकार की छवि वाले मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि नंदीग्राम में कुछ नहीं हुआ, बस उनके कार्यकर्ताओं ने विरोधियों को उन्हीं की मुद्रा में भुगतान कर दिया। मुख्यमंत्री सरीखे संवैधानिक और जिम्मेदार पद पर बैठे किसी व्यक्ति का ऐसा बयान सर्वथा आपत्तिजनक तो है ही, सत्ता

की संवेदनहीनता का सबूत भी है। नंदीग्राम में क्या हुआ? डकैतों के किसी गिरोह ने नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में सरकार का नेतृत्व कर रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम के पूरे इलाके पर धावा बोल दिया। मर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया तो महिलाओं से बलात्कार किया गया। घरों में लूटपाट और आगजनी भी की गयी। इसके बावजूद एक मुख्यमंत्री, जिसे इस घटनाक्रम पर शर्मिंदा होना चाहिए, कह रहा है कि हमने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। बुद्धदेव वही मुख्यमंत्री हैं, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी करते हैं। साहित्यकार तो वह कहे ही जाते हैं, आर्थिक उदारीकरण के प्रति उनके उदार नजरिये की चर्चाएं भी अक्सर होती रहती हैं। नंदीग्राम पर उनकी टिप्पणी इन छवियों को चूर-चूर कर देती है।

नंदीग्राम में हत्या और बलात्कार की घटनों को विरोधियों से हिसाब चुकता करने के नजरिये से देखने वाले बुद्धदेव से इन अनुत्तरित सवालों के जवाब नंदीग्राम ही नहीं पूरा देश जानना चाहेगा। उन्होंने कहा है कि हमने विरोधियों को उन्हीं की मुद्रा में भुगतान कर दिया। सवाल है कि विरोधी कौन, क्योंकि नंदीग्राम में जान और इज्जत गंवाने वाले पुरूष और महिलाएं तो गरीब ग्रामीण हैं। जिनकी रोजी-रोटी का ठिकाना नहीं, वे भला सत्ता धारी दल से टकराने की सोच भी कैसे सकते हैं? अगर उनका इशारा जमीन के जबरन अधिग्रहण का विरोध करने के लिए बनायी गयी भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति से है तो माकपा के कहर का शिकार समिति के अगुवा हरगिज नहीं बने हैं। यह भी क्या संसद से सड़क तक लोकतंत्र का ढोल पीटने वाली माकपा लोगों से विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लेना चाहती है? बुद्धदेव ने नंदीग्राम में हत्या और बलात्कार का नंगा नाच करने वालों को अपना तो मान लिया है, अब उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हथियारबंद अपराधी गिरोह की तरह आचरण करने का अधिकार संविधान का कौन-सा अनुच्छेद देता है? बुद्धदेव ही नहीं माकपा के महासचिव प्रकाश करात ने भी फरमाया है कि समिति वालों ने माकपा कार्यकर्ताओं को नंदीग्राम से खदेड़ दिया था, हमने अपनी जगह वापस पा ली है। अकसर गरीब किसान-मजदूरों का हितैषी होने का दम भरने वाले

करात बताएंगे कि राजनीति में जगह जनसेवा से बनायी और पायी जाती है या फिर गोली-लाठी के बल पर?

आखिर यह जमीन और जनता से कटी राजनीति का दोगलापन नहीं तो और क्या है कि आप शेष देश में सेज या अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध करेंगे, लेकिन अपने यहां औद्योगीकरण के लिए जमीन अधिगृहीत करने के लिए किसानों को न सिर्फ धमकाएंगे, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के अपराधी गिरोहों से इस कदर उत्पीड़ित भी कराएंगे कि वे घर-गांव छोड़कर पलायन को मजबूर हो जायें। इससे भी दुखद यह है कि नंदीग्राम के हृदयविदारक शर्मनाक घटनाक्रम पर भी सिर्फ और सिर्फ बेशर्म वोट राजनीति हो रही है। एक ममता बनर्जी ही हैं जो इस मसले को न सिर्फ ईमानदारी, बल्कि भावनात्मक प्रतिबद्धता से भी उठा रही हैं और इस संघर्ष में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल भी नंदीग्राम हो आया है और पार्टी संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी। नंदीग्राम पर सबसे विचित्र स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। इस नाते उसे इस पर आक्रामक रूख अख्तियार करना चाहिए? लेकिन अपने नेतृत्ववाली केंद्र सरकार वाम दलों, खासकर माकपा के रहमोकरम पर निर्भर होने के चलते प्रियरंजन दासमुंशी के अलावा सारे कांग्रेसी मौन हैं। और भी शर्मनाक बात यह है कि परमाणु करार पर वाम दलों के तेवरों से तंग कांग्रेस नंदीग्राम को ले कर माकपा से समझौते के मूड में है। यह घटनाक्रम बताता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनीतिक दल और नेताओं के सरोकार कितने बौने हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में अंततः मतदाता ही सर्वोपरि होता है और वह अतीत में कई मौकों पर अपनी सजगता और समझदारी से यह साबित कर चुका है।

जनसत्ता

नंदीग्राम के गुनहगार

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की छवि एक संवेदनशील राजनेता की रही है। मगर नंदीग्राम की हिंसा पर उनके ताजा बयान से यह धारणा पुष्ट नहीं होती और न ही इससे पता चलता है कि वे अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों को लेकर गंभीर हैं। नंदीग्राम पर कब्जे की अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मुहिम को उन्होंने जायज ठहराया है, इस तथ्य के बावजूद कि इसके चलते कई व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बुद्धदेव की दलील है कि चूंकि नंदीग्राम महीनों से भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति की आड़ में सक्रिय नक्सलियों के नियंत्रण में था इसलिए माकपा के लोगों ने जो किया वह ठीक किया। पार्टी के दूसरे नेता भी नंदीग्राम पर धावा बोलने वाले अपने लोगों के बचाव में बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि इस इलाके पर नक्सली संगठनों ने कब्जा कर रखा था। अगर यह सही हो तो भी कई सवाल उठते हैं। माकपा के लोगों ने नंदीग्राम में जो आतंक मचाया क्या वह लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले संगठन का काम है? क्या माकपा को सब कुछ करने की छूट इसलिए मिल जाती है कि उस पर नक्सली होने का ठप्पा नहीं लगा है? सवाल यह भी है कि अगर पार्टी की हथियारबंद भीड़ को ही शांति कायम करनी है तो बुद्धदेव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसलिए बैठे हैं? अगर नंदीग्राम में कई महीनों से अराजकता चली आ रही थी, जैसा कि मुख्यमंत्री का कहना है, तो इस स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी किसकी थी?

माकपा को ये सवाल चुभते नहीं हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल में पार्टी और राज्य का फर्क काफी धुंधला हो चुका है नंदीग्राम इसका ताजा और सबसे डरावना उदाहरण है। विचित्र है कि माकपा नेताओं को जिस घटना पर अफसोस होना चाहिए था उसका वे औचित्य ठहरा रहे हैं। हां, उन्हें यह बात जरूर अनुचित लगी कि नंदीग्राम को लेकर राज्यपाल ने क्यों अपनी चिंता जता दी। लेकिन क्या वजह है कि

नंदीग्राम को लेकर माकपा के सहयोगी दल भी उससे क्षुब्ध हैं। वामपंथी विचारधारा या रूझान के तमाम बुद्धिजीवियों ने तो खुल कर राज्य सरकार और माकपा नेतृत्व के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। यही नहीं, कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि एक से ग्यारह नवंबर के बीच नंदीग्राम में जो हुआ उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज है। न्यायालय ने इस आरोप का भी संज्ञान लिया कि हिंसा की घटनाओं के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मीडियाकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को नंदीग्राम में प्रवेश करने से रोकने की कोशिशों पर सख्त एतराज जताते हुए अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग वहां बिना भय के जा सकें और सुरिक्षत लौट सकें। कैसे राज चलाना चाहिए इसका पाठ देश भर को पढ़ाने वाली माकपा को आज अदालत से फटकार मिल रही है। विडंबना यह है कि फिर भी उसके नेता कोई सबक सीखने को तैयार नहीं दिखते। वे इस पर खुश हैं कि नंदीग्राम को 'फतह' कर लिया है। यह कब समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खो दिया है! माकपा नेतृत्व इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि प्रियरंजन दासमुंशी ने नंदीग्राम की हिंसा की तुलना गुजरात दंगों से कर दी। सही है कि इस तरह की तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि गोधरा के बाद हुआ नरसंहार बहुत बड़ा था। लेकिन राजसत्ता की मदद से बदला लेने और सबक सिखाने के जिस रास्ते पर माकपा चल रही है वह किधर ले जाता है?

जनसत्ता : 9.11.07

फिर नंदीग्राम

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले का नंदीग्राम अब भी रणक्षेत्र नजर आता है तो इसके पीछे इस इलाके को लेकर माकपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई है। किसी इलाके को अपने गढ़ के रूप में देखने और वहां अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने की जो राजनीतिक संस्कृति इस

राज्य में विकसित हुई है, नंदीग्राम उसका ताजा और शायद सबसे बुरा उदाहरण है। पिछले दस महीनों से इसकी तस्वीर हिंसा से ग्रस्त इलाके की बनी हुई है। नंदीग्राम पहली बार इस साल जनवरी में सुर्खियों में आया जब विशेष आर्थिक क्षेत्र की निर्माण परियोजना के तहत हल्दिया विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किए थे। स्वाभाविक था कि इसके विरोध में इलाके के किसानों और दूसरे लोगों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया। इस आंदोलन में तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चे से बाहर के वामपंथी संगठन भी कूद पड़े। परियोजना के विरोध में मुहिम चलाने के लिए भूमि प्रतिरोध उच्छेद समिति बनाई गई। लेकिन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य तब प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हर हाल में देखना चाहते थे। इस सिलसिले की दुखद परिणति चौदह मार्च को सामने आई जब पुलिस की गोलियों से चौदह लोग मारे गए। इस गोलीकांड की वजह से राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ा और उसने विशेष आर्थिक क्षेत्र की परियोजना वापस ले ली। कायदे से इसके बाद अशांति और टकराव की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। मगर यह न सिर्फ जारी है बल्कि नंदीग्राम के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां राज्य पुलिस के बजाय केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तैनात करने की बात होने लगी है। मंगलवार को माकपा और भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के बीच हुए हिंसक टकराव ने तीन लोगों की जान ले ली। इसके दूसरे रोज भी एक दूसरे पर हमले की घटनाएं हुईं। यह सिलसिला कब थमेगा, कोई नहीं जानता।

यह हैरत की बात है कि भूमि अधिग्रहण न करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नंदीग्राम सुलगता रहा है। दरअसल यह क्षेत्र माकपा का गढ़ है और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके सैकड़ों समर्थक अचानक विरोधी खेमे में चले गए। वह अपने पुराने प्रभाव क्षेत्र में फिर से पैर जमाने के लिए बेचैन है भले हिंसा का सहारा क्यों न लेना पड़े, तो दूसरी ओर भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति ने नंदीग्राम को अपना दुर्ग बना रखा है जिसमें प्रवेश के लिए उसकी मर्जी जरूरी है। मुख्यमंत्री नंदीग्राम में शांति कायम करने की अपील कई बार कर चुके हैं। मगर किसी भी पक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। माकपा के राज में राज्य और पार्टी का फर्क धुंधला हो चुका है और इसका

नतीजा सबसे ज्यादा पुलिस के कामकाज में दिखाई देता है। चौदह मार्च के गोलीकांड को लेकर ये आरोप लगे थे कि भीड़ पर गोली चलाने में पुलिस के भेष में माकपा के लोग भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद भी पार्टी यह जताने में नहीं चूकी है कि अपने विरोधियों को सबक सिखाने में वह कहां तक जा सकती है। हाल की हिंसा के संदर्भ में खुद राज्य के गृह सचिव की यह टिप्पणी है कि गोलियां उस इलाके की तरफ से चली जो माकपा के कब्जे में है। माकपा कहती रही है कि उसका मकसद बस नंदीग्राम को अराजकता और नक्सलियों के आंतक से बाहर निकालना है। सवाल है कि फिर वह सीआरपीएफ की तैनाती के सुझाव का विरोध क्यों कर रही है? पिछले दस महीनों में यह कई बार जाहिर हो चुका है कि राज्य पुलिस का व्यवहार निष्पक्ष नहीं रहा है। लेकिन केन्द्रीय बल की तैनाती काफी नहीं होगी। नंदीग्राम के हालात सामान्य बनाने के मकसद से मुख्यमंत्री को फौरन सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा, 15.11.2007
संपादकीय

मरघट की शांति

नंदीग्राम प्रकरण में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का आधिकारिक बयान चिंताजनक है। तीस गांवों के इस विवादास्पद इलाके में हफ्ता भर हिंसा और रक्तपात का तांडव जारी रहा। राज्य का जो पुलिस बल वहां भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति और जिला प्रशासन के बीच हुए समझौते के तहत विस्थापित माकपा समर्थकों के पुनर्वास के लिए भेजा गया था, वह मूक दर्शक बना रहा और राज्य भर से जुटाए गए दल-बल के साथ वहां पहुंचे माकपा समर्थक अपने वास्तविक या काल्पनिक विरोधियों को चुन-चुनकर ठिकाने लगाते रहे। इस दौरान बाहर से किसी भी राजनेता को, यहां तक कि मेधा पाटकर सरीखी सामाजिक कार्यकर्ता को भी इलाके में घुसने नहीं दिया गया। महामहिम राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने प्रकरण को नंदीग्राम में

कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो जाने के समतुल्य बताते हुए इस पर खेद जताया, कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसका औचित्य बताने वाले सरकारी वकील को डांट पिलाई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस घटना को लेकर एक शिकन तक नहीं थी। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने नंदीग्राम में विस्थापितों के पुनर्स्थापित हो जाने और शांति बहाल हो जाने को लेकर खुशी जताई और इस दौरान हुई 'कुछ दुखद घटनाओं' का ठीकरा केंद्र सरकार पर यह कहते हुए फोड़ दिया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियां वहां काफी देर से पहुंची। जब उनसे पूछा गया कि नंदीग्राम में मरघट की शांति लौट आई तो, तो जरा भी झेंप दिखाने के बजाय उन्होंने तुर्की-ब-तुर्की तर्ज पर ईंट के जवाब में पत्थर की तरह यह सवाल उछाल दिया कि अभी तक वहां जो था वह क्या स्वर्गिक शांति का कोई नमूना था! ऐसे जवाब स्कूल-कॉलेज स्तर पर होने वाली वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के मंच पर जमते हैं, जहां आपका मकसद अपने प्रतिपक्षी की बोलती बंद करा देना होता है। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हिंसा-प्रतिहिंसा के बहुत लंबे खिंचे दौर में आपके राज्य के कोई गुंडे-मवाली नहीं, अपने खेत, अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए लड़ रहे हों तो इस प्रसंग में आपका इस तरह का स्वर आपके पूरे राजनीतिक-वैचारिक इतिहास पर पानी फेरकर आपको एक पिद्दी से खलनायक में बदल देता है। देश में अब तक बहुत कम ही लोग ऐसे रहे होंगे जो एक राजनेता के रूप में बुद्धदेव भट्टाचार्य को नापसंद करते रहे होंगे। भारतीय राजनीति में दुर्लभ हो चुकी सादगी, कलावंतता और व्यक्तिगत ईमानदारी उनकी पहचान रही है। वे स्वयं कवि हैं और बांग्ला के अद्वितीय आधुनिक जनवादी कवि सुकांत भट्टाचार्य के भतीजे हैं। लेकिन उनके इन सारे अनुकरणीय सद्गुणों और श्लाघनीय पृष्ठभूमि का अब हम क्या करें? हमारे सामने तो उनकी जगह पर बैठा हुआ एक ऐसा मुख्यमंत्री है, जिसके लिए इतने सारे लोगों की भयानक मौत सिर्फ अपनी पार्टी की सियासत चढ़ने-उतरने का एक महत्वहीन प्रसंग भर है। उनकी पार्टी राज्य में तीस साल से राज कर रही है लेकिन नंदीग्राम में मात्र तीन दिनों की अवधि में उसने जो कुछ खोया है उसकी भरपाई वह आने वाली सदियों में भी नहीं कर पाएगी।

नंदीग्राम में मचा कोहराम

पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार नंदीग्राम में भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति से जुड़े लोगों पर माकपा के हथियार बंद कार्यकर्ताओं के हमले को भले ही ठहराए, लेकिन सभ्य समाज में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नही दी जा सकती। (बीयूपीसी) के नेतृत्व में नंदीग्राम में पिछले कुछ महीनों से चलाए जा रहे अभियान के कारण प्रशासनिक और विकास कार्यों में बाधा आई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि माकपा की कथित 'लाल सेना' कानून और व्यवस्था आने हाथ में ले ले। नंदीग्राम में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी माकपा सरकार की है। उसे समय रहते केन्द्र सरकार की मदद लेनी चाहिए थी। केन्द्र की मदद ली तो गई, लेकिन तब जब माकपा के तथाकथित गुंडे बीयूपीसी से छीने गए क्षेत्रों में लाल झंडे गाड़ चुके थे। बुद्धदेव सरकार के यह अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह हथियारबंद कार्यकर्ताओं को तैयार कर उन्हें भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के सदस्यों पर हमला करने की खुली छूट दे दे। सीपीएम कार्यकर्ताओं की तथाकथित गुंडगर्दी का काफी विरोध हुआ। माकपा की सहयोगी आरएसपी के एक मंत्री ने इस्तीफा देने की बात कह दी। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने भी इसे सरकार द्वारा प्रायोजित करार देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई।

आठ महीने पहले नंदीग्राम में हुई हिंसा की शुरूआत से पहले शायद ही इस छोटे से कस्बे को पश्चिम बंगाल से बाहर लोग जानते हों। सेज के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे लोगों पर १४ मार्च २००७ को पुलिस फायरिंग में हुई १४ लोगों की मौत ने इसे सुर्खियों में ला दिया। भीड़ पर पुलिस फायरिंग की खबर हर राष्ट्रीय अखबार व टीवी चैनल की पहली थी। पूरा घटनाक्रम नंदीग्राम की दस हजार एकड़ जमीन पर सेज की स्थापना व केमिकल हब बनाने के मुद्दे पर शुरू हुआ था। सेज की स्थापना मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य

की उस पहल का हिस्सा है जिसमें उन्होंने माकपा शासित पश्चिम बंगाल का औद्योगिकीकरण करने की शुरूआत की है। लोगों के विरोध को देखते हुए सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने की योजना तो स्थगित कर दी, लेकिन १४ मार्च की उस घटना के बाद से ही नंदीग्राम अक्सर सुर्खियों में रहता है।

चलिए एक क्षण के लिए सेज और आर्थिक सुधारों को भूल जाइए। पिछले सप्ताह नंदीग्राम में जो कुछ हुआ वह हमें सोवियत रूस में स्टालिन के दिनों और चीन में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौरान लाल सेना के हथियार बंद कार्यकर्ताओं ने आतंक मचाया। मोटरसाईकिलों पर सवार माकपा के हथियार बंद कार्यकर्ता रात को नंदीग्राम के पास खेजूरी में इकट्ठा हो शुरू हुए।

अपुष्ट खबरों के मुताबिक करीब चार सौ हथियारबंद कार्यकर्ता वहां एकत्र हुए। हथियार और गोला-बारूद मेटाडोर में भरकर लाए गए और ईंट के भट्टों में छिपकर रखे गए। यह वही ईंट भट्टा था जहां १४ मार्च को हुई पुलिस फायरिंग के बाद सीबीआई ने दस माकपा कार्यकर्ताओं को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। हथियारों के साथ आए इन कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि सीआरपीएफ के आने से पहले उन्हें बीयूपीसी से जितनी हो सके ज़मीन फिर से हासिल करनी है। उन कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया था कि इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा और इसलिए काम में किसी की मौत हो गई तो उसके परिवार का ध्यान रखा जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि लाल सेना के कथित गुंडे मरो या मारो की तर्ज पर भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। रातभर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली प्रतिरोध समिति को पीछे धकेलते हुए करीब ४० से ४५ फीसदी जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया गया। सुत्रों की माने तो माकपा के स्थानीय नेताओं ने पुलिस थानों में जाकर तामीद की थी कि हिंसा होने की स्थिति में कोई विशेष प्रसास नहीं किए जाएं। इस प्रयोजित हमले के पूरे होने के बाद माकपा कार्यकर्ताओं ने बकायदा परेड निकाली।

माकपा और उसके सहयोगियों को भले ही इस बात का अहसास नहीं हो, लेकिन वे जनता की काफी नाराजगी झेल रहे है। नंदीग्राम इस नाराजगी की जड़ है। उन्हें देर सबेर होने वाले चुनावों में जनता

का गुस्सा झेलना ही है। विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव अभी महज डेढ़ साल दूर है। अगर माकपा का यही रवैया रहा तो चुनाव जल्दी भी हो सकते है। अब भी वक्त है। माकपा नहीं संभली तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

नंदीग्राम में रेप पर शबाना चुप क्यों है : बीजेपी

नंदीग्राम की महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप के खुलासे के बाद बीजेपी ने गुजरात में पार्टी व मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को अक्सर घेरने वाले ऐक्टिविस्ट और कलाकारों को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने सवाल किया है कि खुद को महिलाओं की अलमबरदार कहने वाली एक्ट्रेस व सांसद शबाना आजमी नंदीग्राम में महिलाओं के साथ रेप पर शांत क्यों है। नंदीग्राम की एक महिला ने मीडिया के सामने खुलासा किया है कि मेरी दो बेटियों और मेरे साथ सीपीएम काडर ने रेप किया। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने नंदीग्राम में रेप के इस खुलासे पर कहा कि पार्टी नंदीग्राम में महिलाओं व गरीब किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कोलकाता में सड़कों पर उतरने के लिए कलाकारों और बुद्धिजीवियों की सराहना करती है। लेकिन खुद को ऐक्टिविस्ट कहने वाले कलाकारों की चुप्पी पर हैरान भी है। गुजरात के सवाल पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने वाली ऐक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ एंड कंपनी नंदीग्राम पर चुप क्यों है। शबाना आजमी और जावेद अख्तर अभी कुछ क्यों नहीं बोल रहे। रेप पीड़ित महिलाओं के खुलासे के बाद अब साफ हो गया है कि नंदीग्राम में सीपीएम काडर बलात्कार में शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल और केन्द्र सरकार दोनों ही जिम्मेदार : राजनाथ सिंह

नन्दीग्राम की विस्फोटक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही आम आदमी की समस्याओं का समाधान करने में बुरी तरह विफल रहे हैं और उन्होंने लोगों को हिंसा पर उतारू मार्क्सवादी समर्थकों की दया पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ''मुझे सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि नंदीग्राम में एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहां सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं की निरंतर जारी हिंसा के कारण सैकड़ों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।''

पश्चिम बंगाल सरकार की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि जिस ढंग से मार्क्सवादी हिंसा का वातावरण खड़ा कर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ''नंदीग्राम की हिंसा के कारण वामपंथी पार्टियों का चेहरा खुलकर सामने आ गया कि उन्हें आम आदमी की जरा भी चिंता नहीं है और वे उनके प्रति एकदम असंवेदनशील बनकर मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि पश्चिम बंगाल सरकार एक तरह से विस्फोटक बारूद पर बैठी हुई हैं। पश्चिमी बंगाल के लोगों ने भारत के इतिहास में पहले ही बदतर किस्म के दंगों को देखा है और राज्य की पूरी की पूरी स्थिति कानून और व्यवस्था के भंग होने को दर्शाती है और यह इस सरकार का ज्वलंत उदाहरण भी पेश कर रही है कि वह समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त खाद्य भी मुहैया

कराने में असमर्थ है।''

भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से कहा कि नंदीग्राम के हालात काबू से बाहर हो गए हैं। सीपीएम का कैडर गरीब जनता को मार काट रहा है पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। श्री सिंह ने कहा कि नंदीग्राम सीपीएम की डिक्टेटरशिप का सूचक है। सीपीएम के कैडर के हमले के कारण करीब २० हजार परिवार अपने घर छोड़कर भूखे प्यासे खुले में रहने को मजबूर हैं। प. बंगाल सरकार लोगों की कोई सहायता नहीं कर रही है।

श्री सिंह ने कहा कि राज्य के हालात बेहद खराब हो चुके हैं इसलिए हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए।

श्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ''नंदीग्राम की स्थिति पूरी तरह से प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर हो गई है जिससे अनेक निर्दोष लोगों के प्राण पहले भी गंवा दिए गए हैं और नंदीग्राम बेमिसाल खूनखराबे का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है।'' उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा पूरी तरह से किसानों और ग्रामवासियों के साथ अपनी एकजुटता प्रगट करती है जो राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की कि नन्दीग्राम तथा आस-पास के क्षेत्रों को फिर से सुरक्षित उनके घरों को वापस लौटाया जाए जिन्हें हथियार बंद गुण्डों की हिंसा के कारण अपना घर बार छोड़ना पड़ गया था और इस समय चल रहे नरसंहार को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ''तुरंत ही नंदीग्राम के घेराव को हटाया जाना चाहिए और केन्द्र को सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और घायल तथा मृतकों को समुचित रूप से मुआवजा दिया जाए।''

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इतिहास में नंदीग्राम होगा टर्निंग पाइंट

yky Ñ".k vkMok.kh

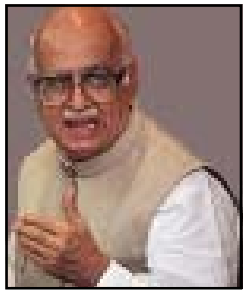

गत 21 नवंबर को नंदीग्राम के मुद्दे पर लोकसभा में हुई बहस के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सारगर्भित भाषण दिया। प्रस्तुत है संपादित अंश :–

आज प्रातःकाल जब मैंने अखबार खोला और देखा कि प्रधान मंत्री ने नन्दीग्राम के बारे में क्या कहा है, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि विदेश जाते हुए उन्होंने वायुयान से इस प्रश्न के महत्व की ओर पूरे देश का और संसद का ध्यान आकृष्ट किया है। एक प्रकार से उनका यह वक्तव्य इस बात पर भी बल देता है कि इस प्रकार के प्रश्न पर संसद चर्चा करे, यह स्वाभाविक है और जरूरी है।

उन्होंने कहा है कि - "I sincerely hope that the State Government will be able to take necessary steps to restore confidence in the people through the effective deployment of security forces. I understand the spontaneous outpouring of grief and anguish over the issue as expressed by artists and intellectuals in Kolkata. I hope the State Government will take note of this." मुख्य मंत्री ने एक रिस्पांस भी दिया है, चाहे पार्टी ने कोई और रिस्पांस दिया हो। यहां पर उसकी

अभिव्यक्ति हो जायेगी कि जो पार्टी वहां पर शासन कर रही है, वह मुख्य मंत्री के रिस्पांस से संतुष्ट है या पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, उससे संतुष्ट है। लेकिन आपने इस चर्चा के लिए जो गाइडलाइंस अपनी ओर से बताईं, मैं उनका पूरा पालन करने की कोशिश करूंगा।

मैं चाहूंगा कि इस चर्चा का उपयोग केवल एक-दूसरे पर मात्र प्रहार करने के लिए न हो, बल्कि इस प्रकार की स्थिति कहीं पर भी, कभी भी पैदा न हो, इसका क्या प्रबंध किया जा सकता है, यह एक चिंता की बात है। मैं समझता हूं कि यह नन्दीग्राम में जाने पर सहज रूप से सबको लगे। यह एक साधारण बात नहीं है। वहां की घटना कोई अभी की घटना नहीं है, जो अक्टूबर, नवम्बर में हुई। यह घटना वहां कई महीनों से चल रही है। वहां पर जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है, उसकी शुरूआत वर्ष के आरम्भ में हुई थी और मैं स्वयं मार्च के महीने में वहां गया था और अबकी बार फिर से पिछले सप्ताह गया। दोनों बार की मेरी यात्रा में पूरे एन.डी.ए. की कई पार्टियों के मेरे साथी मेरे साथ गये थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा अंतर था कि जब मैं मार्च के महीने में वहां पर गया तो बहुत सारे लोग हमसे आकर मिलते थे, बातें करते थे और खुलकर बताते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। इस बार एक आतंक का एक ऐसा वातावरण था कि अगर कोई आकर मिलता था तो उसे रोकने वाले उसके परिवार के ही लोग होते थे। मेरे साथ दूसरे सदन से सुषमा जी भी साथ गई थीं तो उनसे जब महिलाएं मिलती थीं और बलात्कार की चर्चा करती थीं तो एक महिला को उसके घर का लड़का उठाकर ले गया कि ऐसा क्यों करती हो?

अपना नाम मत बताना, किसी टी.वी. वाले को या किसी प्रैस वाले को अपना फोटो मत लेने देना। यह जो आतंक का वातावरण इस बार मैंने देखा, उसके कारण मुझे लगा कि इस बार का मामला बहुत गंभीर हो गया है। कैसे हुआ है, उसका थोड़ा सा उल्लेख मैं करूंगा। मैंने जैसा कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि यह केवल एक-दूसरे को दोष देने का एक प्रकरण बन जाए। यहां तक कि मैं अपने साथियों को भी कहूंगा। मुझे आकर वामपंथी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि आप लेफ्ट मत कहिए। आप सीपीएम का नाम लीजिए। आप लेफ्ट मत कहिए। मुझे ऐसा कहने वाले इस लेफ्ट एलायंस के अलग-अलग पार्टियों के

लोग हैं।

मैं इस बात पर आता हूं कि मैं जहां प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं वहीं मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा कि पहले दिन से लेकर यानी परसों का जो दिन था, सोमवार के दिन यहां सेन्ट्रल हॉल में श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए थे और सदन के नेता से तब मेरी पहली बात हुई। मैंने कहा कि नंदीग्राम के संदर्भ में एनडीए ने तय किया है कि हम एक स्थगन प्रस्ताव देंगे जो कि हमने दिया और अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा था कि स्थगन प्रस्ताव तो हो सकता है in respect of the failure of the Central Government, it cannot be in respect of the failure of a State Government. मैंने कहा कि सही बात है और उसकी ड्राफ्टिंग मैंने उसी हिसाब से करके अध्यक्ष जी को दिया था। मैं नहीं जानता हूं कि वह एडमिट होगा या नहीं होगा। उस पर सदन में कितने लोग समर्थन में खड़े होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैंने अपने सहयोगी मल्होत्रा जी को यह भी कहा कि आप अध्यक्ष जी को यह भी बता दें कि हमारा कोई विधा पर आग्रह नहीं है। डिवाइस एडजर्नमेंट मोशन हो, इस पर आग्रह नहीं है। हमारा इस बात पर आग्रह है कि नंदीग्राम की चर्चा सदन में जरूर होनी चाहिए। वह चाहे किसी रूप में हो।

मुझे इस बात का संतोष है कि कल और परसों जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, वह गतिरोध अब समाप्त हो गया है और इस विषय पर मैं चर्चा शुरु कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऑब्वियसली यह कहूंगा कि जो बात कही गई कि किसी सूरत में इस चर्चा के लिये नन्दीग्राम नाम नहीं आयेगा, तब मैंने कहा कि अगर किसी सूरत में नन्दीग्राम नाम नहीं आयेगा तो गतिरोध किसी सूरत में समाप्त नहीं होगा। मुझे खुशी है कि नन्दीग्राम का नाम इसमें आया है, चाहे जिस ढंग से आया हो। I would have liked it to be different. We are not discussing only SEZs. What has happened in Nandigram goes far beyond the issue or different view points on the question of SEZ. हम लोग SEZs पर डिसकशन कर चुके हैं लेकिन पार्लियामेंट में डिसकस हो,इसलिये कोई न कोई ऐसा पहलू हो चाहे सीआरपीएफ लायें, चाहे

SEZs लाया जाये या कोशिश यह हुई कि नन्दीग्राम का उल्लेख किये बिना, चाहे देशभर में नक्सलवाद की समस्या हो, देश में फार्मर्स की समस्या हो, तब मैने कहा कि अगर ऐसा करना हो तो गतिरोध समाप्त करने का यह कोई तरीका नहीं है। मुझे इसलिये खुशी है कि जिस-जिस ने इस ड्राफ्ट को बनाने में योगदान दिया, मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

अगर इस सदन में नन्दीग्राम पर चर्चा नहीं होती तो न केवल नन्दीग्राम में, न केवल पश्चिमी बंगाल में लेकिन देश के बहुत सारे भागों में बहुत लोगों में यह भावना होती कि नन्दीग्राम जैसा बड़ा कांड हो और संसद में उस पर चर्चा न हो। They do not understand the rules. But the fact is that if this discussion had not taken place, it would have lowered the Parliament in the esteem of the people of the country. इसलिये संसद के सम्मान के लिये आवश्यक है कि यदि इस प्रकार की घटनायें कहीं भी हो, उन पर चर्चा जरूर होनी चाहिये और उस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिये। यह कोई न कहे कि NANDIGRAM शब्द उस में नहीं होगा और यहां कहा गया कि अगर यह शब्द होगा तो हम मोशन स्वीकार नहीं करेंगे।

मैं इतना कहूंगा कि यह सदन सत्य तक पहुंचना चाहेगा और हमारे यहां सत्य को 'शिव' कहते हैं। और शिव तक पहुंचने के लिये नन्दी को पार करना ही पड़ता है।

चाहे अयोध्या की समस्या होए चाहे गोधरा की समस्या हो, चाहे गुजरात के दंगे हों, यहां सदन से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे गये हैं। १९८४ के दंगों में वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन इन तीन स्थानों के लिये ऑल पार्टी डेलीगेशन गये थे। इसलिये मेरा सुझाव होगा जो आखिर में रिपीट करूंगा कि इस बार नन्दीग्राम के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिये एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिये।

जब वहां पर गए तो वहां पर एक हायर सैकेन्ड्री स्कूल है जिसको रिफ्यूजी कैम्प में कनवर्ट कर दिया गया था। गांव बिल्कुल सुनसान थे। They were deserted. Some elderly people were living there. उनसे मिलकर जितना उनसे पता लगता था, वे बताते थे। वे कहते थे कि लोग डर के मारे भाग गए हैं और बहुत सारे हमारे लोग

नन्दीग्राम टाउन में रिफ्यूजी कैम्प में हैं। वहां रिफ्यूजी कैम्प में हम गए। वहां सबसे पहले लोगों ने देखा कि संसद के सदस्य आए हैं तो भागकर कई महिलाएँ एक साथ आईं, आठ-दस होंगी, पैर पकड़कर रोने लगीं कि हमें तो खाली इतना पता लगे कि हमारे पति जीवित हैं या नहीं। हम खाली यह जानना चाहते हैं कि हमारे पति जीवित हैं या नहीं। It was such a spectacle that I felt literally miserable.… (Interruptions)

मैंने कहा कि मैं आया हूँ। फिर उन्होंने उसी समय एक इंप्रॉम्प्टू सा मंच लगाकर कहा कि आप बोलिए। कोई माइक्रोफोन ले आए। मैं उस पर बोला। It became the public meeting. But it was there that I promised them that with these happenings, I can tell them that I have come on behalf, as a Member of Parliament along with my other colleagues. We are certainly going to raise this matter in Parliament and talk about it; and through Parliament, tell the State Government that it is their duty to ensure that these queries whether their husband is alive or not, is he there or not, these should be properly tackled and answered. It happens that in the meanwhile, other things have happened. मैं आज इस बात को स्वीकार करूंगा कि साधारणतः इस संसद में कोई राज्य के मामले डिसकस नहीं होते। अगर कोई साधारण लॉ एंड ऑर्डर का राज्य का मामला माना जाए तो फिर डिसकसशन जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन क्यों जस्टिफाइड हुआए मैं इसका ज़िक्र करना चाहूंगा जिसके कारण प्रधान मंत्री को भी कहना पड़ा कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। उसमें ज़िक्र हैए मैंने क्वोट नहीं किया। लेकिन पहले जब मैंने गवर्नर का स्टेटमैंट देखा तो मैं तो चकित हो गया।

According to Shri Ashok Mitra, when he consented to become the Governor, he wanted that the leadership of the CPI(M) should be prepared to have him. He has now become the enemy. This is the word that has been used… (Interruptions)

Sir, there are three statements from various dignitar-

ies. One is, of course, the Governor's statement. I am not quoting him. He said that the happenings in Nandigram are totally unlawful and unacceptable. Then, the second one is the judgment of the High Court of Kolkata, which goes on to say that the firing took place on 14th March – this judgment has come last week – is unconstitutional and unjustified. What it has said in the body of the judgment, I do not want to quote. The third statement is this. When the CRPF has been invited to help in Nandigram, it was said that हमारी जवाबदारी पूरी हो जाएगी, वे नंदीग्राम संभाल लेंगे। According to the CPI(M) there, it was the Maoists who are indulging in violence, though the Home Secretary of West Bengal came out with a statement that there is no Maoist, there is no Maoist literally there. … (Interruptions)

Sir, the DIG of the CRPF says that he has been given one week now. Sir, he has publicly said: "I have been called here; I have been invited here; I have been asked to deal with the situation in the Nandigram, whereas I am getting no cooperation from the State Government, from the State Police Authorities".… (Interruptions)

Sir, if I were to quote, he said: "I asked the SP two days ago to provide me a list of wanted criminals, but I did not get it. I do not know why he is doing it. I have worked as an SP, and I have never seen such a behaviour." These are the words of the CRPF officer... (Interruptions)

हाईकोर्ट इसे अनकॉस्टीट्युशनल कहता हैए गवर्नर जिसे टोटली अनलॉफुल कहता है और सी.आर.पी.एफ, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वैस्ट कर के केन्द्रीय होम मिनिस्ट्री से मंगवायाए उस सी.आर.पी. एफ. का हैड कहता है कि यहां पर मुझे कोई कोआपरेशन नहीं मिलता। क्या यह गम्भीर स्थिति नहीं हैए जिस पर संसद को विचार करना चाहिएघ

Sir, I visited Nandigram, and many of the Press people, Media people accompanying me said that 'this is the first time that we have been allowed to go to Nandigram. Otherwise, it was out of bounds for us.' I was surprised to hear that 'this is because Advani has friendship with the Chief Minister.' This kind of a comment coming from the Ruling party surprised me. I did not expect this because I have had and I have tried, as the Home Minister, to maintain good relations with all the Chief Ministers in the country including many in the Congress party. That does not matter anything. I have good relations with them. Even now, I have good relations with him also. And, I was happy to find that his response to the Prime Minister's comment on Nandigram was different from the party's response. He said: "I appreciate what the Prime Minister has said."

So, these are matters about which I have only this to say that the CPI(M) must look back at the entire Nandigram episode. How it happened? When you try to convert the party into a substitute for Government, then things go out of hand. I remember, when I first visited Nandigram, the same thing was again and again mentioned that it is his people who wore police uniforms. I do not know.

An MP's name was mentioned. It was said – 'It is they who fired on us while we were doing Puja. The Muslim ladies there were reciting Quran' At that time, firing took place on them and they said that they were not policemen really, they were party men, party cadres in police uniform. … (Interruptions)

Sir, the High Court says in its operative part : "The action of the police department to open fire at Nandigram on 14th March, 2007 was wholly unconstitutional and can-

not be justified under any provision of the law".

Now, a statement of this kind, the statement given by the Governor of West Bengal and lastly the statement made by the DIG, CRPF are there. I said to the Governor when I met him along with my colleagues that : "Is this not sufficient reason why you should send a formal report to the Central Government as to what has happened in Nandigram. You have your inputs on the basis of which you have yourself said." In fact, this is not the first time that he said it. He said it for the first time in March itself, that "I have a feeling of cold horror". These are the words that he used on visiting Nandigram, a feeling of 'cold horror'.

He said : "This time, the Diwali all over the State has been dampened because of Nandigram incidents". I said : "You owe it to the Central Government and to the country to send a detailed report to the Central Government as to what are your inputs which have made you to make this public statement and on the basis of that you can recommend that in this situation, the Constitution empowers the Central Government to issue directions to the State Government under Article 355 and if those directions are not followed to correct the situation in Nandigram, then the Central Government is fully justified in invoking Article 356". … (Interruptions)

Sir, this was something that I said to the Governor which I am repeating here in Parliament. The hon. Minister of Home Affairs is here. I would like to urge him to consider this that the situation should be improved. What is happening there? The Governor said 'I am in touch with the Central Government.' … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदयए जहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि "We have paid them back in their own coin." आप इतिहास देखिए, जब

मैं पार्लियामेन्ट में पहली बार आया था, तब मार्कसिस्ट मुझे कहते थे कि आज हमारा यूरोप पर साम्राज्य है और एक समय आएगा जब जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता। कम्युनिस्ट साम्राज्य भी ऐसा होगा, जिस में कभी सूर्यास्त नहीं होगा। और देखिये, क्या-क्या हो गया। आज वह दुनिया भर से समाप्त हो गया।

सी.पी.एस.यू. की जो २०वीं कांग्रेस थी, जिसमें खुश्चेव ने वह भाषण किया थाए लाइव बस्टिंग हार्ड, याद करो कि कैसे सोवियत संघ में आपका साम्राज्य खत्म हुआ।

अध्यक्ष जी, मैं इसी संसद में था और संसदीय शिष्टमंडल में ढिल्लों साहब हमारे स्पीकर थे, उनके नेतृत्व में मैं १९७२ में चैकोस्लवाकिया गया था और चैकोस्लवाकिया में जिस प्रकार का एग्रेशन मास्को का हुआ था और डुबचैक का काण्ड हुआ था, उसके कारण वहां समाप्ति हो गई। हमारी हिस्ट्री में ये टर्निंग पाइंटस हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के टर्निंग पाइंटस इन सब बातों से आये हैं, चाहे डुबचैक का प्रकरण हो, चाहे खुश्चेव का भाषण हो, चाहे चाइना में थियानानमन स्क्वायर हो, Nandigram is going to be the turning point in the history of the Communist Party of India. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इतिहास में यह एक टर्निंग पाइंट बनेगा। अब ३-४ टापू बच गये हैं।

मैं फिर से कहूंगा कि नंदीग्राम के बारे में संसद को अधिकृत जानकारी मिले, सरकार को भी अधिकृत जानकारी मिले, इस दृष्टि से पहले-पहल तो एक ऑल पार्टी डैलीगेशन यहां से नंदीग्राम भेजा जाना चाहिए और फिर इनको मैं यह कहूंगा कि इस बीच में सरकार इस पर विचार करे कि वह इस मामले में क्या कर सकती है। खासकर हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं, जो मर गये हैं, उनको मुआवजा देना, जिनका बलात्कार हुआ है, उन महिलाओं को न्याय देना, ये सब जितने निर्देश दिये हैं, उन सब का भी पालन हो और साथ-साथ राज्यपाल को यहां बुलाकर उनसे प्रत्यक्ष पूरी जानकारी प्राप्त कर केन्द्रीय सरकार भी आवश्यक कार्रवाई करे।

मैं समझता हूं कि इसके आधार पर आप आर्टीकल ३५५ का पहले उपयोग करके फिर यदि उसका भी वे लोग पालन नहीं करते हैं तो आर्टीकल ३५६ का उपयोग करे।

पूरा गांव खड़े होकर कह रहा था -
'प्राण देबो, रक्त देबो, मान इज्जत देबो,
आमरा जमीन देबो ना, आमरा जमीन देबो ना' -

..लेकिन माकपा ने सब कुछ ले लिया

l"kek Lojkt

गत 22 नवंबर को नंदीग्राम के मुद्दे पर हुई बहस के दौरान राज्यसभा में भाजपा की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने माकपा पर जमकर प्रहार किए। हम यहां उनके भाषण का संपादित अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

उपसभापति जी, संसद का यह शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ था, तब तक नंदीग्राम व्यापक हिंसा की आग में झुलस चुका था। इसलिए यह बहुत स्वाभाविक था कि हम सबसे पहले आपसे यह मांग करते कि शुरुआत में ही नंदीग्राम पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे दुःख है और आश्चर्य भी कि हमारे CPM के साथियों ने इसे कानून-व्यवस्था का साधारण, राज्य का विषय बताकर चर्चा कराने में अपनी आपत्ति दर्ज़ कराई। उपसभापति जी, यह तो बाहर के टीवी गवाह हैं। हमारे कामरेड सीताराम येचुरी जी ने बाहर कहा कि कानून और व्यवस्था का विषय राज्य का विषय है। इन्होंने यह कहकर आपत्ति दर्ज कराई कि यह राज्य का विषय है तो मैंने यही बोला राज्य की कानून-व्यवस्था का विषय बताकर चर्चा पर आपत्ति दर्ज कराई,

इसमें मैंने गलत क्या कहा।

उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि सारा देश जिस घटना पर उद्वेलित हो, जिस घटना पर पश्चिमी बंगाल के बुद्धिजीवी कोलकाता की सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएं, जिस घटना को राज्यपाल गैर-कानूनी और अस्वीकार्य मानें, जिस घटना को कोलकाता का उच्च न्यायालय असंवैधानिक और अनुचित करार दे, क्या वह राज्य की कानून-व्यवस्था का साधारण विषय होता है? मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने विषय की गंभीरता को समझा और हम लोगों को चर्चा की अनुमति दी।

उपसभापति जी, आज हम देश में बनने वाले विशेष आर्थिक जोनों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रारंभ में आपको यह बात कह दूं कि विशेष आर्थिक जोन के बहस के आयाम बहुत बड़े हैं, उस बहस का फलक भी बहुत बड़ा है, किंतु आज विशेष आर्थिक जोन का संदर्भ नंदीग्राम के सिलसिले में केवल इतना है कि क्या उद्योगों के लिए स्थापित किए जाने के लिए कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए और यदि किसान अपनी भूमि के अधिग्रहण का विरोध करते हुए आंदोलित हों, आंदोलन करें, तो क्या हिंसा का सहारा लेकर उन्हें खदेड़ने और मारने का काम किया जाना चाहिए? उपसभापति जी, नंदीग्राम एक वर्ष में तीन बार हिंसा का शिकार हुआ है और यह एक संयोग है कि तीनों ही बार मुझे अपनी पार्टी की तरफ से नंदीग्राम जाने का अवसर मिला है। इसलिए मैं जो कुछ इस सदन में कहूंगी वह न तो सुनी-सुनाई बात है, न वह अखबारों, रिपोर्टों में पढ़ी-पढ़ाई बात है बल्कि मेरी वाणगी एक प्रत्यक्षदर्शी की वाणगी होगी, जो कहूंगी वह सच्ची, सही और आंखों देखी कहानियों पर आधारित होगी। जो कहूंगी वह सच्ची, सही और आंखों देखी घटनाओं पर आधारित होगी, कहानी नहीं है। दिक्कत यह है कि आप लोग इसको कपोल-कल्पित कहानियां समझ रहे हैं। जिस चश्मे से देखा, उसी चश्मे से रखूंगी, यहां सामने दिखाऊँगी, उस चश्मे से आपको शीशा दिखाऊँगी।

उपसभापति जी, सबसे पहले नंदीग्राम में जनवरी मास में हिंसा भड़की और मैं स्वयं अपनी पार्टी के तीन सांसदों का एक शिष्टमंडल लेकर नंदीग्राम गई। उस समय घटना का केंद्र था सोनाचूड़ा गांव।

नंदीग्राम होते हुए हम लोग सोनाचूड़ा पहुंचे। पूरा का पूरा गांव सड़क पर था – महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। वहां बैठकर एक चीज़ जो मैंने देखी, वह मैं सदन को बताना चाहूंगी।

हमने आंदोलन बहुत देखे हैं, देश में आज़ादी के बाद भी आंदोलन हुए हैं, उसके पहले के आंदोलनों की कहानियां पढ़ी हैं, नंदीग्राम का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है उपसभापति जी, जो जाति, धर्म, लिंग और उम्र की सीमाओं को पार कर गया है। इन हदों को उसने तोड़ दिया है। हिंदू-मुस्लिम, दलित-सवर्ण, महिला-पुरुष, बूढ़े-नौजवान और बच्चे, सब के सब इस आंदोलन के सांळीदार हैं। वहां एक तख्त बिछा था, वहां जाकर हम बैठ गए। एकदम से एक विशाल जनसभा का स्वरूप बन गया। ७० प्रतिशत उसमें महिलाएं थीं, ७० प्रतिशत से ज्यादा। हर महिला उंगली पकड़े हुए थी बच्चे की या दूध पीते हुए बच्चे को गोद में लिए हुए थी। कोई खौफ नहीं था उनके चेहरे पर, कोई भय नहीं था, उनके चेहरे पर केवल एक इच्छा दिखाई देती थी, अपनी ज़मीन को बचाने की। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने वहां 'भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का गठन किया है कि पूरा का पूरा गांव अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उसका सदस्य बन गया है और पूरी जनसभा में दो नारे थे – पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और उस समय के सी.पी.एम. के सांसद का नाम लेकर, जो लोक सभा के हैं, क्योंकि वहां तीन लोगों की मौत उस हिंसा में, उस बार हुई थी जनवरी में। खड़े होकर, उन दोनों का नाम लेकर 'फांसी दो, फांसी दो' का नारा था और पूरा गांव खड़े होकर कह रहा था – 'प्राण देबो, रक्त देबो, मान इज्जत देबो, आमरा जमीन देबो ना, आमरा जमीन देबो ना' – वे एक ही बात कह रहे थे कि प्राण देंगे, रक्त देंगे, खून देंगे, मान और इज्ज़त भी दे देंगे, लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जिन तीन लोगों की मौत हुई थी, उनमें से दो के परिवारों ने आकर मंच पर ही माइक से अपनी व्यथा सुनाई थी। एक बालक मरा था, तेरह-चौदह वर्ष का। लोगों ने कहा कि उसके परिवार वाले आ नहीं सके, आप उनके घर जाइए। हम उनके घर गए थे। वह दृश्य हमें अभी भी भूलता नहीं है। इस समय भी वह बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तेरह-चौदह वर्ष का वह बालक मरा था और उस दिन

उसका छोटा भाई, जो शायद आठ-नौ वर्ष का रहा होगा, सिर मुंडाए, धोती पहने, ऊपर से नंगे बदन, एक जनेऊ लटकाए अपने भाई का श्राद्ध कर रहा था। उसकी मां दहाड़े मार-मार कर रो रही थी। मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था, शायद ज़िंदगी में पहली बार मैंने असहायता का अहसास किया था, क्योंकि उस पछाड़े खाती मां को ढाढस बंधाने के लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं थे। सोनाचूड़ा से हम लोग नंदीग्राम आए। वहां बहुत से पत्रकार खड़े थे। उन्होंने हमें कहा कि आपको खुशी होगी, नंदीग्राम के इस आंदोलन के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम के लोगों से कह दो – 'नोटिफिकेशन छेड़िदीन, छेड़िदीन' यानी कि वे नोटिफिकेशन को फाड़ दें, हमने भूमि अधिग्रहण का निर्णय वापस ले लिया है। तो मैंने उन पत्रकारों से कहा कि वे गांव वालों को क्यों कह रहे हैं कि छेड़िदीन, छेड़िदीन, नोटिफिकेशन फाड़ दो? यह तो उनके अपने हाथ की बात है, वे नोटिफिकेशन वापस ले लें। गांव वाले क्यों फाड़ेंगे? वे नोटिफिकेशन अगर वापस ले लें, तो गांव वालों को फाड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो मैंने कहा कि मैं आपके ही माध्यम से मुख्य मंत्री जी को सलाह देती हूं कि अगर उन्होंने यह निर्णय वापस ले लिया है, तो गांव वालों को आश्वस्त करने के लिए वे नोटिफिकेशन withdraw कर लें और जो withdrawal की कॉपी है, वह गांव में भेज दें। सच कहती हूं इस समय यहां कि मैं आश्वस्त होकर लौटी थी उस समय। मुझे लगा था, जितना मैं बुद्धदेव जी को जानती हूं, मेरे अच्छे स्नेहिल संबंध हैं उनसे। उन्हें मैं एक संवेदनशील व्यक्ति मानती थी, वे साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं, मुझे लगा कि यह बात अखबार में छप जाएगी और बात भी सच है कि अगर वे कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन फाड़ दो और फैसला वापस ले लिया है, तो वे नोटिफिकेशन वापस भी ले लेंगे और मैं स्वयं में आश्वस्त होकर लौटी थी, लेकिन दो महीने भी नहीं बीते, मार्च के महीने में, मिड मार्च, १४ तारीख को दोबारा नंदीग्राम में हिंसा भड़की और आधिकारिक तौर पर सरकार ने १४ लोगों के मरने की पुष्टि की।

उस समय आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे एनडीए का एक प्रतिनिधिमंडल नंदीग्राम गया। उस प्रतिनिधिमंडल में भी मैं शामिल

थी। वापस घटना का केन्द्र सोनाचूड़ा था। हम फिर सोनाचूड़ा पहुंचे। इस बार १०००-१५०० लोग मिलने के लिए आए। जो कहानी टीवी पर दिखायी जा रही थी - वह नौजवान भी हमसे मिलने आया जिसके हाथ से भाई का शव वर्दीधारियों ने छीन लिया था। वह लड़का हमसे मिलने आया। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, मेरी आंख के सामने मेरे भाई को गोली लगी। मैंने उसकी डेड बॉडी को - पता नहीं वह मरा था या नहीं - अपनी बाहों में लेकर भागना चाहा, लेकिन उसका वह शरीर भी - जो मश्त था या उस समय तक जीवित था - मेरे हाथ से छीन लिया गया। आज तक मुझे नहीं पता कि वह शरीर कहां है। वह उसके बाद मरा या जिंदा था, मेरे पास से वह ले लिया गया - मुझे नहीं मालूम वह कहां है। वहां लोगों ने यह कहा कि पुलिस तो आयी लेकिन पुलिस के साथ कोई एम्बुलेंस नहीं आयी। जिनके ऊपर गोलियां चलीं, जो घायल हो गए, उन्हें हम कंधों पर उठाकर अस्पताल ले गए या साइकिल पर एक आदमी बिठाकर अस्पताल ले गया लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं थी जिस पर हम घायलों को ले जा सकते और शायद उन्हें बचा सकते। वहां हमने उनसे पूछा कि घटना शुरू कैसे हुई? हम सुनकर हैरान हुए। वहां के लोगों ने बताया कि उस दिन गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन था। वे चैतन्य महाप्रभु का विग्रह लेकर भजन कीर्तन कर रहे थे। इतने में अचानक पुलिस आयी और दनादन-दनादन उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। वहां बच्चे और महिलाएं थीं जो कीर्तन कर रहे थे। वहां पर १४ लोगों के मरने की पुष्टि तो स्वयं सरकार ने की है। इसमें मैंने ऐसी कौन-सी बात कही जो ये लोग हँस रहे हैं? उपसभापति महोदय, जो हँस रहे हैं उन्होंने ही अपने हस्ताक्षरों से एक खुला पत्र सारे सांसदों को भेजा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में खड़े होकर कह सकती हूं कि यह खुला पत्र तथ्यों से दूर असत्य का पुलिंदा है। मैं बताती हूं कि १४ मार्च की घटना के लिए कामरेड सीताराम येचुरी ने अपने हस्ताक्षरों से इसमें क्या लिखा है। १४ मार्च की घटना का उल्लेख पृष्ठ नम्बर ६ पर है। 'Earlier, in March, when scores of offers of talks fell on deaf ears, the Government sent in a team of police to repair the roads and ensure links of Nandigram with the rest of

the State. The police were attacked." यह उन्होंने कहा है, the police were attacked. 'The police tried to pacify and disperse the crowd by appeal through loudspeakers. Then women and children were brought to the front without their consent. Armed hooligans were to the rear, as was shown on TV channels. Tear gas shells were brought, but did not have the desired effect. The appeals were ignored. In the ensuing police firing, eight people were killed; another six people were killed in other injuries. ये १४ लोगों के मरने की पुष्टि कर रहे हैं।

If this is the truth, I have one simple query to Shri Sitaram Yechury. अगर पुलिस पर आक्रमण किया गया था, अगर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस और अपने बचाव में गोलियां चलायी थीं तो १४ लोगों के मरने की पुष्टि आप कर रहे हैं, क्या एक पुलिस अधिकारी मारा गया? क्या एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ? उपसभापति जी, पुलिस वालों को खरोंच तक नहीं आयी।

उपसभापति जी, १४ मार्च की इस घटना के बाद बहुत फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ नंदीग्राम गयी थीं। ऐसी एक कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है, 'नंदीग्राम ऐंड सिंगूर - बाय जस्टिस ऑन ट्रायल' इसमें सात लोग थे, दो फॉर्मर जजिज़ थे। इन सात लोगों ने यह रिपोर्ट हमें नहीं सौंपी, तत्कालीन राष्ट्रपति डा० कलाम को सौंपी थी। जो प्रश्न मैंने किया है, वह प्रश्न जस्टिस ऑन ट्रायल ने, उन लोगों ने पूछा - 'क्वेश्चन दैट अराइज़' एक पूरा पन्ना इसमें है। उन्होंने एक सवाल पूछा है: 'If the Police acted in self-defence, how is it that १४ people have been killed and a lot many injured in the Police firing, and not a single Policeman injured?" यह सवाल आज मैं नहीं पूछ रही हूं, यह सवाल जस्टिस ऑन ट्रायल ने अपनी रिपोर्ट में पूछा है। और दूसरा सवाल पूछा है: 'When women including minors were assaulted, physically tortured and raped, why did Womens' Commission, either from the State Government or from the Centre, visited the site and not

react? Why is there no such kind of order or action taken by the State Government?" और मैंने जो बात गौरांग महाप्रभु की कही, सबसे पहले उन लोगों ने वह बात कही है, 'People of Nandigram had gathered to perform *puja* of *Gorang* on 14th March, 2007 being the birthday of *Gorang*. What was the propriety of the West Bengal Government to send on that day a huge Police force duly armed?" यह सवाल आज मैं नहीं पूछ रही हूं, ये जितनी फैक्ट्स फाइंडिंग्स कमेटीज गई हैं उन्होंने इनसे यह सवाल पूछा है। इसलिए मैंने यह कहा था कि यह तथ्यों से दूर असत्य का पुलिंदा है , मुझे ये जवाब दें कि Police were attacked, अगर पुलिस पर आक्रमण हुआ था और पुलिस वहां की रोड रिपेयर करने के लिए गई थी, जबकि रोड रिपेयर करने के लिए पुलिस नहीं जाती है। रोड रिपेयर करने के लिए पी०डब्लू०डी० के लोग जाते हैं। रोड रिपेयर करने, पुल बनाने अगर पुलिस वहां गई तो एक भी एम्बुलेंस साथ लेकर नहीं गई थी, एक भी मजिस्ट्रेट साथ लेकर नहीं गई थी, वरना हमेशा पहले मजिस्ट्रेट पुलिस फायरिंग का आदेश देता है उसके बाद फायरिंग होती है और ये कहते हैं कि Police were attacked. मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं। हम नंदीग्राम की इस पुलिस फायरिंग के बाद सोनाचूड़ा की इस घटना को देखने के बाद अस्पतालों में गए थे। Tamluk के अस्पताल में गए, नंदीग्राम के अस्पताल में गए, वहां हमें जितने लोग मिले उन्होंने जो हृदय विदारक और मर्मस्पर्शी कहानियां सुनाई थीं वे आज तक हमारा दिल दहलाती हैं। वहां मेरी दो महिलाओं से प्रत्यक्ष भेंट हुई थी जिनके साथ बलात्कार हुआ था। उनमें से एक महिला ने मुझे कहानी सुनाई थी कि पुलिस को देखकर डरकर वह अपने घर के पिछवाड़े बनी गौशाला में छिपने के लिए भागी थी लेकिन दरिन्दों ने गौशाला में भी उसका पीछा किया और वहीं उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का काम किया। मैं पूछना चाहती हूं अपनी बहन वृंदा कारत से कि वे महिलाओं के विषय को लेकर बहुत जुझारू हैं और अगर देश के किसी कोने में भी महिलाओं के साथ कोई घटना घटती है तो आप वहां जाती हैं और उसको सदन में पूरी शिद्दत के साथ उठाती हैं। तो

क्या आपकी भेंट उन महिलाओं से हुई, क्या आप एक बार सोनाचूड़ा गई, क्या आप अस्पतालों में गईं?

मैं कहना चाहती हूं कि उन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ क्योंकि यह कहा जाता है कि उनका नाम यहां नहीं लिया जाए इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं लेकिन जब मैंने वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से पूछा कि क्या इन केसेज में बलात्कार हुआ है, तो उन्होंने उसकी पुष्टि की और बताया कि इन दोनों केसेज को हमने जो यहां जब सी०बी०आई० थी उनको बतला दिया है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन उस समय वहां जाने की किसी ने जरूरत नहीं समझी क्योंकि वह पश्चिम बंगाल का केस था, क्योंकि वह नंदीग्राम और सोना चूड़ा का केस था।

उपसभापति जी, १४ मार्च की इस घटना के बाद सी०पी०एम० के लोगों की बहुत आलोचना हुई, वामपंथियों ने की, इनके सहयोगियों ने की तथा इसके खिलाफ में सम्पादकीय भी लिखे गए और संसद में भी आवाजें उठीं। उस समय मुझे यह लगा था कि चलिए, १४ लोगों की बलि तो हुई है और शायद नंदीग्राम १४ लोगों की बलि लेकर शांत हो जाएगा। मैं एक जगह बैठी थी और वहां पांच-सात लोग बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि बुरा तो बहुत हुआ, अधिकारिक तौर पर ये १४ कह रहे हैं इसलिए मैं १४ कह रही हूं जबकि वहां लोग तो सैकड़ों की बात करते थे। वहां लोग तो कहते थे कि लोगों को मारकर नदियों में डाल दिया है और उनके ऊपर चील, गिद्ध घूम रहे हैं जिससे पता चलता है कि यहां लोग मारे गए हैं। लेकिन मैं १४ की ही बात कर रही हूं क्योंकि सरकारी पुष्टि १४ लोगों की हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो कम से कम अब नंदीग्राम की भूमि के अधिग्रहण का मामता तो समाप्त हुआ और शायद इससे बाकी जगहों के एस०ई०जैड० में भी जो कृषि योग्य भूमि ली जा रही है उनका मामला भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको यह कहना चाहती हूं उपसभापति जी, अगर आपको कभी नंदीग्राम जाने का मौका मिले तो आप वहां जाकर उस भूमि के दर्शन करिए जिसे हम हरी-भरी वसुंधरा कहते हैं या बंगाली में जिसे धनधान्य वसुंधरा कहते हैं वह हरी-भरी वसुंधरा का साक्षात प्रतीक है।

वहां पान की खेती होती है, वहां धान की खेती होती है, वहां तीन-तीन फसल ली जाती हैं। चारों तरफ इतना सौम्य वातावरण, इतना रमणीक वातावरण कि आदमी की आत्मा में कुछ होता है जब यह कहा जाता है कि यह भूमि उद्योग के लिए ले ली जायेगी। इसलिए मुझे लगा कि चलिए, वह भूमि तो बची। वहां पर एक साथी बैठे थे, उन्होंने कहा कि सुषमा जी फिर आप कम्युनिस्टों को जानती नहीं हैं। आपको लगता है कि नंदीग्राम शांत हो गया, नंदीग्राम भड़केगा और दोबारा इससे ज्यादा बुरी तरह से भड़केगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप शायद नहीं जानती हैं इसलिए कह रही हैं, आप जिन्हें प्हाजी कहती हैं, अहलुवालिया जी को, आप उनसे पूछना, वह इनका असली चरित्र जानते हैं। वह आपको बतायेंगे। लेकिन मैं सच कहती हूं कि मैंने प्हाजी से नहीं पूछा, क्योंकि मैं मन में कहीं न कहीं आश्वस्त थी कि बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में शायद नंदीग्राम में दोबारा यह नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं उनको बहुत ही ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति मानती थी। जब मैं I & B मिनिस्टर थी, तब मेरा उनसे डायरेक्ट राब्ता रहता था, मुझे पता लगा कि वह कभी भी डायरेक्ट अपने घर आफिस से उठकर सीधे नहीं जाते, पहले कोई न कोई नाटक, पहले कोई न कोई फिल्म देखकर जाते हैं, जो व्यक्ति इतनी साहित्यक रूचि का है, वह कैसे इतनी हिंसा को बर्दाश्त करेगा ! सच कहती हूं, खड़े होकर, मेरा मन आश्वस्त था, मैंने प्हाजी से भी नहीं पूछा कि क्या नंदीग्राम में दोबारा आग लगेगी। लेकिन आज कहती हूं कि मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। वह कहने वाला व्यक्ति सही था, मैं गलत थी। सात महीने बाद दोबारा नंदीग्राम में हिंसा भड़की है, बहत योजनाबद्ध तरीके से भड़की है। उपसभापति जी, मैं कहना चाहती हूं कि इस बार की हिंसा में पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इसी १३ नवम्बर, २००७ को आडवाणी जी के नेतृत्व में दोबारा एनडीए का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल नंदीग्राम गया, मैं फिर उसमें शामिल हुई। इस बार घटना का केन्द्र सोनाचूड़ा नहीं था, इस बार घटना का केन्द्र था अधिकारीपाड़ा और सतंगाबाड़ी। हम लोग अधिकारीपाड़ा गए और एक बुनियादी अंतर मुझे दिखायी दिया। जनवरी महीने में पूरा गांव सड़कों पर, मार्च महीने में हजार-पन्द्रह सौ

लोग बेखौफ बोलते हुए, लेकिन इस बार पूरा गांव दहशतज़दा। कोई घर से निकलने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसा कि स्वाभाविक है, मैंने पहला सवाल पूछा, आपका नाम क्या है, उसने कहा कि मेरा नाम मत पूछो। मैंने कहा कि क्यों, वह बोली नाम छप गया तो मार डालेंगे। केमरामैन सामने था, तो वह बोली इनको कह दो, मेरी फोटो नहीं खींचे। मुझे बोली इधर आओ, वह मुझे एक तरफ ले गयी, क्योंकि मेरे साथ बाकी पुरूष थे। वह मुझे एक तरफ ले गयी और मेरे कान में केवल फुसफुसाते हुए कहा - यहां बहुत नौजवान महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है, सिर्फ तुम्हें यह कहने के लिए आयी थी और यह कहकर वह कहां गायब हो गयी मुझे नहीं मालूम। सारा अधिकारीपाड़ा घूमते-घूमते हम लोग वापिस आए तो हमने देखा कि एक घर के आगे सात-आठ महिलाएं खड़ी थीं, मुझे लगा कि शायद वे महिलाएं बोलेंगी। मैं स्वयं उनके पास जा पहुंची। एक बूढ़ी मां खड़ी थी, मैंने उससे पूछा - कुछ तो बताओ, हम लोग इतनी दूर से आए हैं। गृह मंत्री जी, उसने मुंह खोलकर केवल इतना कहा था, क्या बताऊं तीन दिन से मेरा बेटा घर नहीं आया। इतने में उसकी बहू आयी, वह उसका हाथ खींचकर ले गयी, मत बोल, मार डालेंगे, मत बोल। यह घटना मैंने अपनी आंख से देखी है। अधिकारीपाड़ा से हम नंदीग्राम आ गये। लोगों ने कहा कि वहां जाइये, वहां एक रिफ्यूजी कैम्प है, वहां लोग बोलेंगे। हम रिफ्यूजी कैम्प में गये, आडवाणी जी की गाड़ी आगे थी, मेरी गाड़ी थोड़ी पीछे थी। आडवाणी जी मुझसे पहले पहुंच गए थे। मैंने वहां जाकर देखा कि आठ औरतें उनके पांव में गिरी हुयी थीं। वह बार-बार कह रहे थे, वे चरण पीछे हटा रहे थे, लेकिन वे पांव से उठ नहीं रहीं थीं। मैंने एक महिला को उठाया, गले लगाया, पूछा क्या बात है, एक ही शब्द सबके मुंह से था, हमारे स्वामी ला दो, हमारे स्वामी का पता लगा दो। स्वामी वहां पति को कहते हैं। अभी मुझे लोकमत टाइम्स के एक अखबार, मैं तो लेकर नहीं आयी थी, यहां विजय दर्डा जी ने भेजी है, उसमें वह फोटो छपी है, वह महिला मेरे गले लगी हुयी है, वह एक ही बात कहती है कि मेरे स्वामी का पता लगा दो।

मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतनी गंभीर बात कहूंगी, तो उसको इतनी हल्की, लाइट कहकर उसका विषयांतर कर दिया जाएगा। एक लड़का हमारे सामने था और उसने कहा सुषमा जी, मेरी मां को तो मार दिया, पिता का पता नहीं है, कम से कम मेरे पिता का पता लगा दो। इसको भी बंगाली में कुछ और कहते होंगे, लेकिन दोनों बातों का अर्थ यही था, औरतें कह रही थीं कि हमारे पति का पता लगा दो और लड़का कह रहा था कि मेरे पिता का पता लगा दो। उनको मालूम नहीं था कि उनके पिता और पति कहां गायब कर दिए गए हैं। उस रिफ्यूजी कैम्प में दो हजार से ज्यादा लोग खड़े थे कि वहां से उठना भारी हो गया। मैं आडवाणी जी से कहा कि यहां से चलिए, हम यहां खड़े रहकर इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बाकी कार्यक्रम खत्म करिए। हम सीधे राज्यपाल के पास चलते हैं, हम और कुछ करें या न करें, लेकिन हम कम से कम गवर्नर से इस बारे में कहते हैं कि इनके पिता और पति का पता लगाकर दें। हम यह कह कर वहां से चले आए। वे सतंगावाड़ी के लोग थे, वहां पर ३४० घर जला दिए गए हैं। वे घर से जुदा हुए लोग थे और वे उस सतंगावाड़ी के रिफ्यूजी कैम्प में रह रहे थे। यह वह घटना है, जो हम १३ नवम्बर का देखकर आए हैं। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहती हूं कि इस पूरी घटना की निंदा करने के बजाए, हमारे वामपंथी साथी, वैसे मैं वामपंथी कहूं तो गलत होगा क्योंकि उनके सहयोगी दल भी उनकी आलोचना कर रहे हैं, हमारे सीपीएम के साथी, इस पूरी घटना का औचित्य ठहराने में लगे हैं। वे कहते हैं कि ये तो माओवादी हिंसा के लोग हैं, हिंसक हैं और नश्शंसक हैं। उन्होंने यहां आकर डेरा डाल लिया है, कैप्चर कर लिया है, हमारे लोग तो वहां रि-कैप्चर करने के लिए गए थे। मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस सवाल में यह प्रश्न उठा है, इस बहस के दौरान मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहती हूं, जिनका जवाब मुझे सीपीएम के वक्ता से भी चाहिए और जिनका जवाब मुझे गश्ह मंत्री जी से भी चाहिए। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या वाकई वहां माओवादी हैं? उपसभापति जी, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, 'Eye for an eye should be the principle. We have paid them back in the same coin.' इसका मतलब है कि वे माओवादियों की उपस्थिति की बात करते हैं,

लेकिन उसी पश्चिम बंगाल का गश्ह सचिव कहता है, वहां कोई माओवादी नहीं है, not a single Maoist is there. मुझे एक भी माओवादी के होने की जानकारी नहीं है। मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि माओवादियों की उपस्थिति पर जो प्रश्न चिह्न लगाया गया है, उसमें सत्य क्या हो और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि माओवादियों पर आखिर सीपीएम और कांग्रेस की सोच क्या है? कॉमरेड सीताराम येचुरी, जब नेपाल में माओवादी हिंसा करते हैं, तो आप माओवादियों के वार्ताकार बनकर नेपाल पहुंचते हैं। आप कॉमरेड प्रचंड को सरकार बनाने का न्यौता देते हैं, उसमें शामिल होने वाली बात करते हैं और यहां आप पूरे का पूरा पैराग्राफ Maoist role पर लिखते हुए इस खुले पत्र में कहते हैं कि ळारखंड के रंजीतपाल ने पूरा का पूरा ऑपरेशन आर्गनाइज किया है क्यों, कॉमरेड प्रचंड के लिए सरकार, कामरेड झारखंड के विरुद्ध हथियार, ये दो-मुंही बातें कह कर किसे धोखा देना चाहते हैं? मैंने कौन सी बात गलत कही है? क्या सीताराम येचुरी जी नेपाल नहीं गए थे?

उपसभापति जी, क्या कॉमरेड सीताराम येचुरी नेपाल नहीं गए थे? क्या ये माओवादियों के प्रतिनिधि बनकर नहीं गए थे? क्या उनको सरकार में बनाने का न्यौता देने नहीं गए थे, क्या माओवादियों की तरफ से वार्ता के लिए नहीं गए थे? मेरा दूसरा सवाल कांग्रेस से है कि माओवादियों के प्रति आपकी क्या सोच है? कल यहां सवाल उठाया जा रहा था। मैं यहां कोई पुरानी बात नहीं कर रही हूं और न ही कोई पुरानी स्पीच निकाल रही हूं। उपसभापति जी, केवल २४ घंटे बीते हैं, कल यहां संयोग से एक सवाल शोभना भरतिया जी का माओवादी हिंसा को लेकर था। उनके प्रश्न का उत्तर गृह मंत्री जी दे रहे थे। उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए जब गृह मंत्री ने कहा कि वे वहां पर पुलिस लगा रहे हैं, इंटेलिजेंस के लिए पैसा दे रहे हैं और हथियार खरीदने के लिए राज्य सरकारों को पैसा दे रहे हैं, ताकि इस तरह की हिंसा समाप्त हो। तब इन्हीं की पार्टी के एक सदस्य और आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष श्री केशव राव खड़े होकर एक पूरक प्रश्न पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे, जरा मैं बता दूं। यहीं कहा है, इसी में है, सभी ने सुना है। उनके जवाब से उन्हें संतोष नहीं हो रहा था, तो वे शुरू

कैसे करते हैं 'Sir, there cannot be a more perplexing paradox than the answer given by the hon. Minister. At one stage, you people say that it is a socio-economic problem, यह केशव राव कह रहे हैं 'at another, you want the entire House to take credit and be proud of the money that you are giving to the States and kind of intelligence they are building up and the battalions they are sending in. उसके बाद वे पूछते हैं, जब चेयरमैन साहब ने कहा कि सीधे सवाल पूछो तो उन्होंने कहा, 'I would rather put it positively. Are you thinking on the lines of having a new approach to the issue?" यह मैं नहीं पूछ रही हूं कि क्या आपकी सोच बदल गई है, क्या आप नई अप्रोच लेकर आए हैं, यह आंध्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, इस सदन के सम्मानित सांसद केशव राव, कल २१ तारीख को पूछ रहे हैं। 'Andhra Pradesh has brought it down by, not by ६० per cent, but ८३ per cent. But, do not equate it with terrorism. Naxalism is not terrorism at all. It is wrong to say. It is wrong to do so. It is only the rural activists' voice against exploitation in those areas. Let it not be equated with extremism or terrorism." मैं पूछना चाहती हूं, गृह मंत्री जी, आप यहां बैठे हैं, आपको बताना होगा कि माओवादी के प्रति आपकी सोच क्या है? क्योंकि केशव राव जी ने तो यह बात यहां कही और इसी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने कल माओ- त्से-तुंग को महिमामंडित करते हुए यह कहा है कि हिंदुस्तान का हर नौजवान, चाहे वह किसी भी पोलिटिकल पार्टी का हो, उन्होंने कहा कि चाहे वह बी.जे.पी. का ही क्यों न हो, उसे माओवादी कविताएं प्रेरित करती हैं, उसे माओवादी विचारधारा प्रेरित करती है। यह आप लोग कहते हैं। सी.पी.एम. वाले कहते रहे हैं कि माओवादियों की विचारधारा तो सही प्रेरणा से प्रेरित है, उनकी कार्य शैली में फ़र्क़ हो सकता है।

सोशल-इकोनॉमिक, they say it is a socio-economic problem, कल तक यह सामाजिक-आर्थिक समस्या थी, आज जब अपने घर में सेंध लगी तो सुर बदल गया। आप कह रहे हैं कि आप

क्या करने गई थीं? जहां तक हमारा सवाल है, हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह कहा था कि पशुपति से लेकर तिरुपति तक एक रेड कॉरीडोर इस देश में बनने जा रहा है। उसे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि पशुपति में कामरेड सीताराम येचुरी माओवादियों से जाकर वार्ता करते हैं और तिरुपति में कांग्रेस वाले नक्सलियों से हाथ मिलाकर मिलते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हम पशुपति से लेकर तिरुपति तक हर जगह माओवादियों के ख़िलाफ़ हैं, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम माओवादियों की विचारधारा के विरोधी हैं, हम माओवादियों की कार्य शैली के भी विरोधी हैं। हम न माओवादी विचारधारा से आकृष्ट होते हैं, न उनकी कार्य शैली को मान्यता देते हैं।

मेरा तीसरा सवाल गृह मंत्री जी से है। गृह मंत्री जी, यदि मैं एक मिनट, केवल बहस के लिए यह मान लूं कि वहां माओवादी हैं, assume for the assumption sake, only for an academic debate मैं यह मान लूं कि वहां माओवादी हैं तो मैं देश के गृह मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या माओवादी हिंसा से निपटने का यह तरीका मान्य है? मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप माओवादियों से निपटने की कार्य योजना तैयार करते हैं। आपने बहुत बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपसे बहुत बार यह सवाल किया जाता है, कल भी सदन में यह सवाल किया गया था, जो कार्य योजना आप तैयार कर रहे हैं, क्या उसमें इस योजना पर, इस मैथड पर, इस तरीके पर केंद्र सरकार सहमति की मोहर लगाती है कि सुरक्षा तंत्र को एक तरफ करके, पुलिस प्रशासन को एक तरफ करके, हर राजनीतिक दल के काडर को यह स्वतंत्रता दी जाएगी कि वह वर्दी पहनकर हथियार पकड़कर या बिना वर्दी पहने शस्त्र लेकर माओवादियों से निपटे। क्योंकि यह तरीका पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सरे आम अपनाया जा रहा है। वे इस हिंसा का औचित्य ठहरा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या माओवादी हिंसा से निपटने का यह तरीका केंद्र सरकार मान्य करती है और क्या वह इसे अपनी कार्य योजना का हिस्सा बनाएगी? क्या बाकी राजनीतिक दलों के लोगों को भी वह इस तरह की स्वतंत्रता देगी, क्योंकि नंदीग्राम में पता नहीं माओवादी हैं या

नहीं, यह एक प्रश्न चिह्न है।

लेकिन इस देश में एक हकीकत है कि इस देश के १५० से ज्यादा जिले आज माओवादी हिंसा से ग्रस्त हैं। पशुपति से तिरुपति तक जिस रेड कॉरिडोर की बात आडवाणी जी ने की है, वह एक हकीकत बन चुकी है, वह एक जमीनी सच्चाई है। क्या इस रेड कॉरीडोर को समाप्त करने के लिए यह तरीका केन्द्र सरकार मान्य करेगी, यह मेरा आपसे अगला सवाल है?

उपसभापति जी, सच्चाई यह है कि सीपीएम का नेतृत्व अपरिपक्व हाथों में आ गया है और इसलिए इनको यह लगता है कि सीपीआई(एमएल) की हिंसक गतिविधियों के सामने ये अप्रासंगिक हो गए हैं। तभी ये जेएनयू में भी चुनाव हारते हैं। सीपीआई(एमएल) जीतती है, सीपीएम हारता है। इसी कारण से ये आज एक ऐसी जगह आकर खड़े हो गए हैं, जहाँ इन्हें अपनी नीति समझाने में मुश्किल पैदा हो रही है। ये उस रिवोलुशन के बदले किंडर गार्टन रिवोलुशनरीज़ रिवोलुशन करना चाह रहे हैं। ये भूल गए हैं कि क्रूरता क्रान्ति नहीं होती, लेकिन ये क्रूरता से क्रान्ति का बीज बोने जा रहे हैं। यही कारण है कि इन्हें अपनी बात समझाने में मुश्किल हो रही है। कॉमरेड येचुरी, मैं पूछना चाहती हूँ कि यह पत्र लिखने की नौबत क्यों आई? आपने पहले वाक्य में यह स्वीकारा है, 'क्योंकि एकतरफा रिपोर्टिंग हो रही है, किसी को हमारी बात समझ नहीं आ रही, इसलिए हम यह खुला पत्र लिख रहे हैं।' क्यों नहीं समझ में आ रही? हमें समझ में न आए, आप कह सकते हैं कि हमने तय कर लिया है कि हम आपकी बात समझेंगे नहीं, हम आपके विरोधी हैं। आपके अपने लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही? कॉमरेड अशोक मित्रा ६० साल तक आपके कॉमरेड-इन-आर्म्स रहे हैं। अशोक मित्रा लिखते हैं - 'The Party is over". अशोक मित्रा लिखते हैं - 'Nandigram exposes arrogance and ineptitude of CPI(M). महाश्वेता देवी आपका विरोध करती हैं। गौतम घोष कहते हैं कि मुझे अपने आपको वामपंथी कहते हुए शर्म महसूस होती है। रितुपर्णो घोष सड़क पर उतरते हैं। मौसमी चटर्जी अपना पुरस्कार वापस करती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके अपने रूलिंग लेफ्ट फ्रंट में से आलोचना की आवाजें उभर रही हैं - आखिर

क्यों? हम आपकी बात न समझें, यह तो समझ में आता है, क्यों नहीं आप अपनी बात अपने सहयोगियों को समझ पा रहे हैं? क्यों पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवियों को सड़क पर उतर कर एक-एक लाख लोगों का प्रदर्शन करना पड़ता है? सच्चाई यह है कि तर्क आपके साथ नहीं है, तथ्य आपके साथ नहीं है, सत्य आपके साथ नहीं है, इसीलिए आप लोगों को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं।

उपसभापति जी, ये अपनी इस पुस्तक के एंड में कहते हैं कि वहाँ अब सीआरपीएफ आ गई है, इसलिए सब कुछ ठीक हो गया है। इससे बड़ा असत्य कुछ हो सकता है! सीआरपीएफ के डीआईजी ने तो जाने के सात दिन बाद यह कहा कि मैं केवल अनवांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट मांग रहा हूँ, वहाँ का एसपी मुझे यह भी मुहैया नहीं करवा रहा। सीआरपीएफ के डीआईजी अपने आपको असहाय पा रहे हैं और आप कहते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। कल कोलकाता में क्या हुआ है? कल नंदीग्राम और तस्लीमा नसरीन, दोनों का मिक्स था वह। यहाँ सदन की कार्यवाही बाधित हुई, सदन को पहले स्थगित करना पड़ा। आप कहते हैं कि सीआरपीएफ के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। यह देखिए - 'With the CRPF moving in on 4th November, the situation has come under the control of the Administration". यह कहा। आप ही का लिखा हुआ है, यह किसी और का नहीं है। अपना पत्र निकालिए और पृष्ठ १३ पढ़िए। अंग्रेजी तो केवल आपको आती है, मुझे तो न अंग्रेजी आती है और न बांगला आती है। जसवन्त सिंह जी को शायद आपसे ज्यादा अंग्रेजी आती है। जसवन्त सिंह जी, इसका क्या अर्थ होता है कि सिच्युएशन नियंत्रण में आ गई? सर, आपको तो अंग्रेजी आती है, इसका क्या अर्थ होता है? स्थिति काबू में आ गई, इसका यही अर्थ होता है न! सर, 'Situation has come under the control of the Administration" का क्या अर्थ होता है? मुझे तो अंग्रेजी का जितना हिन्दी अनुवाद आता है, यही आता है।

सर, बताइए, इसका क्या अर्थ है। सर, वहाँ सिच्युएशन कंट्रोल में आ ही नहीं सकती। इसलिए सिच्युएशन कंट्रोल में नहीं आ सकती कि 'वही मुंसिफ, वही मुजरिम, वही जल्लाद भी हैं, अकरबाँ मेरे, करें खून

का दावा किस पर'। यही मुंसिफ हैं, यही मुजरिम हैं, यही जल्लाद हैं, तो कैसे आएगी एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में सिच्युएशन? आ ही नहीं सकती। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि कल उन्होंने कहा कि हमने ३५५ के तहत निर्देश दिए हैं। शायद ३५५ शब्द का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि उन निर्देशों की अनुपालना होगी या हो रही है?

यह आज के इंडियन एक्सप्रैस की लाइन है। आपने कल निर्देश देते हुए क्या कहा था? मैंने आपको टीवी पर बोलते हुए भी देखा था, जिस वेदना, जिस फर्मनैस और जिस दश्ढ़ता के साथ आप यह कह रहे थे कि हमने कह दिया है, हर व्यक्ति को अपना घर मिलेगा, किसी को भी वहां से इरैक्ट नहीं किया जाएगा, सबको वापस भेजा जाएगा। सर, यह इंडियन एक्सप्रैस की आज की खबर है। 'Meanwhile, largest refugee camp at Ground Zero faces closure. School headmaster, also CPM member, says inmates illegal, have to leave.'

उपसभापति जी, गृहमंत्री जी देश की संसद में, लोकसभा में खड़े हो कर यह कहते हैं, 'हमने कह दिया है, किसी को घर से उजाड़ा नहीं जाएगा' और यह रिपोर्ट कहती है कि उजड़े हुए लोगों को, जिन्हें रेफ्यूजी कैम्प में रखा गया है, वहां से सीपीएम का एक हैडमास्टर उजाड़ रहा है। वह कह रहा है तुम इल्लीगल हो, यहां से जाओ। आपके निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह पेपर सुषमा स्वराज नहीं लिखती है और न ही इसे लिखने वाला भाजपा का कोई कॉरस्पॉडैंट है। इंडियन एक्सप्रैस की साइड लीड है कि रेफ्यूजी कैम्प जो ग्राउंड ज़ीरो में बना है, वहां की सीपीएम का स्कूल हैडमास्टर यह कह रहा है कि तुम इल्लीगल आए हो, यहां से भाग जाओ। यानी फतंगाबाज़ी से उजड़े, घर जलाए, रेफ्यूजी कैम्प में रहे, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि वापस घरों में भेजो, किसी को उजाड़ो मत और यहां उजड़े हुए लोग जो रेफ्यूजी कैम्प में रह रहे हैं, उनको सीपीएम का हैडमास्टर उजाड़ कर कहता है कि घर जाओ, तुम यहां पर इल्लीगली रह रहे हो। यह है आपके निर्देशों की अनुपालना?

गृहमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूं, मैं सरकार

की मजबूरी समझ रही हूं, क्योंकि आपके जो सहयोगी दल हैं वे अपको परेशानी में डालते रहते हैं, आपको लगता है कि कहीं कुछ और कर लिया तो मुसीबत में डाले जाएंगे और सरकार चार दिन पहले चली जाएगी। मैं कहना चाहती हूं कि लोगों की जिन्दगियों के बदले अगर सरकार चली जाए तो चली जाए, लेकिन लोगों को बचाना आपका धर्म है। इसलिए, उपसभापति जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं, मेरी आपसे यही मांग है कि अब ३५५ से कुछ नहीं होगा, ३५५ के निर्देशों की धज्जियां उड़ गईं, इसलिए अब ३५६ लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए और जो वहां पर पीड़ित हैं, उनको न्याय दीजिए, मुआवज़ा दीजिए और जो वहां पर दोषी हैं, उन्हें बेलिहाज़ा दंडित कीजिए।

उपसभापति जी, मैं एक निवेदन आपसे भी करती हूं और वह यह है कि जब भी कहीं इतना बड़ा नरसंहार हुआ है तो सदन की चेयर की तरफ से प्रस्ताव ला कर हमेशा इस तरह के नरसंहार की निन्दा की गई है इसलिए एक ओर जहां सरकार से मेरी प्रार्थना है, एक आखिरी निवेदन आपसे भी करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि नन्दी ग्राम की इस हिंसा की निन्दा करते हुए एक निन्दा प्रस्ताव अथवा भर्त्सना प्रस्ताव चेयर की ओर से आना चाहिए और सर्वसम्मति से वह पारित होना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

◆◆◆